LOK SABHA DEBATES

(Part I -- Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Fifteen of the Clock

Friday, September 18, 2020 / Bhadrapada 27, 1942 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, September 18, 2020 / Bhadrapada 27, 1942 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 921-1150)	**1-230**

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. Kirit P. Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakshi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Friday, September 18, 2020 / Bhadrapada 27, 1942 (Saka)

(Please See the Supplement)

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, September 18, 2020 / Bhadrapada 27, 1942 (Saka)

C ON T E N T S	P A G E S

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	231
PAPERS LAID ON THE TABLE	231-36
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	237
STANDING COMMITTEE ON COMMERCE 154th Report	237
STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE 102nd to 105th Reports	238
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS/OBSERVATIONS IN 2ND REPORT OF STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY – LAID Shri Prakash Javadekar	239
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS/OBSERVATIONS IN 7TH AND 13TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE – LAID Shri Arjun Ram Meghwal	239
BILL INTRODUCED Taxation and other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill	240-55
STATEMENT RE: TAXATION AND OTHER LAWS (RELAXATION OF CERTAIN PROVISIONS) ORDINANCE – LAID Shrimati Nirmala Sitharaman	255

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**255-58**
Shri Sunil Kumar Soni	**255**
Shri M.K. Raghavan	**256**
Shri Hibi Eden	**256**
Shri Rajamohan Unnithan	**257**
Shri S.R. Parthiban	**257**
Shri Magunta Sreenivasulu Reddy	**258**
Shri Rahul Ramesh Shewale	**258**
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS First Batch	**259-344**
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS	
…	**260**
Shri Jayant Sinha	**261 & 267-73**
…	**262-66**
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	**274-83**
Shri Dayanidhi Maran	**284-89**
Prof. Saugata Ray	**290-94**
Shri M.V. Midhun Reddy	**295-99**
Shri Arvind Sawant	**300-03**
Shri Ramprit Mandal	**304**
Shri Bhartruhari Mahtab	**305-10**
Shri Ritesh Pandey	**311-13**
Shri Mohammae Faizal PP	**314-16**
Shri Nama Nageswara Rao	**317-19**

Shri Sunil Kumar Singh	**320-22**
Shri Gaurav Gogoi	**323-25**
Shri Jayadev Galla	**326-27**
Shri E.T. Mohammed Basheer	**328-29**
Adv. A.M. Ariff	**330-31**
Shrimati Anupriya Patel	**332-34**
@ Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil	**335**
Dr. Mohammad Jawed	**336**
Shri Nihal Chand Chauhan	**337**
Shri N.K. Premachandran	**338-39**
Shri Bhagwant Mann	**340**
Shri Shrirang Appa Barne	**341**
$ Shri D.K. Suresh	**342**
Kunwar Danish Ali	**343**
…	**344**

(FOR REST OF THE PROCEEDINGS,
PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)

xxx

@ For English Translation of the speech made by the Hon. Member Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil in Marathi, please see the Supplement (PP335A-335B)

$ For English Translation of the speech made by the Hon. Member Shri D.K. Suresh in Kannada, please see the Supplement (PP342A-342B)

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, September 18, 2020 / Bhadrapada 27, 1942 (Saka)

S U P P L E M E N T

CONTENTS PAGES

XXX XXX XXX XXX

Xxx xxx xxx xxx
Xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS 335A-35B &
First Batch 342A-42B &
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS 345-75

xxx xxx xxx xxx

Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil 335A-35B

xxx xxx xxx xxx

Shri D.K. Suresh 342A-42B

xxx xxx xxx xxx

* Dr. T. Sumathy 345-52

* Dr. Kalanidhi Veeraswamy 353-54

* Shri Saptagiri Sankar Ulaka 355-56

* Shri Om Pavan Rajenimbalkar 357-58

* Dr. Heena Vijaykumar Gavit 359-60

* Sushri S. Jothimani 361-62

---

*Laid on the Table

*Shri Jagdambika Pal	363-64
* Shri Malook Nagar	365
Shrimati Nirmala Sitharaman	366-75
Demands – Voted	375
BILL INTRODUCED	376-77
Appropriation (No.4) Bill	376
Motion for Consideration – Adopted	376
Consideration of Clauses	377
Motion to Pass	377
BILL INTRODUCED	377-78
Appropriation (No.3) Bill	377
Motion for Consideration – Adopted	378
Consideration of Clauses	378
Motion to Pass	378

*Laid on the Table

(1500/MM/RBN)

1501 बजे

लोक सभा पन्द्रह बजकर एक मिनट पर समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1501 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे स्थगन प्रस्ताव की कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यदि कोई महत्वपूर्ण विषय होगा तो माननीय सदस्य को "अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे" के समय पर बोलने का मौका देने का प्रयास करूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैण्डीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैण्डीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, डॉ. हर्ष वर्धन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 34 के अंतर्गत गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (छमाही प्रशिक्षण) संशोधन नियम, 2020 जो 29 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 419(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री श्रीपाद येसो नाईक की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन मेडिसीन्स फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसीन्स फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री आर. के. सिंह की ओर से, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक – संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2020 का संख्यांक 9) – पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पारेषण परियोजनाओं के नियोजन और क्रियान्वयन संबंधी निष्पादन लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, सुश्री देबाश्री चौधरी की ओर से, मैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 45 की उप-धारा (3) के अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 जो 9 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 165(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 7ए.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to lay on the Table a copy (Hindi and English versions) of the Notification No. 34/2020 – Customs, dated 17th September, 2020, together with an Explanatory Memorandum making certain amendments in the Notification No. 50/2017-Cus., dated 30.06.2017, so as to reduce the import duty from 30 per cent to 10 per cent on Lentils (Masur) originated in or exported from countries other than USA and to reduce the import duty from 50 per cent to 30 per cent on Lentils (Masur) originated in or exported from USA from 18.09.2020 to 31.10.2020 in both cases under Section 159 of the Customs Act, 1962.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह जो नोटिस है, वह ले होने के बाद ही होता है, आप लोगों के लिए सब हो रहा है।

महासचिव।

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha: -

> "In accordance with the provisions of Rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 16th September, 2020 agreed without any amendment to the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill, 2020, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 19th March, 2020."

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति
154वां प्रतिवेदन

महासचिव : महोदय, मैं कृषि तथा समुद्री उत्पाद, बागानी फसलें, हल्दी और कॅयर का निर्यात विषय से संबंधित वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का 154वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

----

* प्रतिवेदन, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, 26 अगस्त, 2020 को माननीय सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन की एक प्रति माननीय लोक सभा, अध्यक्ष को भी अग्रेषित की गई।

STANDING COMMITTEEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE
102nd to 105th Reports

SECRETARY-GENERAL: I beg to lay the following Reports[@] (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice: -

1. One Hundred-second Report on 'Effectiveness of Vigilance Administration in certain Revenue & Banking Institutions and Selected CPSEs'.
2. One Hundred-third Report on 'Functioning of the Virtual Courts/Courts proceeding through Video Conferencing – Interim Report'.
3. One Hundred-fourth Report on the Action Taken on One Hundredth Report of the Committee on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
4. One Hundred-fifth Report on the Action Taken on One Hundred-first Report of the Committee on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Law and Justice.

[@] The Reports were presented to hon. Chairman on 11th September, 2020 under Direction 30 (i) of Directions by the Chairman, Rajya Sabha when the House was not in session and hon. Chairman was pleased to order for the publication and circulation of those Reports under Direction 30 (ii). Reports were also forwarded to the Lok Sabha Secretariat on the same day.

(1505/SM/SK)

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS/OBSERVATIONS IN 2nd REPORT OF STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY – LAID

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting.

माननीय अध्यक्ष: श्री रामेश्वर तेली : उपस्थित नहीं।
माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री अर्जुन मेघवाल जी।

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS/OBSERVATIONS IN 7th AND 13th REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Rameswar Teli, I beg to lay the following statement regarding:-

(1) The status of implementation of the recommendations/observations contained in the 7th Report of the Standing Committee on Agriculture on 'Demands for Grants' (2019-2020) pertaining to the Ministry of Food Processing Industries.

(2) The status of implementation of the recommendations/observations contained in the 13th Report of the Standing Committee on Agriculture on 'Demands for Grants' (2020-21) pertaining to the Ministry of Food Processing Industries.

माननीय अध्यक्ष: माननीय संसदीय मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर माननीय मंत्री किसी आवश्यक कार्य में बिज़ी हैं तो आपके माध्यम से सूचना दे दें। कल भी माननीय वित्त मंत्री जी का लिस्ट ऑफ बिजनैस में बिल इंट्रोड्यूज का विषय आया था।

मैं सदन के माध्यम से आग्रह करता हूं, क्योंकि कभी भी अति आवश्यक काम हो सकता है, आपके माध्यम से सूचना दे दें ताकि हम उसे अगले दिन ले लें। यह व्यवस्था हमेशा बनी रहे।

मद संख्या 13, माननीय वित्त मंत्री जी।

TAXATION AND OTHER LAWS (RELAXATION AND AMENDMENT OF CERTAIN PROVISIONS) BILL

1506 hours

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, with your permission, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for relaxation and amendment of provisions of certain Acts and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि कतिपय अधिनियमों के उपबंधों पर और छूट देने और उनका संशोधन करने वाले तथा उससे संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापति करने की अनुमति दी जाए।"

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I wish to oppose the introduction of this Bill under Rule 72 of the Rules of Procedure and Conduct of Business on the following four grounds:-

1. Clause 7 of the Bill seeks to amend the central Goods and Services Act of 2017, which would allow the Government to extend the time limit for completion of actions under the Act in events of force majeure, such as epidemic, with retrospective effect. This would permit the Government to retrospectively validate its failure and extend the time-limit indefinitely while disbursing compensation to States. That is an unconstitutional violation with the Government undertakings in the name of 'Act of God'.

2. The Bill brings the PM-CARES Fund within the ambit of the same Clause that now governs the PM's National Relief Fund. If the Government seeks to draw equivalence between the two, then why has the need to institute a new fund arisen? This raises serious questions regarding the intention behind creating a duplicate fund, which has also been exempted from C&AG's audit and for which no reasons have been provided under this Bill.

3. While the Bill seeks to provide the same tax exemptions to the PM-CARES Fund and the PM's National Relief Fund, it draws an arbitrary distinction between the two, as donations of the PM-CARES Fund count towards a company's mandatory CSR contributions, but do not count in case of PM's

National Relief Fund. This creates a double benefit of tax exemption for companies' donation to the PM-CARES Fund.

A high-level Committee constituted by the Ministry of Corporate Affairs in 2015 criticised this practice stating that donations to Central Government funds should not be allowed as a CSR contribution since they have already been exempted under the Income Tax.

(1510/AK/SKS)

A second High-level Committee, in its 2019 Report, agreed to this. Therefore, this Bill goes against the spirit of the CSR provision as the companies could be in compliance through a mere donation with no real application towards the betterment of the society.

Finally, the fourth objection is that the Bill continues to extend the benefits provided to tax evaders under the Direct Tax Vivad-se-Vishvas Act…(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री ए. एम. आरिफ जी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब बिल पर डिटेल में चर्चा होगी, तब आप कहिएगा।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): No, Sir. I am not speaking on the main Bill. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों बिल का विरोध कर रहे हैं? आप इसका तर्क दीजिए।

…(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, it promotes arbitrariness and resorts to unreasonable classification. Hence, it is not within the appropriate state to be introduced. It promotes arbitrariness and resorts to unreasonable classification by treating equal entities unequally. Therefore, the Minister should really look into these shortcomings before introducing the Bill.

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, I rise to oppose the introduction of the Bill on the following grounds. The Bill is being introduced at a time when the country is united in its fight against the COVID pandemic. This Bill is part of an attempt by the Central Government to reduce powers of the States. This Bill, with the new amendment, gives income tax deduction to those who contribute to PM CARES Fund and tax deduction not to those who pay in CMDRF …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मिस्टर आरिफ, आपने यह सवाल उठाया है कि यह बिल योग्यता से बाहर है। आप उस विषय पर बोलिए। Okay.

…(व्यवधान)

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, kindly give me only one more minute to conclude. This Bill, with the new amendment, gives income tax deduction to those who contribute to PM CARES Fund and tax deduction not to those who pay in CMDRF with a political objective of reducing the powers of the States.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, with your kind permission, I do oppose the introduction of the Bill under Rule 72 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

Under Article 266 (2) of the Constitution, public moneys received by or on behalf of the Government of India, which is not on account of revenue from taxes, duties, repayment of loans and the like, should be credited to the public account of India. The salient features of the Bill are very much in conflict with this Article of our Constitution.

Secondly, when an amendment is suggested, it should have a purpose, but this is simply adding PM CARES without any particular statement. Thirdly, why should you bring an amendment in the Act if this is not a public authority? The Government has to make it clear as to who benefits from this action. Fourthly, the Prime Minister, Minister of Defence, Minister of Home Affairs and Minister of Finance are part of the Government of India, which again makes it a public authority. The Government is not giving answer to RTI queries on ground of not being a public authority, and the Government is finding reasons to hide data from public. This is a question of accountability. Hence, I am opposing the introduction of this Bill.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, under Rule 72 (1) of the Rules of Procedure, I beg to oppose the introduction of the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020.

Other Members have pointed out their objections to various provisions of the Bill. I point out mainly to Section 4 where a particular fund known as the …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, देखिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। आप पहले नियम 72 को पढ़ लीजिए, ठीक है।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदय, मैंने पढ़ लिया है।

माननीय अध्यक्ष : मैं पढ़ लेता हूं, ताकि माननीय सदस्यों को यह ध्यान रहे कि नियम 72 क्या है?

प्रो. सौगत राय (दमदम) : आप मेरे पढ़ने के बाद पढ़िए।

माननीय अध्यक्ष : मैं पढ़ता हूं।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : आप पहले पढ़ेंगे। मैं भी पढ़ सकता हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह अधिकार मेरे पास है, इसलिए मैं ही पढूंगा। ठीक है। यह सबको ध्यान रहे कि नियम 72 क्या है? क्यों अधीर रंजन जी, इसका ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो आप सदन को कह देंगे कि नियम 72 हमारा अधिकार है। यह आपका अधिकार है, लेकिन अध्यक्ष की परमिशन से। ठीक है न।

"यदि किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए, तो अगर अध्यक्ष ठीक समझे तो प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की अनुज्ञा देने के बाद अग्रसर वाद-विवाद के प्रश्न को रखा जा सकेगा।"

इसकी सेकेंड लाइन यह है, "परंतु जब इस आधार पर विरोध किया जाए कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है, जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष के द्वारा उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दी जा सकेगी।"

(1515/SJN/SPR)

तीसरा, "परंतु यह भी अध्यक्ष द्वारा वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव तुरंत मतदान के लिए रखा जाएगा।"

क्या मैं आगे और पढ़ दूं? दादा, अब आप बोलिए।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदय, अच्छा हुआ कि आपने कानून के बारे में बता दिया है। इसके बाद जब भी कोई सदस्य किसी बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध करेगा, तब उनको यह पता चलेगा कि कैसे इसकी अनुमति मिलती है और कैसे अध्यक्ष पर सब कुछ निर्भर करता है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अध्यक्ष का यह भी दायित्व है कि वह सभी माननीय सदस्यों का संरक्षण करें।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदय, हम सभी का यह फर्ज़ है कि आपके पद की महिमा को बनाए रखें। आपको जो यह पावर है, आप उसका ठीक से इस्तेमाल करेंगे, यही मेरा इरादा है, मेरी आशा है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदय, मुझे बोलने दिया जाए।…(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : महोदय, मैं यही दादा से पूछ रहा हूं।…(व्यवधान) आपने तो दादा को बोलने दिया है, आप तो उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।…(व्यवधान) उनको बोलने का मौका दिया है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम सभी का एक ही मत है कि सदन में चाहे सत्ता पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, सदन में सभी की सहमति चले और सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मिले, लेकिन सही दिशा की तरफ।

…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, let me start from the beginning. Under Rule 72(1) of the Rules of Procedures, with your permission, I beg to oppose the introduction of the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020. Some relaxations have been made in the taxation proposals; some extra time has been given in view of the pandemic. I am not objecting to that. My objection is to Section 4 of the Bill where references are made, "after the "Fund", the words and brackets "or the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES FUND)" shall be inserted. This is a totally new concept of money gathering, subscription gathering by the Prime Minister's Office. The PM already has a National Relief Fund and he also has the Prime Minister's National Relief Fund for Cancer Treatment. Now, what is the need of this PM CARES Fund? As has been pointed out, there will be no audit by the Comptroller & Auditor General of India into the affairs of the Fund.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस विषय को माननीय शशि थरूर जी ने रख दिया है। उसका रिपीटेशन करने की आवश्यकता नहीं है।

…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): That is why, I propose that this PM CARES Fund must be abolished and all the money, huge sums of money, that has gathered in it, be transferred to the Prime Minister's National Relief Fund. Whoever wants to be benefited from the Prime Minister's National Relief Fund, let them apply to the Prime Minister's National Relief Fund, and not to the newly formed entity called the PM CARES Fund. That is why, I oppose the Bill, which includes this `PM CARES FUND'.

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष तिवारी जी।

माननीय सदस्य, कोई विशेष विषय हो, तो ही रखिएगा।

…(व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Mr. Speaker, Sir, with your kind permission, I metaphorically rise to oppose the introduction of the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions Act, 2020 on four grounds.

The Bill which is sought to be introduced is not procedural in nature. It makes substantive amendments to eight different Acts, some of which are required to be or should have to be standalone amendments because they end up changing the character of the principal Act itself. By way of example, let me demonstrate. If you look at Clause 4, Sub-Clause 18, of the proposed Bill which is sought to be introduced, it gives faceless jurisdiction to Income-Tax authorities. On the face of it, Mr. Speaker, Sir, this looks to be a benign and an assessee-friendly amendment, but it is riddled with minefields and would fundamentally alter the character of the Income-Tax Act, 1961.

(1520/UB/GG)

So, therefore, it needed to be brought as a standalone amendment to the Income Tax Act rather than being snuggled in into a law which seeks to really project itself as being procedural.

My second objection, Mr. Speaker, Sir, is with regard to the PMCARES Fund and the objection is different from the ones which have been raised by my hon. colleagues. Since the name of the institution of the Prime Minister is attached to it, would it not have been more appropriate if this Fund were created through legislation rather than as a public trust?

My final objection is to clause 7 that inserts clause 168(a), specifically clause 168(a), sub-clauses 1 and 2 that allow force majeure to be operationalised retrospectively. In fact, this is a very convenient way that the Government has found in order to wriggle out of its obligation to pay GST compensation to the States which is long overdue.

So, therefore, Mr. Speaker, Sir, on these three substantive grounds, with your permission, I oppose the introduction of this Bill.

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ विषय रखना चाहेंगी?

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, अगर आप अनुमति दें तो I can give some explanation.

माननीय अध्यक्ष: अनुमति है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, मेरा पहला जवाब है, I have a feeling that there is definitely a misunderstanding. यह फोर्स मेजर क्लॉज़ का उपयोग करते हुए हम किसी राज्य के अधिकार को छीन नहीं रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी को निभाने से दूर नहीं हो रहे हैं। Nor are we running away from our responsibility. इसीलिए इधर फोर्स मेजर लगा कर, in retrospect, राज्यों को जो देना है, उससे आप भाग रहे हैं, यह आर्ग्यूमेंट एकदम गलत है। राज्यों को जो पैसा देना है, हम उसको नहीं देंगे, हमने ऐसा बयान कहीं नहीं दिया और हमारा ऑब्जेक्ट भी वह नहीं है। इसीलिए वह आर्ग्यूमेंट इधर डाल कर, राज्यों को जो देना है, वह आप नहीं देंगे, ऐसे आरोप लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रधान मंत्री सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको मालूम है कि राज्य सरकारों की दिक्कत क्या है। राज्यों को समय पर पैसा मिलना कितना आवश्यक है, हमें बार-बार प्रधान मंत्री जी से एडवाइज़ भी मिलती है। इसीलिए इसको डिस्टॉर्ट, क्षमा कीजिए, मैं डिस्टॉर्ट का शब्द उपयोग कर रही हूँ, मगर मैं एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, डिस्टॉर्ट कर रही हूँ, मगर इसका ऐसे इंटरप्रेट करना आवश्यक नहीं है, हम किसी राज्य के अधिकार को छीन नहीं रहे हैं और उनका पैसा जो देना है, वह बिल्कुल देंगे। So, this is about 'Force Majeure' and also, माननीय शशि थरूर जी बोलते हैं – Section 168A of the CGST Act, आपको सिर्फ यह प्रोवाइड करता है कि That on the recommendation of the GST Council आप कर सकते हो, मगर सरकार खुद कुछ नहीं कर सकती है, जीएसटी काउंसिल की रिक्मेंडेशन है। सर, हम बिल्कुल इसको मानते हैं। हम इमसें ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसको आप कहें कि जीएसटी काउंसिल का हम वॉयलेट कर रहे हैं, बायपास कर रहे हैं। However, GST Council और सीजीएसटी एक्ट के द्वारा इस बिल में जो हम कर रहे हैं, टैक्स पेमेंट, टैक्स फाइलिंग और टैक्स रिटर्न्स के ऊपर ही हमारे जो भी अमेंडमेंट्स हैं, उसके इंटेंशंस हैं। इसीलिए टैक्स पेमेंट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स वगैरह बिल्कुल केन्द्र सरकार की परिधि में है। It is within the limits of the Central Government's terrain. So, it is relevant to know that tax payment, tax filing and filing of returns etc. were excluded from the purview of the relevant notifications issued in the exercise of powers under this Section.

(1525/KN/KMR)

इसलिए कंफ्यूज रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं पीएम केयर्स के ऊपर जाने से पहले विवाद से विश्वास के ऊपर ऑब्जेक्शन, ऑब्जर्वेशन हुआ। विवाद से विश्वास एमनेस्टी स्कीम नहीं है। उसको बार-बार उस नजरिये से देखना सही नहीं है। Vivad se Vishwas Scheme does not extend any benefit to dishonest tax evaders. इसलिए वह एमनेस्टी की स्कीम नहीं है। यह डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन स्कीम है। लिटिगेशन बहुत सालों से पड़ा हुआ है, उसको सुलझाने का कुछ तरीका नहीं है, है तो उसमें समय लगता है। इसलिए डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन के लिए हम विवाद से विश्वास स्कीम ले आए। इसके द्वारा लिटिगेशन कम करने के लिए रास्ता हम ढूंढ रहे हैं, इसलिए इसको एमनेस्टी के रास्ते पर चलते हुए इसमें ऑब्जेक्शन रेज करना नेसेसरी नहीं है।

सर, पीएम केयर्स रिलेटेड इश्यू में मैं एमओएस अनुराग ठाकुर जी को बोलती हूँ कि वह जरा एक्सप्लेन करें, अगर आपकी अनुमति हो।

माननीय अध्यक्ष : आपने तो पहले ही उनको डायरेक्शन दे दी। आपने अनुमति बाद में मांगी है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : क्षमा कीजिए। मैंने सोचा कि मिनिस्ट्री का जवाब देना है, मैं एमओएस को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ।

माननीय अध्यक्ष : वह जवाब दे सकते हैं, उसमें अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : थैंक यू सर। मैं आपसे अनुमति मांग रही हूँ।

माननीय अध्यक्ष : अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं है, वह जवाब दे सकते हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): अध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ विपक्ष के साथियों ने पीएम केयर्स पर प्रश्न उठाने का प्रयास किया है। यह अभी नहीं, इससे पहले भी जब से इसकी स्थापना हुई है, उस दिन से लेकर आज तक इसका विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन विरोध के पीछे तर्क तो हो, केवल कहने के लिए विरोध करना, जैसे यह ईवीएम खराब है, चुनाव के समय विरोध करते थे, लेकिन एक बार नहीं, कई बार चुनाव हारे। फिर कहा- जनधन खराब है। फिर कहा- डिमोनेटाइजेशन खराब है। फिर कहा- ट्रिपल तलाक खराब है।…(व्यवधान) फिर कहा- जीएसटी खराब है। फिर कहा- तीन तलाक खराब है। आपको तो हर चीज में खराबी नजर आती है। सच्चाई यह है कि आपकी नीयत खराब है।…(व्यवधान) नीयत और सोच खराब होने के कारण आप एक अच्छे कदम को भी खराब नजरिये से देख रहे हैं।…(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, पीएम केयर्स खराब क्यों है, क्या गलती है? एक नहीं, कई बार आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, कई विषयों को लेकर, लेकिन अंत में उसका नतीजा क्या निकला? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हर कदम पर, हर कोर्ट ने पीएम केयर्स के पक्ष में अपना निर्णय दिया, इनके हित में नहीं दिया है। आखिर इन्होंने क्या-क्या चुनौतियाँ दीं, इन्होंने तो इसको सेट-अप करने के लिए कि आपने बनाया ही गलत है, आपने उसको चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया।…(व्यवधान) संवैधानिक रूप से उसको वैध बताया गया।

सर, यही नहीं, ये अप्रैल महीने में चले गए थे। मार्च में बना और अप्रैल महीने में उसके विरोध में चले गए। देश कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, प्रधान मंत्री जी कदम उठा रहे थे, लेकिन ये उस समय भी राजनीति कर रहे थे, ये लोग विपक्ष का काम कर रहे थे।…(व्यवधान) सर, जून, 2020 में इन्होंने कहा कि इसको आरटीआई के अंतर्गत देना चाहिए, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि सारे पैसे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर करने चाहिए। कोर्ट ने उसमें डिटेल्ड जजमेंट दी है कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में राज्य और केन्द्र का पैसा जाता है और इसमें पीएम केयर्स फंड में कंसोलिडेटेड फंड का कोई पैसा नहीं जाता, कोई बजटरी सपोर्ट नहीं जाती। स्वैच्छिक निधि से जो लोग, जनता पैसा देती है, वह पैसा इसमें आता है। केन्द्र सरकार का कोई पैसा इसमें नहीं गया है।

(1530/CS/SNT)

हम सांसदों ने पैसा दिया होगा, गरीब से गरीब व्यक्ति ने पैसा दिया।

सर, मुझे दु:ख इस बात का होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति ने तो इसमें अपना योगदान दिया, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि उनकी अच्छी सोच पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये केवल नरेन्द्र मोदी जी की सोच पर या प्रधान मंत्री जी की सोच पर प्रश्न खड़ा नहीं करते, ये हिन्दुस्तान की 138 करोड़ जनता की सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। किन-किन लोगों ने योगदान दिया, मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ।

सर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की 9 साल की अनुष्का और 6 साल के युवराज ने अपनी गुल्लक तोड़कर 700 रुपये में से 300 रुपये का इसके लिए योगदान दिया है। बच्चों ने पैसा दिया है। अगला, कानपुर के किदवई नगर में बच्चों ने मजदूरों के लिए गुल्लक तोड़कर 5,855 रुपये पीएम केयर्स फंड के लिए दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की 10 साल की बेटी सुहानी ने 4,091 रुपये पीएम केयर्स फंड के लिए दिए हैं। बीड की रहने वाली एक रिटायर टीचर ने 5 लाख रुपये पीएम केयर्स फंड में दिए हैं।…(व्यवधान)

सर, अगर योगदान देने वालों के लिए भी, जिन बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर पैसा दिया, उनका नाम सुनने के लिए भी ये राजी नहीं हैं तो इस सोच के ऊपर… *(Not recorded)* आनी चाहिए।…(व्यवधान) उत्तराखंड की अगस्तमुनि 80 साल की वीरांगना दर्शनी देवी जी 10 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक आयीं और अपने जीवन भर की पेंशन 2 लाख रुपये पीएम केयर्स फंड में दे दी। दिल्ली के जय प्रकाश नगर के 82 वर्ष के महेन्द्र सिंह ने एक लाख रुपया पीएम केयर्स फंड के लिए दे दिया। उत्तराखंड के गोचर की 60 साल की देवकी भंडारी ने 10 लाख रुपये पीएम केयर्स फंड में दिए।…(व्यवधान)

सर, नेता हो, अभिनेता हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, सांसद हो या विधायक हो, हर किसी ने अपनी तरफ से देने का प्रयास है, क्योंकि यह लड़ाई देश की लड़ाई थी और इस लड़ाई में प्रधान मंत्री मोदी जी ने पीएम केयर्स फंड की स्थापना करने का काम किया।…(व्यवधान)

सर, अभी इसमें मुझे बहुत कुछ कहना है।…(व्यवधान) इनका असली चेहरा तो दिखाना बाकी है।…(व्यवधान) सर, इसमें कम से कम आधे घंटे का समय तो चाहिए होगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आप बिल की फुल डिबेट के समय बोलिएगा।

…(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, इनका उत्तर तो देना पड़ेगा। सर, आप यह कह दीजिए कि या तो अभी मुझे विस्तार से अपनी बात रखने का मौका दीजिए या फिर चर्चा के समय मुझे अपनी पूरी बात रखने का अवसर मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष : चर्चा के समय आपको पूरा मौका मिलेगा।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, मैं एक बात जरुर कहना चाहता हूँ कि जब ये चर्चा करने आएं, मेरा विपक्ष के लोगों से अनुरोध रहेगा कि कृपया करके प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड को पढ़कर आएं।…(व्यवधान) 1948 में शाही हुक्म की तरह उस समय के प्रधान मंत्री नेहरु जी ने कह दिया कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड बना दो।…(व्यवधान) 1948 से लेकर आज तक उसकी रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाई।…(व्यवधान) सर, 1948 से आज तक उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई।…(व्यवधान)

कैसे उसको एफसीआरए क्लियरेंस मिली, कैसे उसको 12(ए) की रजिस्ट्रेशन बगैर ट्रस्ट के मिली?…(व्यवधान) सर, ट्रस्ट रजिस्टर नहीं है, ट्रस्ट डीड नहीं है।…(व्यवधान) आपने सैक्शन 12(ए) में उसे कैसे रजिस्टर किया? आपने उसको एटीजी की एग्जम्प्शन कैसे दी? एफसीआरए की क्लियरेंस आपने उसको कैसे दी? …(व्यवधान) यह मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ।…(व्यवधान) हमारे यहाँ पर पीएम केयर्स संवैधानिक रूप से एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है।…(व्यवधान) मैं विपक्ष को खुली चुनौती देता हूँ कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर लें, यह संवैधानिक रुप से पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है।…(व्यवधान) यह हिन्दुस्तान की 138 करोड़ जनता के लिए है।…(व्यवधान) …(अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)…(व्यवधान) प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड में… (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ये लोग उसके सदस्य रहे।…(व्यवधान) इसकी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।…(व्यवधान) दूध का दूध और पानी का पानी हो।…(व्यवधान) इसके ऊपर देश को आपका असली चेहरा नजर आना चाहिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि कतिपय अधिनियमों के उपबंधों पर और छूट देने और उनका संशोधन करने वाले तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुर:स्थापित कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, ये नाम हटाए जाएं।…(व्यवधान) यह क्या हो रहा है? …(व्यवधान) यह ठीक नहीं है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम देख लेंगे।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आप बताइए कि क्या यह इंट्रोडक्शन की चर्चा है? …(व्यवधान) हम लोगों ने कुछ नहीं कहा है।…(व्यवधान)

(1535/RV/GM)

सर, … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) …(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सर, मैं कहता हूं कि … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) का पूरा नाम लेना चाहिए।…(व्यवधान)

सर, मैं अधीर रंजन चौधरी जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं।…(व्यवधान) इस पर पूरे … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) का नाम लेना चाहिए क्योंकि आज तक देश की जनता को गुमराह करके, अलग-अलग चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसे लेकर आपने व्यक्तिगत लाभ उठाने का काम किया है। उसको हम पर्दाफाश करके छोड़ेंगे।…(व्यवधान) ये … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ने देश के साथ खिलवाड़ किया है।…(व्यवधान) इसका 'दूध का दूध, पानी का पानी' करेंगे।…(व्यवधान) आपका एक-एक चिट्ठा यहां पर निकाला जाएगा।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं? ऐसे नहीं चलेगा।…(व्यवधान)

1536 बजे

(इस समय श्री अधीर रंजन चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य
सभा से बाहर चले गए।)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

…(व्यवधान)

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): सर, अगर आपकी अनुमति हो तो बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं एक शब्द बोलना चाहूंगी।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कल्याण जी, बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अनुराग जी, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कल्याण जी, बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज, बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हों, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से कहता हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सदस्य, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों, प्रतिपक्ष के हों, चाहे माननीय मंत्रीगण हों, कोई भी माननीय सदस्य अगर उठकर बोलने का प्रयास करेंगे तो मैं उनका नाम लेकर सदन से बाहर निकालने की कार्रवाई करूंगा।

(1540/MY/RK)

मेरे लिए सबसे पहले सभी माननीय सदस्यों की सुरक्षा आवश्यक है और ये सारे इंतजाम भी, जो आप विशेष परिस्थितियों के अंदर कठिनाई उठाकर यहाँ पर बैठे हैं। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत परेशानी है, लेकिन सबकी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं। शीट लगाई गई है, ताकि माननीय सदस्य बैठकर बोलें। अगर हम मास्क खोलकर बोलने लगेंगे तो इसे सारा देश देखेगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: दादा, एक मिनट रुकिए। मैं सभी को मौका दूँगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको बोलने के लिए मौका दूँगा।।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हम सब को पूरा देश अनुसरण करता है। अगर अनुसरण करते हैं तो सारा देश भी हमको देख रहा है। सारे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है। हम सब को इस देश को सुरक्षित रखना है, इसलिए हम सब माननीय हैं। हम सब अपने-अपने क्षेत्र के 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी बात का मैं हमेशा आदर करता हूँ। मैं आपको पर्याप्त अवसर भी देता हूँ। कोई भी माननीय सदस्य हो, चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हो, चाहे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हो।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप मास्क लगाकर बोलिए।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): सुनिए साहब, जब से हाउस स्टार्ट हुआ है, हम लोग चुपचाप बैठकर आपकी बात सुन रहे हैं।…(व्यवधान) लेकिन, बीजेपी का कोई मेम्बर हम लोगों के लिए बोलेगा, आप उन लोगों के लिए कुछ नहीं बोलेंगे…(व्यवधान) जब हम लोग कुछ बोलेंगे तो आप हमें बोलेंगे, यह नहीं चलेगा।…(व्यवधान) इसे हम चलने नहीं देंगे,…(व्यवधान) लोग क्या सोचते हैं? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, आप अपनी बात कहें और संयम में बोला करें।

…(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): साहब, आप सुनिए। …(व्यवधान) आप हमारा नाम लेकर सस्पेंड कर दीजिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) यह नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसे हम चलने नहीं देंगे, लोग क्या सोचते हैं?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, शांति बनाए रखें। मैंने उन माननीय सदस्यों को भी कहा, जो खड़े हुए थे। मैंने माननीय मंत्री जी को भी कहा। मैंने किसी सदस्य को अलग-अलग भाषा में नहीं कहा।

जो भी माननीय सदस्य खड़े हैं, चाहे इधर से खड़े हो, चाहे उधर से खड़े हो, चाहे सदस्य हो, चाहे माननीय मंत्री हो, मैंने सबको कहा।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आज बिजनेस कैसे शुरू हुआ, टैक्सेशन बिल पर इंट्रोडक्शन के लिए शुरू हुआ। कानून के मुताबिक हम लोगों ने अपोज़ किया। आपने हमें बोलने के लिए इजाजत दी।

सर, हमारी बात को रिकॉर्ड से निकाल कर देखिए। एक भी ऐसी बात नहीं हुई, जो अनकंस्टिट्यूशनल है या अनपार्लियामेन्ट्री है, आप एक लफ्ज़ दिखा दीजिए। मैडम निर्मला सीतारमण जी बड़े अच्छे ढंग से जवाब दे रही थीं और हम सब भी उनकी सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वह बहुत अच्छी लेडी हैं और हम सब उनका सम्मान भी करते हैं।

सर, इसी बीच में वह हिमाचल का … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) कहाँ से आ गया। … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) बीच में कहाँ से आ गया और आकर सारे बाजार को खराब कर दिया।…(व्यवधान) इन्होंने आकर सारे बाजार को खराब कर दिया।

सर, इस चर्चा में …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) कहाँ से आ गए, इस चर्चा में …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)को लाने की क्या जरुरत थी? आप हमें बताइए। हम लोगों ने कभी कहा कि पी.एम. केयर्स फंड में नरेन्द्र मोदी … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) करते हैं, चीन के फंड से पैसा लेते हैं, वसूली करते हैं। हमने कभी पी.एम. नरेन्द्र मोदी जी का एक लफ्ज़ उच्चारण किया है, नहीं किया है। उन्होंने …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) जी का नाम कैसे ले लिया? नेहरू जी जब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम का जिक्र करके किसका अपमान करना चाहते हैं?

सर, ये लोग आपके चेयर की गरिमा को नष्ट करना चाहते हैं। आपके चेयर की गरिमा को बचाना हम सब का फर्ज है। यहाँ राजनाथ सिंह जी भी है। राजनाथ सिंह जी आप कहिए, क्या हम लोगों ने कोई गलती की। ये आपके तीन दिन के … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ने गलती की, यह आप बताइए।…(व्यवधान)

(1545/CP/PS)

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठकर बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठकर बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): आप हमको निकाल दीजिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठकर बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठकर बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सदस्यगण।

…(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट क्या?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक मिनट।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, प्लीज बैठिए। क्या हो गया है यह?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं ऐसा नहीं है।

…(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): बाहर कर दीजिए हमको।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज।

…(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक सेकंड रुक जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज अब डिबेट न करें। बहुत हो गया।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बहुत डिबेट हो गई।

…(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, पहले दिन से हम आपका समर्थन कर रहे हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अनपार्लियामेंट्री, अपमाननीय शब्द के लिए हम यहां नहीं आए हैं। मंत्री महोदय क्षमा मांगे। जिस प्रकार से बोला …(व्यवधान) क्षमा मांगे। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप चुपचाप बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए।

…(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): …(व्यवधान) आपको सुनना होगा। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठकर बोलें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर आसन के कहने के बाद भी आप इस तरीके से व्यक्तिगत रूप से इस तरह चलाएंगे, तो सदन आपके कंट्रोल में चलने वाला नहीं है। मैं इस तरीके से न सदन चलाने का आदी हूं और न सदन चलाऊंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं है। मैं आप सभी को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर देता हूं। न मैं इधर की आंखों में अंतर समझता हूं और न उधर की आंखों में अंतर समझता हूं। कोई माननीय सदस्य कभी आसन से नहीं कह सकता कि मैंने केवल एक तरफ के पक्ष या दूसरी तरफ के पक्ष को बैठने के लिए कहा हो।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट।

…(व्यवधान)

श्री मोहन एस. देलकर (दादरा और नागर हवेली): अध्यक्ष महोदय, आपने सभी को बराबर मौका दिया है। हम आपके सपोर्ट में हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे किसी के कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सदन सुरक्षा की दृष्टि से चले और व्यक्तिश: रूप से भी आपसे मैंने कई बार चर्चा की है। सारे व्यापक इंतजाम के लिए भी हमने एक बार, दो बार डिटेल चर्चा की है। मैं चाहूंगा कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस आचार संहिता को बनाए रखें तो उचित होगा। अगर आप इस तरीके की आचार संहिता को तोड़ना चाहते हैं तो हम बैठकर चर्चा कर लेते हैं। मैं आपसे अभी बैठकर चर्चा कर लूंगा।

मैं सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

1550 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोलह बजकर बीस मिनट तक
के लिए स्थगित हुई।

(1620/NK/RC)

1620 बजे

लोक सभा सोलह बजकर बीस मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

1620 बजे (श्रीमती रमा देवी पीठासीन हुईं)

कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का संशोधन और छूट) विधेयक – जारी

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): माननीय वित्त मंत्री जी, विधेयक को पुर:स्थापित कीजिए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, I rise to introduce the Bill.

STATEMENT RE: TAXATION AND OTHER LAWS (RELAXATION OF CERTAIN PROVISIONS) ORDINANCE – LAID

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-14, माननीय वित्त मंत्री जी।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I rise to lay on the Table an explanatory Statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Taxation and other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 (No.2 of 2020).

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले बीस मिनट के अंदर सभा पटल पर रख दें।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपनी सीट पर जाइए, अपनी सीट पर बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

Re: Need to develop the operation theatre of Leprosy Research Institute, Raipur, Chhattisgarh

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): रायपुर स्थित कुष्ठ अनुसंधान केन्द्र में न केवल छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्य जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश के अलावा भी अन्य राज्यों से कुष्ठ रोगी अपने इलाज हेतु आते हैं। उक्त अनुसंधान केन्द्र मध्य भारत का वृहद कुष्ठ अनुसंधान केन्द्र है। वर्तमान में उक्त केन्द्र के आपरेशन थियेटर को विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

उक्त कुष्ठ अनुसंधान केन्द्र लगभग 12 एकड़ जमीन के क्षेत्रफल में स्थित है। यदि अनुसंधान केन्द्र के क्षेत्रफल का उचित उपयोग किया जाए तो अनेक सुविधाएं विकसित की जा सकती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त विषयों पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(इति)

Re: Shelving of the Nirdesh project at Chaliyam

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Nirdesh began its operation in 2010 at Chaliyam, part of my parliamentary constituency. Conceived as a national centre of excellence to achieve self-reliance in strategic area of warship building, today it is in a very pathetic condition.

Nirdesh requires Cabinet approval and also funds to start in full steam besides the co-operation of the defence shipyards. The shelving of the project is not in the interest of the nation.

This is the first of its kind in the country and a need of the country and will help the defence and other shipping community and also save immensely in foreign exchange.

I urge upon the Defence Minister and the Hon'ble Prime Minister for Cabinet Clearance and required fund. Otherwise the requirement of self-reliance in the shipping sector will be a set back to the nation.

This will generate employment in the region.

(ends)

Re: Draft Environment, Impact Assessment 2020 Notification

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): The EIA 2020 draft notification has brought shame to India's long standing Environment Protection face among the international community and invited widespread opposition from public. It is against the very fundamentals of Environment Impact Assessment as envisaged by the Stockholm Convention. Ex post facto clearance is alien to environmental jurisprudence and once held as unconstitutional by Supreme Court. Through clause 22, new draft provides a re-entry for the same. Exclusion of a large number of activities from current EIA regime is clear dilution of the constitutional mandate. Public participation is the strength of EIA process, which is seen reduced in the new draft. After 2009, Ministry has appointed 11 Expert Committees and sought its recommendations for strengthening and betterment of EIA Process. New draft is just opposite to most of the recommendations. The stand taken by the Government is strongly condemnable and EIA has to be withdrawn.

(ends)

Re: Establishment of AIIMS in Kasaragod District, Kerala

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): The public health care system in Kasaragod district is poor in terms of infrastructure, health personnel, and quality of health care services in comparison to the corresponding state indices. COVID 19 pandemic has further aggravated the health system of Kasaragod. There is no multi- speciality hospital in Kasaragod either in the public or private sector.

The AIIMS was established in 1956 through an Act of Parliament and operates autonomously under the Ministry of Health and Family Welfare. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana launched in 2006, envisaged more AIIMS across the country. Out of the AIIMS subsequently set up, only three were allotted to South India. Unfortunately, Kerala has been left out of the list.

Kasaragod is languishing from the disastrous effects of Endosulfan pesticide tragedy. The Supreme Court had directed to set up a speciality hospital for the victims. Hence, AIIMS should be set up in Kasaragod district immediately under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana.

(ends)

Re: Allocation of funds for Establishment of 'Tamil Nadu Defence Industrial Corridor'

SHRI S.R. PARTHIBAN (SALEM): The Central Government has already announced the Tamil Nadu Defence Industrial Corridor' project. The cities Salem, Chennai, Coimbatore, Hosur and Trichy will get benefit from this project.

Tamil Nadu is a major defence manufacturing state in the country. It is famous for automobile components. It is a much stronger manufacturing state and has a strong IT presence. There is also a large base of engineering colleges in the private sector, so there are huge talented people available here.

Salem and Coimbatore are the major area for development of precision machinery and is a base of about 4 thousand manufacturing companies. Huge unused land is available in the Salem Steel Plant to establish new industries.

I request the Central Government to allocate necessary funds and implement the "Tamil Nadu Defence Industrial Corridor" project immediately. This will help to create new employment for my constituency people.

(ends)

Re: Sanction of One Kendriya Vidalaya at Kanigiri, one Novodaya Vidyalaya at Darsi and Sainik School at Cumbum

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): My Parliamentary constituency Ongole has 3 revenue divisions Ongole Markapuram and Kandakur in Prakasam District, Andhra Pradesh. It is a backward district and majority of the people are poor and illiterate depending on agriculture and agriculture labour.

They are very much interested in giving education to their children but most of them cannot afford private boarding school and are also not capable to keep their family in town or city for education as they depend on agriculture for their livelihood.

I request Hon'ble Education Minister to sanction one Kendriya Vidyalaya at Kanigiri that will cater to the need of Kanigiri Assembly Constituency one Navodaya Vidyalaya at Darsi to cater to the needs of Darsi Assembly Constituency and one Sainik School in Cumbum, Giddalur Assembly Constituency for their education.

(ends)

Re: Alleged Harassment of SC/ST employees of BARC

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): It has been reported that a senior officer of the rank of CA(P) of Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai is allegedly harassing SC/ST employees. The SC/ST employees of BARC have been served Memorandums asking them to obtain Validity Certificate from employees belonging to Maharashtra State and not from employees of other States, which is against the rules. It is understood that Director, BARC should follow orders of DoPT, Government of India which is Nodal Agency. But in case of BARC, they are not following the same and violating provisions of Articles 341/342 of Constitution of India regarding reservation policies for SC/ST. This unpleasant situation has been creating unrest in SC/ST employees of BARC. I request Hon'ble Minister of Department of Personnel to direct BARC to follow the rules framed by the constitution and guidelines issued by the DoPT, Government of India for SC/ST reservation and give relief to the SC/ST employees of BARC.

(ends)

अनुपूरक अनुदानों की मांगें
पहला बैच
और
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

1621 बजे

माननीय सभापति: मद संख्या 16 और 17 अब सभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगों तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को एक साथ चर्चा के लिए लिया जाएगा।

कटौती प्रस्तावों के बारे में घोषणा

माननीय सभापति: अनुपूरक मांगों पर प्रो. सौगत राय जी के चार कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं। …(व्यवधान) यदि वह अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो पन्द्रह मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्ची भेज दें, जिसमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों जिन्हें वह प्रस्तुत करना चाहते हैं।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची कुछ समय के पश्चात् सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। …(व्यवधान) यदि माननीय सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो वह उसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर मौजूद अधिकारी को दे दें।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

> " कि सिविल मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्ष संख्या 13, 21 और 23 के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान हुए खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं। "

और

> " कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाये गए मांग शीर्ष संख्या 1,2,4,5, 7 से 9, 14 से 16, 18, 20, 23 से 27, 29, 32, 34, 39 से 44, 48, 51 से 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 70, 71, 73, 75, 76, 83 से 88, 92, 94, 95, 97, 98, 100 और 101 के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं। "

माननीय सभापति: श्री अधीर रंजन चौधरी जी

1624 hours

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, the House is not in order. Kindly bring the House in order …(*Interruptions*). नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप मंत्री जी को कहिए की ... (*Expunged as ordered by the Chair*) क्या अभी हमारे *… (Not recorded)* हैं? क्या यहां *… (Not recorded)* हैं? सदन के अंदर इन लोगों के खिलाफ ... (*Expunged as ordered by the Chair*) होता है, सदन के अंदर *… (Not recorded)* के खिलाफ ... (*Expunged as ordered by the Chair*) की क्या जरूरत थी? नहीं, हमें बोलने का मौका दीजिए। …(व्यवधान) हमारी भी मांग है, अगर आप सदन चलाना नहीं चाहते तो अलग बात है। आप हमारे पर ... (*Expunged as ordered by the Chair*) मत किया करो, हमारे पर ... (*Expunged as ordered by the Chair*) नहीं करो।

(1625/SK/SNB)

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय सभापति जी, इन लोगों की बात भी सुनी जाए। …(व्यवधान) अगर आप जबरदस्ती सदन चलाना चाहती हैं तो अलग बात है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): माननीय अधीर रंजन जी, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं श्री जयंत सिन्हा जी को बोलने के लिए कहूंगी।

श्री जयंत सिन्हा जी।

…(व्यवधान)

1625 बजे

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): माननीय सभापति जी, मैं सर्वप्रथम आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि कल 17 सितम्बर को हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी का जन्मदिन था।…(व्यवधान) इस दिन हज़ारीबाग के झंडा चौक और रामगढ़ के सुभाष चौक पर आम जनता केक बांट रही थी, मिठाई बांट रही थी। आम जनता यशस्वी प्रधान मंत्री जी को अनंत शुभकामनाएं दे रही थी, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि वह सदैव स्वस्थ रहें और जिस प्रकार से उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन देश को मिलता रहा है, मिलता रहे। जनता न सिर्फ हज़ारीबाग और रामगढ़ में यह कर रही थी, बल्कि देश भर में माननीय प्रधान मंत्री जी को शुभकामनाएं दी जा रही थीं।…(व्यवधान)

महोदया, आपको मालूम है और हम सबको भी मालूम है कि आज किस गंभीर परिस्थिति से देश गुज़र रहा है। पूरे विश्व में कोविड का एक तूफान चल रहा है। हम कोविड की महामारी से त्रस्त हैं। हम जब इस तूफान से गुज़र रहे हैं, अगर आप विश्व भर में देखें, सब देशों का मुआइना करें तो हमें नज़र आता है कि हम …(व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही पांच बजे तक के लिए स्थगित होती है।

1627 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पांच बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1700/MK/SRG)

1701 बजे

लोक सभा सत्रह बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(श्रीमती रमा देवी पीठासीन हुईं)

…(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): आप पहले बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप सभी अपनी सीट पर बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही पांच बजकर तीस मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

1702 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सत्रह बजकर तीस मिनट तक
के लिए स्थगित हुई।

(1730/YSH/RU)

1731 बजे

लोक सभा सत्रह बजकर इकत्तीस मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

…(व्यवधान)

1731 बजे

(इस समय श्री डी. के. सुरेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर
पटल के निकट खड़े हो गए।)

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। यह अपनी सुरक्षा के लिए और सभी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यहां पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उनका कृपा करके पालन कीजिए।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated in your seats. Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप देखिए, ये सभी व्यवस्थाएं इसलिए की गई हैं, क्योंकि आप सुरक्षित रहें। आप जानते हैं कि यह सत्र विशेष परिस्थितियों में आयोजित हुआ है। आपको सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please cooperate with the Chair.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही को चलने दें। आप प्लीज बैठ जाइए। आप अपनी बात अपनी सीट से कहिए। प्लीज बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही छ: बजे तक के लिए स्थगित होती है।

1732 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अट्ठारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1800/RPS/NKL)

1800 बजे

लोक सभा अट्ठारह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

...(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आप लोग प्लीज बैठ जाइए।

श्री जयंत सिन्हा जी।

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): सभापति महोदय जी, जब सदन की कार्यवाही स्थगित हुई।...(व्यवधान)

1801 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए।

मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि आपने इन असाधारण परिस्थितियों में, जब सारा देश संक्रमण के संकट से जूझ रहा है, इस परिस्थिति में भी आप सभी माननीय सदस्यों ने अपने कर्त्तव्यों-संवैधानिक दायित्वों को निभाया और पिछले चार दिनों में जिस तरीके से सदन चला, सदन की कार्यवाही चली, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से हम कोरोना वायरस के संक्रमण के समय में भी, अपने सारे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, आप सभी ने एक संदेश देश में दिया है, क्योंकि हम एक व्यक्ति नहीं हैं, एक संस्था हैं। हम 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारा संदेश पूरे देश में जाता है।

इसलिए मेरा व्यक्तिश: आग्रह है कि इस सदन की बहुत मर्यादा रही है। मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। आप सभी माननीय सदस्यों ने भी समय-समय पर, इस सदन की गरिमा बनी रहे, इसलिए आसन पीठ को सहयोग करते रहते हैं। मैं यह अपेक्षा करता हूं और सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि हम अपने तथ्यों को रखें, चर्चा करें, वाद-विवाद करें, संवाद करें, पक्ष-विपक्ष की बात करें, लेकिन बिना तथ्यों के आरोप-प्रत्यारोप लगाने से हमें इस परिस्थिति में बचना चाहिए। इस सदन में बहुत अच्छी-अच्छी परम्पराएं रही हैं, उन परम्पराओं को हम जीवंत रखें। मेरा व्यक्तिश: आग्रह है कि इस सत्र के लिए जो समय बचा है, उसमें हम सब अपने दायित्वों-कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए, सुरक्षित तरीके से इस कार्यवाही को चलाएं।

(1805/IND/KSP)

मैं चाहूंगा कि इस सत्र के इस समय में किसी को भी, किसी भी बात की पीड़ा पहुंची हो और मैंने आसन से किसी को कुछ कहा हो, तो मेरे कहने का ऐसा तात्पर्य कतई नहीं है। मेरे लिए सभी सदस्य बराबर हैं और हर सदस्य का संरक्षण करना मेरा दायित्व है। यदि मैं कोई बात भी कहता हूं तो सदन को संचालित करने के लिए कहता हूं। अगर किसी को पीड़ा पहुंची हो, तो मैं व्यक्तिगत रूप से माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता हूं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष जी, ऐसा कोई विषय नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : यह सदन हमेशा बड़ी उच्च मर्यादाओं से चला है। हम चाहते हैं कि इस कार्यकाल का सत्र जब चले, तो देश तथा दुनिया देखे कि भारत के लोकतंत्र में सभी माननीय सदस्यों ने विपरीत परिस्थितियों में सदन को चलाया और देश के राष्ट्रीय हित में मुद्दों पर चर्चा की तथा देश की जनता को संकट से बचाने के समय सभी साथ रहे। मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि यदि माननीय सदस्यों को पीड़ा पहुंची है, तो वे अपनी बात सदन में रखें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): अध्यक्ष जी, टैक्सेशन एंड अदर लॉज के इंट्रोडक्शन के समय मेरे द्वारा तथ्य रखते समय किसी को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। यदि किसी को ठेस पहुंची है, तो मुझे भी इस बात की पीड़ा है।

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह): अध्यक्ष जी, इसमें दो मत नहीं हैं कि जब से आपने अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला है, आपने बहुत ही कुशलतापूर्वक सदन की कार्यवाही को चलाया है। मैंने महसूस किया है कि आपने सभी सम्मानित सदस्य, चाहे वे किसी भी दल या किसी भी पक्ष के क्यों न हों, सभी का विश्वास हासिल करने की कोशिश की है और सभी का विश्वास हासिल करके ही सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयत्न किया है। मैं कहना चाहता हूं कि केवल आपके सामने ही हमारी औपचारिक प्रशंसा नहीं है, बल्कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह तहे दिल से कह रहा हूं। आज जिस प्रकार का अवरोध पैदा हुआ, जिस प्रकार का स्टेलमेट हुआ और जिस प्रकार से आपने सूझबूझ से काम लिया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, वह कम है। इस घटना के बाद जब हाउस स्थगित हुआ, तब मैं आपके चैम्बर में गया था और मैं महसूस कर रहा था कि आप किस हद तक आहत हैं। सचमुच मुझे भी उस समय बहुत पीड़ा हुई। मैंने कहा कि आपने बहुत कुशलतापूर्वक सदन का संचालन किया है और आप आश्वस्त रहें, कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। जहां तक अनुराग ठाकुर जी का प्रश्न है, वे तेज तर्रार और युवा नेता हैं। वे चार बार संसद सदस्य रह चुके हैं और अच्छे वक्ता भी हैं। यदि उनके द्वारा कोई बात निकली है, तो उन्होंने स्वयं मुझसे भी कहा है कि संसद के किसी भी सदस्य को यदि हमारी बातों के कारण कोई पीड़ा पहुंचती है, तो स्वाभाविक है कि मुझे भी उसकी पीड़ा हो रही है और उन्होंने आज यह भावना सदन के समक्ष प्रस्तुत की है। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो भी भावना व्यक्त की है, उससे सभी सहमत होंगे और आगे सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलेगी।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, आप जब पीठ में बैठकर यह कहते हैं कि आपकी यदि कोई गलती है और हम सभी के सामने सिर झुकाते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत पीड़ादायक है और इस तरह की बात यदि आप न करें, तो हम खुश रहेंगे। आप हम सभी के लिए बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं।

(1810/RAJ/KKD)

जब हम लोग कोरोना के कारण अपने-अपने गांव चले गए, अपने-अपने घर चले गए, तब भी आप ने अपना घर-बार छोड़ कर इस सदन को चलाने के लिए दिल्ली में दिन-रात मेहनत की है। इससे बड़ा और क्या फर्ज माननीय स्पीकर साहब निभा सकते हैं, मुझे मालूम नहीं है। हम सभी को

यह सोचना चाहिए कि हम इस विषम परिस्थिति में सदन में तब आए हैं, जब कोरोना का संक्रमण प्रतिदिन लगभग एक लाख से ज्यादा हो चुका है। हम सभी को सावधानी बरतना जरूरी है। इस विषम परिस्थिति में सिर्फ एक नुमाइंदा होने के नाते, हम अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपना फर्ज निभाने के लिए, सारे देश के सामने जनता की बात करने के लिए इस सदन में पहुंचे हैं। सरकार का काम है - सरकार चलाना। हमारा काम है, सरकार के काम में मदद करना और इसके साथ-साथ हमारे अंदर जो कुछ सवाल है, जो कुछ चर्चा करना चाहते हैं, उनकी ओर सरकार की निगाहें आकृष्ट कराना चाहते हैं कि ये सारे मुद्दे सदन में रखें, आपके सामने रखें। यही हमारा फर्ज होता है, यह फर्ज निभाने के लिए हम सभी यहां आए हैं। सर, यह सदन हम सभी के लिए है। यह कोई पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं है। सदन सभी पक्षों के लिए बराबर होता है। इंसान के सामने सराहना नहीं करनी चाहिए। अगर हम आपके सामने आपकी सराहना करें तो आपको लगेगा कि ये क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। कभी-कभी यह भी सोच सकते हैं कि हम लोग किसी की चापलूसी करते हैं, लेकिन यह बात नहीं है। हम जो भी कहते हैं, वह तहेदिल से कहते हैं। सदन के पक्ष-विपक्ष, हमारे पक्ष के जितने माननीय सदस्य हैं, सभी आपसे खुश हैं। सरकार पक्ष के माननीय सदस्य हों या विपक्ष के माननीय सदस्य हों, उनको आपसे कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल भी शिकायत नहीं है।

सर, जब आप सदन के चेयर पर बैठे रहते हैं, हम सभी महसूस करते हैं कि आप मेरे आदमी है और सरकार पक्ष महसूस करता है कि आप सरकार के आदमी हैं। हम सभी आपको अपना गार्जियन समझते हैं। अगर हमें किसी चीज की जरूरत होती है, कोई तकलीफ होगी, तो एक गार्जियन की हैसियत से आप हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए हम कोई भी बात के लिए हर वक्त आपके सामने गुहार लगाते हैं, क्योंकि हमें यह भरोसा है कि अगर आपके सामने सही ढंग से गुहार लगाई जाए, तो सारी समस्याओं को सुलझाना आसान होगा। इसलिए अगर हम में से कोई आहत होते हैं, हमारे बीच कोई माननीय सदस्य दु:खी होते हैं, तो आप ही के पास जाते हैं। आपके पास जाकर गुहार लगाते हैं और आप एक गार्जियन की हैसियत से सारे पक्ष को समझाते हुए, सारी चीजों को बहुत आसानी से सुलझाते हैं। सर, आपको यह सहयोग लेना ही पड़ेगा। हम सभी मिल कर यह सदन चलाएंगे। यह सदन हम सभी का है। सदन की गरिमा की रक्षा करना, सदन की गरिमा को बराबर बनाए रखना, यह हम सभी की जिम्मेवारी है, चाहे वह सरकार पक्ष हो या विपक्ष हो। सर, नमस्कार।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अनुदानों की अनुपूरक मांगे 14 सितम्बर को प्रस्तुत की गईं थीं, तत्पश्चात् इनकी प्रतियां प्रकाशन फलक पर सदस्यों को वितरण के लिए उपलब्ध करा दी गईं थीं। प्रकाशन फलक पर उपलब्धता की सूचना भी नोटिस बोर्ड पर सदस्यों की जानकारी के लिए लगाई गई थी।

अत: 14 सितम्बर से 17 सितम्बर तक कटौती प्रस्ताव की सूचना दे सकते थे। माननीय सौगत राय जी ने कटौती प्रस्ताव की सूचना भी दी है, जो सदस्यों को परिचालित किए गए हैं और यह चर्चा के पूर्व प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब दिए गए कटौती प्रस्ताव समय बाधित होने के कारण स्वीकार्य नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें जांचने और परिचालन करने का समय नहीं मिलेगा।

श्री जयंत सिन्हा जी।

कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का संशोधन और छूट) विधेयक – जारी

माननीय अध्यक्ष : जयंत सिन्हा जी, आप अपनी भाषण जारी रखें।

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): अध्यक्ष महोदय, जब सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, तो मैं बस यही बता रहा था कि कल जब परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी का जन्म दिन था, तो हमारे हजारीबाग में, रामगढ़ में, देश भर में, सभी लोग चौक-चौराहे पर खड़े होकर केक काट रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, फल बांट रहे थे और माननीय प्रधान मंत्री जी को अनंत शुभकामनाएं दे रहे थे। वे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी सेहत स्वस्थ रहे, ठीक रहे और हम लोगों को उनका जो मार्गदर्शन और नेतृत्व मिल रहा है, वे मिलते रहें।

(1815/SKS/RP)

अध्यक्ष महोदय, हम लोग बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। पूरे विश्व में कोविड-19, वैश्विक महामारी फैली हुई है। पूरे विश्व में एक तूफान सा फैला हुआ है और पूरी दुनिया इस तूफान से गुज़र रही है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारा सौभाग्य है कि इस तूफान में देश की नैया एक ऐसे मांझी के हाथ में है, जो हम लोगों को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब दूसरे देशों के प्रधान मंत्रियों और प्रेसिडेंट्स की लोकप्रियता के ग्राफ को देखा जाता है, तब आज के समय में सबकी लोकप्रियता कम होती जा रही है, घटती जा रही है, लेकिन हमारे परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि उन्होंने इस आपदा को अवसर बनाया है। हम लोग देश को सिर्फ बचाने में नहीं लगे हुए हैं, बल्कि हम लोग देश को बदलने में भी लगे हुए हैं। हम लोग आज जिस सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर चर्चा कर रहे हैं, उसे सिर्फ टेक्नीकल नज़रिये से नहीं देखा जाना चाहिए। इसे हम लोग सिर्फ एक टेक्नीकल डॉक्यूमेंट न माने।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आत्मनिर्भरता के लिए एक घोषणा पत्र है। माननीय प्रधान मंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस नेतृत्व और कुशलता के द्वारा इस दस्तावेज को तैयार किया है और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इसे थोड़े विस्तार से आपको और पूरे सदन को बताना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से देश के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। हमें इसके लिए सबसे पहले कुछ आंकड़ों को समझना होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने जब फरवरी माह में बड़ी कुशलता से बजट को पेश किया था, तब उन्होंने हमें यह बताया था कि बजट में सरकार के खर्चे 30.42 लाख करोड़ रुपये होने वाले हैं। अब हम लोग सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में 2.35 लाख करोड़ रुपये की डिमांड्स प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें 1.66 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्चे हैं। अगर हम इतिहास में जाकर देखें, तो देखेंगे कि यह अतिरिक्त खर्चा जो कि 5.4 प्रतिशत यानि 1.66 लाख करोड़ रुपये हैं, जो कि 30 लाख करोड़ रुपयों का 5.4 प्रतिशत है। इतिहास में जब इस प्रकार का सप्लीमेंट्री आता है, तो इतनी बड़ी राशि 5.4 प्रतिशत की मांग कभी हुई है कि नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि अगर हम फिस्कल 2018 या 2019 देखें, तो सप्लीमेंट्री में लगभग 11 हजार करोड़ रुपये ही मांगे जाते थे। हम लोग इस बार 2.35

लाख करोड़ रुपये मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस दस्तावेज के द्वारा देश का नक्शा और दिशा दोनों बदल रहे हैं। हम लोग इसे आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं।

अगर हम लोगों को सर्वप्रथम किसी चीज पर ध्यान देना है, तो हमें इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में स्वास्थ के क्षेत्र में कितना पैसा दिया जा रहा है? पहले डिजास्टर रिस्पांस में 46,602 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह सीधा राज्यों को दिया जा रहा है। इसमें काफी बड़ी राशि दी गई है, जिसे वे कोविड पर होने वाले खर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अस्पतालों को कोविड प्रिपेयर्डनेस के लिए 6,852 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से एम्स, लोक नायक जय प्रकाश नारायण आदि अस्पताल हैं। अन्य अस्पतालों को 4,905 करोड़ रुपये दिए गए हैं। आईसीएमआर को डिजास्टर और पैनडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए 2,475 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बॉयोटेक रिसर्च के लिए जिसमें वैक्सीन की तैयारी तेज और बेहतर तरीके से हो सके, उसके लिए 350 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप देखिए कि किस महानता से इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को पेश किया गया है कि रेलवे कोचेज़ के लिए भी कुल मिलाकर 620 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह दूरदर्शी सोच दर्शाती है कि अगर जरूरत पड़ी, तो हम लोग रेलवे कोचेज़ को भी आईसीयू बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। वेंटिलेटर्स, मास्क और पीपीई किट के लिए रेलवे कोचेज़ को भी इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में पैसा दिया गया है। इसमें पेन्शनर्स के लिए भी 745 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
(1820/VB/RCP)

कुल मिलाकर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए करीब 63 हजार करोड़ रुपए, out of the 2.35 lakh crore यानी 28 परसेंट स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दिया गया है। इसमें कुछ खर्चे हो चुके हैं। इसका क्या परिणाम हुआ? इन खर्चों का इम्पैक्ट और जो तैयारियाँ की गई हैं, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है? महोदय, आपको मालूम है कि 30 जनवरी को हम लोग देश में सिर्फ 10 टैस्ट प्रतिदिन कर पाते थे, सिर्फ 10 टैस्ट और आज के दिन हम लोग 10 लाख टैस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। दुनिया में और कोई नहीं हमारा मुकाबला कर सकता है। हम लोग इतने टैस्ट आज के समय में कर रहे हैं। करीब एक हजार लैब्स हैं, जिनमें से सरकारी लैब्स भी हैं और 600 लैब्स प्राइवेट सेक्टर के हैं। आइसोलेशन बेड्स 22 गुना बढ़े हैं, आईसीयू बेड्स 14 गुना बढ़े हैं। वैक्सीन का डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से और रफ्तार से होता जा रहा है। हर जिले में, यहाँ माननीय सांसदगण बैठे हैं, सभी अपने जिले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर ध्यान देते हैं। सबको मालूम है कि आज के समय में हर डिस्ट्रिक्ट में टैस्टिंग हो रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में कोविड केयर सेन्टर्स खड़े हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में आईसीयू और वेंटिलेटर्स तैयार हो चुके हैं। हज़ारीबाग, रामगढ़ आदि सभी जगहों पर हम लोगों ने इसकी तैयारी कर ली है। यह इसलिए किया गया है क्योंकि इन राशियों को हम लोगों ने जिले में देकर कोविड की तैयारी कर ली है।

साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 70 साल में हम लोगों ने अपने देश में सिर्फ 48 हजार वेंटिलेटर्स बनाए। अब हम लोगों ने 70 दिनों में 50 हजार वेंटिलेटर्स तैयार किए हैं। ये तैयारियाँ हम लोगों ने कोविड के लिए की है।...(व्यवधान) लाखों लोगों की जिन्दगियाँ बचाई गई हैं। हम लोग

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते गए हैं। हमारे जो कोरोना योद्धा हैं, जो फ्रंटलाइन के हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हम लोगों के फ्रंटलाइन के वर्कर्स हैं, जिन्होंने लोगों को बचाया है, देश को चलाया है, हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन लोगों ने इतने काम किए हैं।

सीएसआर के तहत कई संस्थाओं ने वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड्स दिए हैं। सीसीएल ने हमारे ही क्षेत्र- नई सराय में एक बहुत बड़ा अस्पताल खड़ा किया है, जहाँ आज के समय में बहुत-से लोगों के इलाज किए जा रहे हैं। अगर सीएसआर और पीएम केयर्स के तहत हम लोगों को यह लाभ नहीं मिलता, तो आज हम लोग कोविड के लिए तैयार नहीं होते। हमारे कार्यकर्ताओं और अनेक सिविल सोसायटीज के आर्गेनाइजेशंस, एनजीओज आदि इन सबने हमारी मदद की है। जहाँ हम लोगों के पास पीपीई किट्स, मास्क और वेंटिलेटर्स नहीं होते थे, वहीं आज हम लोग इन सभी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश से ये सभी चीजें 'मेक इन इंडिया' के तहत बनाकर 'मेक फॉर द वर्ल्ड' का काम हम लोगों ने किया है। इस प्रकार से, हम लोगों ने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है।

अध्यक्ष महोदय, यह मैंने आपको स्वास्थ क्षेत्र के बारे में बताया। हम सबको यह भी मालूम है कि लॉकडाउन के दरम्यान और लॉकडाउन के बाद एक बहुत ही जरूरी मामला था कि जिन लोगों को अनाज नहीं मिल रहे थे, जो लोग भूखे थे, जिन लोगों की जरूरत थी, उन सबको हमें अनाज दिलवाना है और इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' के तहत इस देश में हर व्यक्ति को अनाज मिला है। किसी को भूखा नहीं छोड़ा गया है।...(व्यवधान) सभी लोगों को जन वितरण प्रणाली के द्वारा, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हर किसी को अनाज मिलेगा, हर किसी को दाल मिलेगी, उन सभी को दिलवाया गया है। प्राइस स्टैबिलाइजेशन में हमने 6 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, फूड सिक्योरिटी में 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, गरीब कल्याण योजना के लिए 4,860 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे लोगों को गैस के सिलेंडर्स मिलें ताकि वे अपना खाना गैस पर पका सकें। उज्वला योजना के लिए भी इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में 13 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब आपदा आती है, तो आपने पहले जो काम किए हैं, आपके जो पुराने अच्छे-अच्छे सिस्टम्स बने हैं, उनका महत्व हम लोगों को तब पता चलता है। हम लोग मिलजुलकर, माननीय वित्त मंत्री जी उस समय वित्त मंत्रालय में थीं, उन्हीं के नेतृत्व में, माननीय अरूण जेटली जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जन-धन योजना शुरू की।

(1825/PC/SMN)

हम लोगों ने हर परिवार को बैंक का खाता दिया। आज जन-धन योजना के तहत हम लोगों ने करीब 30,957 करोड़ रुपये सीधे बैंक्स में लोगों के खातों में दिए हैं। यह जन-धन का कमाल है, जिसके द्वारा हम लोगों ने सबके बैंक खातों में पैसे दिए हैं। नैशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का पैसा भी सीधा लोगों के बैंक खातों में गया है। हम लोगों ने चूंकि तैयारी पहले से ही की हुई थी, सबको हम लोगों ने इन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर

लाभ पहुंचाया है। आज के समय जब जरूरत पड़ी, जब यह आपदा आई तो सीधा उनके बैंक खातों में हम लोगों ने ये पैसे पहुंचा दिए।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की भी दो किश्त के चार हज़ार रुपये हम लोगों ने सबके बैंक खातों में डाले हैं। इसके द्वारा जो कई लोगों की मांग थी, कई बड़े अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ मांग करते थे कि आप सीधे लोगों के हाथ में पैसे दीजिए। महोदय, अगर हम हिसाब करें और जानना चाहें कि ग्रामीण क्षेत्र में हर परिवार के बैंक के खाते में इन सब योजनाओं के तहत कितने पैसे आए हैं, अगर उनमें हम एमएसपी और फसल के भी पैसे डाल दें तो कुछ लोगों ने हिसाब किया है, अनुमान लगाया है कि ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार को 10-12 हजार करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में गए हैं। जो अर्थशास्त्री कह रहे थे कि यह पैसा दीजिए, जिससे हम कन्ज़म्पशन को मज़बूत रखें, दुरुस्त रखें, यह भी हम लोगों ने इस सप्लिमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में कर के दिखाया है।

अध्यक्ष महोदय, हम रोज़गार की बात करते हैं। आप सबको मालूम है कि इस देश की रीढ़ की हड्डी हमारा एमएसएमई सैक्टर है। एमएसएमई सैक्टर को तीन लाख करोड़ रुपये के ऑटोमैटिक क्रेडिट के बारे में कहा गया था कि उसका 20 परसेंट उनको और मिलेगा, उस तीन लाख करोड़ रुपये के लिए चार हज़ार करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड भी इस दस्तावेज़ में है। आज के समय इस तीन लाख करोड़ रुपये का काफी वितरण हो चुका है, लगभग 1.63 लाख करोड़ रुपये का आवंटन हो चुका है। हमने तीन लाख करोड़ रुपये का वायदा किया था, 1.63 लाख करोड़ रुपये का हमने आवंटन किया है और इसके द्वारा हमारे जो एमएसएमईज़ हैं, वे सुरक्षित रहे हैं। हम लोगों ने ठेले वालों से भी कहा कि हम आपको दस हज़ार रुपये देंगे, जिससे आपका कारोबार, व्यापार चल सकता है। इस सप्लिमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में 288 करोड़ रुपये का सब ठेलेवालों के लिए प्रावधान किया गया है। जिन एमएसएमईज़ की डिस्ट्रेस्ड ऐसेट्स हैं, जिनको और पैसे की जरूरत है, उनके लिए भी 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है और यह एक दुखद मामला था कि बहुत सारे शहरों में जो मजदूर थे, जिनको घर लौटना पड़ा, उनको भी रोज़गार की जरूरत थी, उनको भी हम लोगों को कोई न कोई साधन देना था। इस डिमांड फॉर ग्रांट्स में मनरेगा के लिए, जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में 60 हजार करोड़ रुपये दिए थे, उसके लिए 40 हजार करोड़ रुपये और दिए हैं, जिससे जिन लोगों को रोजगार की जरूरत है और जब वे ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर जाते हैं तो इससे हम उनको भी साधन दे सकते हैं, उनका भी संवर्धन कर सकते हैं।

महोदय, हम लोगों के लिए यह बहुत संतुष्टि की बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था रिकवर करती चली जा रही है, फिर दुरुस्त होती चली जा रही है, उसमें जो स्पाइक आया था, मनरेगा के यूसेज़ और डिमांड में जो पीक आई थी, करीब छ: करोड़ लोग जॉब-कार्ड लेकर काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि इससे पूरे सदन को संतुष्टि मिलेगी कि जो छ: करोड़ लोग मनरेगा में काम कर रहे थे, आज यह संख्या दो करोड़ से कम हो चुकी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अब रिकवर कर रही है, अर्थव्यवस्था को अनलॉक के द्वारा हम लोगों ने और मजबूत बना दिया है।

Sir, there is a particular sector to which I pay great deal of attention. That is the financial sector because as we know, credit is the life blood of the economy and if during this time of COVID-19 pandemic emergency our financial sector suffers and the life blood of our economy is not available, it is very difficult for our economy to recover for companies to get the credit that they deserve, for MSMEs to be able to get working capital loans and also for smaller entrepreneurs to be able to fund their activities and prosper.

(1830/MMN/SPS)

So, it is a matter of great satisfaction that in this lot of Supplementary Demands for Grants, if you see the various allocations that have been made to keep our financial sector robust, you will note that it is having, in fact, the intended effect. In the Supplementary Demands for Grants, we have asked for Rs.20,000 crore for recapitalisation bonds for our Public Sector Banks; we have asked for Rs.1,232 crore for a two per cent interest subvention on Shishu loans; and we have asked for Rs.1,000 crore to provide partial credit guarantees for the NBFCs. The sum of all of these is that we are providing this support at a very, very important time. I want to recognise what the Reserve Bank of India has also done in this regard. It is because of their intervention and the close coordination between our fiscal authorities and our monetary authorities, we have stabilised the financial sector.

Mr. Speaker, Sir, you will be very pleased to know that today the G-Sec rate, the rate at which the Government borrows, which is the benchmark rate, the rate at which everybody else in the economy is then benchmarked to and everybody is borrowing, that rate is at a 10-year low. जो लोग ईएमआई दे रहे हैं, जो लोग छोटे व्यापार चला रहे हैं, उन सब लोगों का जिस बेंचमार्क रेट पर ब्याज का दर सेट होता है, आज वह 5.79% है। यह 10 साल लो है। इसको आरबीआई और माननीय वित्त मंत्री जी ने इस प्रकार संभाला है कि ब्याज की दर 10 साल के लो पर 5.79% है।

There was a lot of panic. A lot of people were very worried about what is going to happen in the credit market. Will we have sufficient liquidity for borrowers to be able to get funds for their borrowings? There is sufficient liquidity. It had reached up to Rs.7-8 lakh crore. It has now come down to Rs.3 lakh or Rs.4 lakh crore. And, what is most important is the G-Sec. I spoke about the G-Sec. I said that the G-Sec is at 5.79 per cent right now. But what is equally important is, we have to understand what is the spread between the G-Sec and

the rate at which other borrowers in our economy borrow and those credit spreads are also at historic lows. This is again an example of how well the Government in collaboration with the RBI has managed the credit markets ensuring that there is sufficient credit; sufficient life blood flowing through the economy and thereby stabilising the economy.

Of course, the net result of it is that we are going through a very strong recovery. Now, we can argue whether we have reached 90 per cent or 95 per cent of pre-COVID-19 levels. But I think what the high frequency indicators are telling us is that in many sectors of the economy we are operating at pre-COVID-19 levels or even beyond pre-COVID-19 levels. Today, power usage is at 100 per cent of pre-COVID-19 levels; petrol and diesel consumption is at 100 per cent; e-way bills are over 100 per cent; and e-tolling rates are over 100 per cent. The Index of Industrial Production, steel and PMI is close to 90 per cent right now. Our foreign exchange reserves are at 540 billion dollars while most other developing countries have seen their currencies depreciate. In India, the rupee has actually appreciated against the dollar showing that our macroeconomic stability has not been compromised in any manner. The world still has confidence in India. The world has confidence in our leadership.

जो भारत के नागरिक हैं और जो हमारा विश्वास है कि हम 78 परसेंट पॉपुलैरिटी रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग मोदी जी को देते हैं, उसी प्रकार से विश्व भर में हमारी अर्थव्यवस्था की पॉपुलैरिटी को अगर आप देखें, चाहे रुपये के इंडीकेटर से देखें या एफडीआई के इंडीकेटर से देखें तो सब जगह आपको महसूस होगा कि लोग हम लोगों को एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि जब इतना बड़ा एक तूफान आता है, जब इतना बड़ा संकट और आपदा का समय आता है तो हम लोगों को अपनी प्राथमिकताओं को बदलना पड़ेगा और हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना पड़ेगा। इसलिए अगर हम इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में देखें तो हम लोग न सिर्फ आपदा से बच रहे हैं, बल्कि देश को बदल भी रहे हैं। वहां भी आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। ये सिर्फ देश को बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि एक नई दिशा देने के लिए भी इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में आपको कई चीज़ें नजर आएंगी।

अध्यक्ष महोदय, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि स्ट्रैटेजिक पैट्रोलियम रिज़र्व पर हमने 3,184 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है।

(1835/MM/VR)

Now, let us consider that. We know that oil prices are at their lowest level than they have been historically. At this point, to set aside Rs.3184 crore and

put petroleum in reserve for our country demonstrates clearly how we are thinking about *Atmanirbhar Bharat*. जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास यह रिज़र्व होंगे और इसके लिए भी हमने पैसे का आबंटन किया है। आप दूरदर्शी सोच देखिए कि हम लोग अपना रिज़र्व किस तरह से बढ़ा रहे हैं। एमएसएमई के फण्ड के लिए 500 करोड़ रुपये दे रहे हैं। अंतरिक्ष के लिब्रलाइजेशन के लिए भी हमने कई ठोस कदम उठाए हैं, उसके लिए भी 123 करोड़ रुपये रखे गए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 1366 करोड़ रुपये, फिशरीज़ के लिए 560 करोड़ रुपये, फूड प्रोसेसिंग के लिए 140 करोड़ रुपये, लाइव स्टॉक मिशन के लिए 63 करोड़ रुपये, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 180 करोड़ रुपये और एक नयी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के लिए भी 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। हम लोग सिर्फ आज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं। हम एक आत्मनिर्भर भारत, एक नया भारत इस घोषणा पत्र के द्वारा बना रहे हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि खर्च तो किया ही जा रहा है, लेकिन देश को भी हम बदल रहे हैं। देश को हम एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्यवाही 6 बजे शुरू हुई है। आप सभी को पता है कि असाधारण परिस्थितियों में हम यह सत्र चला रहे हैं। सभी माननीय सदस्य अपनी बात को संक्षिप्त तरीके से कहें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, बहुत सारे मैम्बर्स हैं और दूसरी पार्टी के मैम्बर्स भी हैं और आप इस बात को महसूस करते हैं कि सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में हर पार्टी के हर मैम्बर की दिलचस्पी होती है, क्योंकि वे अपनी-अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब पौने सात बजने जा रहे हैं, इसलिए आज सात बजे तक सदन में चर्चा हो और कल फिर से इस पर चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आज बहुत रात हो जाएगी।

माननीय अध्यक्ष : कल नहीं, आज ही चर्चा होनी है।

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी लाए हैं तूफान से देश की नाव निकाल के-

हमें विश्वास है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश करेंगे।
मिल जाएं हमें नदियां, समुद्र तलाश करेंगे।
आत्मनिर्भरता के विशाल सागर को पार करके ही विराम करेंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

(इति)

1838 बजे

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, “दोपहर तक भीग गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा ही रहा।” हम बैठे हैं और आपको सच बताएंगे। Both the Supplementary Demands for Grants for expenditure for the Central Government and the Demands for Excess Grants for expenditure for the Central Government related to 2016-17 – are deemed to have been moved. I have not found anything to come to the conclusion that some new services have been contemplated. It is a practice that the amount to be voted will be incorporated in the Appropriation Bill. जयंत सिन्हा जी एक बड़े अर्थशास्त्री हैं। मोदी जी को जन्मदिन पर हम सभी की शुभकामनाएं हैं। हम सब चाहते हैं कि प्रधान मंत्री मोदी जी लम्बी उम्र के हों। हम यह बिलकुल चाहते हैं। मोदी जी की पॉप्युलेरिटी की लहर से आप सब की नैय्या पार हो चुकी है। लेकिन जिस पॉप्युलेरिटी की आप बात कर रहे हैं, अब वह नहीं रही है, क्योंकि उन्हीं के फेसबुक पेज पर लाइक से डिसलाइक अब शुरू हो गए हैं।

(1840/SAN/SJN)

Sir, the 2020-21 Budget passed in February, 2020 had estimated an expenditure of Rs. 30,42,234 crore for the year. This is the first Supplementary Demand. The first Supplementary Demands for Grant propose an incremental cash outgo of Rs. 1,66,984 crore, an increase of 5.5 per cent in expenditure over the budgeted estimate. I must admit it.

The Supplementary Demand for funds is about Rs. 1.67 lakh crore, of which Rs. 1.62 lakh crore is the real revenue expenditure. Most of this amount relates to COVID-19 relief announcement made earlier. This amount would be 0.23 per cent of GDP. This contradicts the *… (Not recorded)* claims of the Prime Minister when he said that India would spend 10 per cent of its GDP as fiscal stimulus. It was a big *… (Not recorded)*. The fiscal stimulus was merely 0.23 per cent of GDP. It is not a surprise that due to lack of any help, our GDP for the first quarter of 2020-21 contracted by nearly 24 per cent. You have benignly forgotten the contraction of our economy.

The Government has sought an additional amount of Rs. 40,000 crore for MNREGS. This is the real contribution. आप लोग कहते थे कि यह मनरेगा मरेगा। मरेगा तो नहीं, मनरेगा, आप सबको और देश को बचाता है। यह मनरेगा सभी को बचाता है, लेकिन आपने यह अभिशाप दिया था कि यह मनरेगा, मरेगा। तब आप लोग इधर बैठा करते थे। आप लोग हर दिन यह अभिशाप देते थे कि मनरेगा मरेगा, मर गए हैं। देखिए, आज आप लोगों को मनरेगा की तारीफ करनी पड़ती है।…(व्यवधान) यह कोई दया नहीं है। यूपीए के जमाने में हमने जिस कानून की व्यवस्था की

थी, यह आपकी कानूनी मजबूरी है कि मनरेगा में पैसा डालना है। यह कोई दया नहीं है। यह कानूनी मजबूरी है।

There has been a complete breach of trust by the Centre as far as sharing of revenue with States is concerned. You have blithely forgotten it. There is a revenue deficit of over two lakh crores of rupees that the Centre had to devolve to the States. It has sought only Rs. 44,340 crore as additional fund. This is unconstitutional and a complete betrayal, especially when the States were asked to give up their right to collect taxes. आप लोग तो सेस से कमा लेते हैं, सरचार्ज़ से कमा लेते हैं। सूबे की सरकार क्या खाएगी? वह कैसे चलेगी? वह कैसे कोविड-19 के साथ मुकाबला करेगी? आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है। आप कह रहे हैं कि States have instead been asked to borrow from the RBI. मतलब आरबीआई से जो ब्याज मिलेगा, वह आपके डिविडेंड में तब्दील हो जाएगा। एक तरफ आप सूबे की सरकार को कुछ नहीं देते हैं, फिर यह कहते हैं कि आप बचने के लिए उधार लीजिए। उधार लेने के बाद आरबीआई को जो ब्याज देंगे, आप उसको डिविडेंड पर ले लेंगे। यह बड़ा ही अद्भुत है। It is ironical that States are being made to borrow against their entitlement. लेकिन यह स्टेट का एन्टाइटल्मेंट है। आप उनको बॉरो करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। The Central Government is profiteering from the misery of the States.

It is also ironical that only Rs. 2,262 crore is being given to the States under Grants-in-Aid (General) for State Disaster Response Fund. The money collected under the PM CARES Fund is about Rs. 30,000 crore which the PM has sequestered as a private fund.

(1845/RBN/GG)

This exposes the Government's doublespeak and the blatant attempts to expose our federal structure. It also exposes the big … *(Not recorded)* that Mr. Modi ji spoke before the nation about the fiscal stimulus. You were talking about *Atmanirbhar*. The amount of Rs. 20 trillion Atmanirbhar Bharat Package announced in May had a fiscal cost ranging between Rs. 1.5 trillion and Rs. 2 trillion.

Most of the rating agencies and banks had estimated it as Rs. 98,000 crore have come under the Supplementary Demands for Grants. These reiterate the points that we have been making ever since this Package was announced. Close to Rs. 18 lakh crore is for credit line expansion. You said that there is no shortage of liquidity. This Rs. 18 lakh crore is for credit line expansion and debt restructuring. Only five per cent of the economic stimulus package is

the actual expenditure by the Government. This is nothing but a bluff that the Government has tried to pull off.

I am breaking up the Rs. 98,000 crore. Out of Rs. 98,000 crore, which includes Rs. 40,000 crore of additional allocation to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Rs. 33,771 crore is for direct benefit transfer to the women holders of Pradhan Mantri Jan Dhan account; Rs. 10,000 crore is for food subsidy; Rs. 6,000 crore for setting up Price Stabilisation Fund; Rs. 4,374 crore for PM Garib Kalyan Yojana; Rs. 4,000 crore is for emergency credit line for micro, small, and medium enterprises.

The Government also sought the Legislature's nod for Rs. 20,000 crore for recapitalisation of public sector banks through issue of Government Securities. In 2017-18, it had infused Rs. 80,000 crore and Rs. 1.06 lakh crore in the net fiscal. Rs. 20,000 crore package for the banks is only ten per cent. I would like to reiterate that point. Rs. 20,000 crore package for the banks is only ten per cent of what is required by the banks on account of pandemic-induced loan crisis.

Where is the Government's additional spending on infrastructure? Where is it? The only way to revive the industrial activity and also to create jobs is by pumping huge amount in infrastructure spending. The Government is either clueless or does not intend to spend on infrastructure. This is the situation especially at a time when the private investment is also very low. As compared to Rs. 9,47,000 crore expenditure by the Centre between April and July 2019, this year it has only increased to Rs. 10.54 lakh crore. That is also mostly towards salaries and other regular expenses. So, the expenditure needs to go up to create more jobs. Push the money in the hands of the people so that consumption picks up.

इसीलिए हम क्या कहते हैं कि गरीब माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जनरल ग्रांट स्कीम बनाइए। आपने इतनी बात कही है, लेकिन माइग्रेंट लेबर के बारे में एक शब्द आपकी ज़ुबान से नहीं निकला। रातोंरात चार घंटे का वक्त देते हुए, सारी दुनिया में सबसे कठिन, निर्दयी एक लॉकडाउन घोषित हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ? सारे हिन्दुस्तान में तबाही मच गई। बिना कोई प्रिपेरेशंस ले कर, अचानक आपने बोल दिया कि लॉकडाउन शुरू हो चुका है, चार घंटे की मौहलत है। नतीजा क्या निकला कि लाखों की तादात में लोग सड़क पर उतरे। नंगे पांव, भूखे पेट अपने गांव वापस जाने के लिए पैदल चलने लगे। कोई साईकल, कोई ट्रक, कोई बस से निकल पड़ा। आपने इसका ब्यौरा क्यों नहीं दिया? आपकी वित्त मंत्री एक फरवरी को जब बजट पेश कर रही थीं, तो उन्होंने क्या कहा था?

The Finance Minister outlined the importance of data and said that in order to meet the challenges of real time monitoring of India’s increasing complex economy, data must have strong credibility.

(1850/KN/SM)

मेरी बात नहीं है। Data is the new oil. मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, यह आपकी ही राय है। 14 सितम्बर को इस सदन में, इस पार्लियामेंट में एक प्रश्न के जवाब में यह कहा गया कि it has not maintained any data on the number of migrant workers who died while trying to reach their homes after the nation-wide lockdown to combat the novel coronavirus was announced. इतना डेटा की बात करते हैं। लेकिन कितने लोगों की मौत हो चुकी थी, आपके पास कोई डेटा नहीं है।

Reports are coming from various credible organisations that more than 1,000 people have died which include getting burnt to death in forest fire, heat or crushed by truck, bus, train, exhaustion, heart attack, blood vomiting, chest pain, asphyxiation often falling in deep pit, stomach pain, dehydration, fatigue, multiorgan failure and snake bite, to name a few.

आपको एक बार इनकी याद नहीं आई? एक 12 साल की बच्ची ने तेलगांना से छत्तीसगढ़ पैदल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ दिया। एक चार-पाँच साल की बच्ची की माँ को एक स्पेशल ट्रेन से उतारा। रेलवे स्टेशन में वीडियो में क्या देखते थे कि माँ की मौत हो गई और छोटी बच्ची आजू-बाजू में घूमती है, माँ के कपड़े, टांग खींचती है कि माँ तुम उठो, अभी तक क्यों सो रही हो? चलो मेरे साथ खेलो। बच्ची को यह जानकारी नहीं थी कि उसकी माँ जिन्दगी में कभी नींद से नहीं उठेगी। क्या यह डेटा आपके पास नहीं है? जब हम पूछते हैं कि नौकरियाँ कितनी दीं, आपकी सरकार जवाब देती है कि we do not maintain any data.

यह नो डेटा गवर्नमेंट बन चुकी है। आप डेटा-डेटा करके यहाँ बार-बार गुहार लगाते हैं, लेकिन सरकार के पास कोई डेटा है ही नहीं, तो आपको कहाँ से डेटा मिलेगा? आप लोगों के सारे डेटा गलत है। सारे देश में देखिए, देश की हालत देखिए, आप लोगों को पता चलेगा। यह सरकार के दिए हुए आंकड़े से भी पता चलता है।

During April-July, 2020, the Government has collected revenue of Rs. 2.3 lakh crore out of the budgeted estimate of Rs.22.5 lakh crore for 2020-21 excluding borrowings. This is 42 per cent less than the revenue collected during the corresponding period in the previous year, 2019-20.

While gross revenue has been 30 per cent less on year-on-year basis, devolution to States has been comparatively lesser, decreased 12 per cent. This implies that the States may see a cut in monthly devolution levels in the later part of the year.

Receipts on account of disinvestment are only Rs.3 crore – disinvestment of Rs.3 crore out of the budgeted Rs.2.1 lack crore. As compared to April-July, 2019-20, the trends in collection under various components of revenue during April-July, 2020 are: net tax revenue of the Central Government is 40 per cent less; non-tax revenue is 44 per cent less; among major taxes, collection of corporate tax, income tax, GST etc. saw a reduction of 39 per cent, 29 per cent, and 35 per cent respectively on year-on-year basis.

As per the official estimates released by the National Statistical Office on 31st August, 2020, GDP at constant 2011-12 prices in the first quarter of 2020-21 is estimated at Rs.26.90 lakh crore as against Rs.35.35 lakh crore in the first quarter of 2019-20, showing a contraction of 23.9 per cent as compared to 5.2 per cent growth in the first quarter of 2019-20.

GDP estimates by various national and international agencies for India in the financial year 2020-21 have already painted a very bleak picture ranging from -5 to -11.5 per cent. आप बताइए। इसके बाद यह 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या हुआ?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठकर जब बोलते हैं तो ज्यादा बोलते हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, ज्यादा समय नहीं लिया है।

माननीय अध्यक्ष : बहुत समय ले लिया।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): कहाँ से लिया?

(1855/CS/AK)

मैडम, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ। What is the fate of $ 5 trillion economy? Already, we are facing contraction of 24 per cent and it may be increased to 35 per cent according to the experts. Yet, वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक आप कैसे पहुँचोगे, जब सालाना आपकी पॉजिटिव ग्रोथ रेट 9 परसेंट होनी चाहिए, आप जरा दयापूर्वक यह बता देना।

सर, मैंने समय एकदम नहीं लिया है।…(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, मेरा पॉइंट ऑफ आर्डर है।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): देश की जो हमारी सारी सम्पत्ति है, जो सारी हमारी फैमिली सिल्वर है, उसे आप बेचना चाहती हैं। BPCL entire 53.29 per cent stake of Government is being sold; sale of 53.75 per cent of the Government holding out of 63.75 per cent stake in SCI; and as regards CONCOR, sale of 30.90 per cent stake where the Government currently holds 54.80 per cent. The disinvestment proceeds generated by the Central Government since 1991, 67 per cent has come during the Modi Government regime. आप इन सबको बेचना चाहते हैं।

The Government has also frequently resorted to getting one PSU like ONGC or LIC to buy another. यह नया चक्कर है। 2015-16 में एलआईसी, 2016-17 में नालको, 2017-18 में ओएनजीसी, 2018-19 में फिर एलआईसी को आपने कहा to buy the Government's 51 per cent stake in the distressed Public Sector Bank, IDBI. During 2018-2019, the full stake of Government of India in HSCC Limited was acquired by NBCC India. इधर से उधर, उधर से इधर करके आप दिखाना चाहते हैं कि आपका डिसइंवेस्टमेंट किस तरीके से आगे निकल रहा है।

मैडम, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ। Has the Government set the ball rolling on asset monetization in the PSU sector? NITI Aayog has already identified assets owned by PSUs for monetization and the list is now being vetted by various Ministries.

मैडम, पीएसयूज मॉनीटाइजेशन के बारे में आप क्या कर रहे हैं, यह थोड़ा बताइएगा। The Core Group of Secretaries for Asset Monetization is already vetting a list prepared by NITI Aayog of the State-owned assets that can be monetized. अगर यह सही है, इसकी अभी स्टेट क्या है, यह कौन से सिटी में है? The process is categorized under the broad definition of disinvestment. However, it does not lead to any changes in the share-holding pattern. The amount received by the Government from asset monetization is counted as disinvestment proceeds. The sector is planning to raise Rs. 2.10 lakh crore from disinvestment. यह डिसइनवेस्टमेंट का चक्कर क्या है? आपकी इसमें क्या पॉलिसी है? कहाँ तक पहुँचे हैं? आपका टारगेट क्या है? इस टारगेट तक पहुँचने के लिए आप क्या-क्या करना चाहती हैं, आप यह दयापूर्वक बता दीजिए। सर, मैं 10 मिनट लूँगा।

महोदय, हम सरकार को जैसे सदन में मदद करते हैं, वैसे ही हम बाहर भी मदद करना चाहते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। Despite our pleas, the Modi Government took no corrective action. It refused to acknowledge that demonetization was a huge blunder. It refused to accept our advice for a simple GST with a few and moderate rates of taxes. It refused to defer the implementation of GST on the ground that trade and industry were not ready and the implementation machinery was not prepared. The result was that the economy was in doldrums at the end of 2019-2020 when COVID-19 struck our country in March, 2020. The Modi Government's response to the pandemic-affected economy made the situation worse. The Modi Government refused to heed to our suggestion. महोदय, हमारा सुझाव क्या था, हम लोगों ने कहा था to transfer cash of Rs. 7,500 instead of Rs. 5,000 to the poorest 50 per cent of the families. हमारे नेता राहुल गाँधी जी ने 12 फरवरी को ही कह दिया था, and he had prophetically predicted that we are going to be fated to face the COVID-19 pandemic situation.

(1900/SPR/RV)

The country should be prepared for confronting Covid-19 pandemic. राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को ही यह कह दिया था। उन्होंने 'न्याय' प्रकल्प के लिए poorest 50 per cent of family को 5,000 से 7,500 रुपये ट्रांसफर करने के लिए कहा। Use the mountain of food grains to generously distribute to all households at 25 kg. a month.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए।

माननीय सदस्यगण, अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय 9 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ, महोदय।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके भाषण का समय पूरा हो गया।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): नहीं, सर।

माननीय अध्यक्ष: आपकी पार्टी का ही समय पूरा हो गया।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैंने आपसे आधे घंटे का समय माँगा था। क्या आधा घंटा हो गया?

माननीय अध्यक्ष: नहीं, नहीं। बीस मिनट हो गए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, लेकिन मैंने आपसे आधे घंटे का समय माँगा था।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, नहीं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। It refused to cut wasteful and vanity expenditure on Bullet Train and Central Vista. अभी जयंत सिन्हा जी कह रहे थे कि हम सेन्ट्रल विस्टा बनाएंगे। जेब में पैसे नहीं हैं, लोग भुखमरी में मर रहे हैं। इस समय आपको सेन्ट्रल विस्टा बनाना सही लग सकता है, पर यह हमारे लिए सही नहीं है।

सर, हमारी तरफ से यह कहा गया था कि give relief on indirect taxes like GST; extend the pay protection scheme to protect employment and wages; increase spending on infrastructure projects; pay the arrears of tax devolution and GST to the States so that they may enhance their capital and welfare expenditure. Borrow more if necessary, to fund the increased expenditure. हमने उधार लेने के लिए आपको कभी मना नहीं किया। If the above measures had been taken, they would have amounted to a significant fiscal stimulus to the economy and helped arrest the slide. As it turned out, the fiscal stimulus imparted by the Modi Government was a pitiable 1.7 per cent of GDP whereas other comparable countries imparted a fiscal stimulus ranging from 10 to 20 per cent of GDP.

सर, इसका मतलब क्या हुआ? आप कहते हैं कि हिन्दुस्तान दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि हिन्दुस्तान फास्टेस्ट स्लोइंग इकोनॉमी में तब्दील हो चुका है। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण में हम दूसरे स्थान पर हैं।

सर, ये कहते हैं कि वे सब कर रहे हैं, लेकिन लोगों की मौतों की कतार को देखते हुए आप खुद सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं? अभी कोरोना की दूसरी लहर आनी बाकी है। जब कोरोना की दूसरी लहर आएगी तो इससे ज्यादा खतरा पैदा होने की संभावना है।

Another direct consequence of the closure of MSMEs is that of the 10 to 11 crore MSMEs in the country, it is estimated that all of them were closed in April, May and June; nearly 30 per cent have shut down permanently.

सर, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में कोई भी किसी पर विश्वास नहीं करता है। मैडम बैंकों को कहती हैं कि आप एम.एस.एम.ईज़. को पैसे दीजिए, पर बैंक नहीं देते हैं। आपकी बात आर.बी.आई. नहीं सुनता, आर.बी.आई. की बात बैंक्स नहीं सुनते और कस्टमर्स की बात भी बैंक नहीं सुनते। हिन्दुस्तान में अविश्वास का एक माहौल पैदा हो चुका है, आप यह पता कर लीजिए।

Despite the fact that crude oil prices declined to a low range of USD 17 to USD 42 per barrel, the Modi Government relentlessly increased the price of petrol, diesel and LPG and as a result, contrary to conventional wisdom, during the period of low demand, India had higher inflation. The CPI has increased from 5.9 per cent in March, 2020 to 6.7 per cent in August, 2020. According to the official data released by the CSO, it is only agriculture and allied activities that have recorded positive growth in quarter one. लेकिन, गांवों में डिमांड नहीं बढ़ती है। आप गांवों में जाकर यह पता कर लीजिए। गांवों में डिमांड नहीं बढ़ती है।

Sir, all other sectors of the economy have registered huge negative growth – manufacture - 40 per cent; construction - 50 per cent; travel and tourism - 47 per cent.

(1905/MY/KMR)

सर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 117 देशों में हमारा स्थान 102 हो गया है। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान हम से आगे हैं। आज हिन्दुस्तान कहाँ है, इसे आप खुद देख लीजिए।

सर, नौकरी की बात तो छोड़ ही दीजिए। अभी हिन्दुस्तान में नौकरी के लिए हाहाकार मच चुका है। जब हम सरकार से पूछते हैं कि कितनी सारी नौकरियाँ दी गई हैं, तो सरकार कहती है कि हमने नौकरी दी है, लेकिन हमारे पास डेटा नहीं है। इसकी डेटा की बड़ी कमी हो रही है। According to a survey by Azim Premji University, 57 per cent of rural workers and 80 per cent urban workers lost work during lockdown.

सर, आईएलओ की रिपोर्ट क्या बोलती है? आईएलओ की रिपोर्ट बोलती है कि 40 करोड़ लोग बीपीएल की सीमा से नीचे हैं और 14 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियाँ खोई हैं। आज नौजवान बेकार पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। मोदी जी जब सत्ता में आए थे, सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था कि अब चिंता मत करो बेरोजगार, आ रही है मोदी सरकार। अभी क्या हो गया

है? अभी बेरोजगार लोगों की क्या हालत है? इस बारे में सरकार एक बार सोचे तो हम सरकार के प्रति बड़ा आभार प्रकट करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मेरे पास और दो मुद्दे हैं।

वित्त मंत्री जी, आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने हमारी पार्टी के दावे पर आकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार से शुरू किया था। इसके लिए 50 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। इसमें 25 हजार माइग्रेन्ट लेबर्स को रहना पड़ेगा और उनके लिए 125 दिन का काम होगा। बिहार, यू.पी. और बंगाल, ये तीन स्टेट्स सबसे ज्यादा माइग्रेन्ट लेबर्स की जगह हैं। 116 जिलों को चिन्हित किया गया, जहाँ 25 हजार से ज्यादा माइग्रेन्ट लेबर्स रहा करते हैं।

मैडम, बंगाल में 11 लाख से ज्यादा माइग्रेन्ट लेबर्स पहुँच चुके थे, यह बंगाल की सरकार की राय है। फिर भी, 116 जिलों के अंदर बंगाल का एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि 116 डिस्ट्रिक्ट्स में बंगाल का कोई स्थान नहीं है, लेकिन बंगाल में 11 लाख प्रवासी मजदूर पहुँच चुके हैं, जहाँ इस स्कीम के लिए 25 हजार माइग्रेन्ट लेबर्स की जरुरत है। A huge bonanza was given to corporates by the Modi Government in the form of a steep cut in corporate taxes. The corporates have used the windfall to deleverage and are sitting on cash. According to RBI's Annual Report, the corporates are not making new investment as was expected by the Government. Regular salaried jobs are not being created. दो करोड़ से ज्यादा सैलरीड लोगों की नौकरी चली गई। अर्थशास्त्री जयंत जी, आप यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ से इन्वेस्टमेन्ट आएगा? पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट, प्राइवेट इन्वेस्टमेन्ट और हाउसहोल्ड इन्वेस्टमेन्ट, ये तीन इन्वेस्टमेन्ट्स की जरुरत है। सरकार पैसा नहीं लगाती है। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल चेयर्स के साथ हमारे प्रधानमंत्री कभी बैठकर प्राइवेट इन्वेस्टमेन्ट की बात नहीं करते हैं। हाउसहोल्ड इन्वेस्टमेन्ट कैसे आएगा? हमारे देश में चारों तरफ बेरोजगारी है। दो करोड़ से ज्यादा सैलरीड लोगों की नौकरी चली गई है। हमारे 14 लाख वर्कर्स की नौकरी चली गई है। क्या आपको यह जानकारी नहीं है? हमारी डिमांड कैसे पैदा होगी? सप्लाई और डिमांड में जब तक यह मिसमैच रहेगा, हमारा ग्रोथ कभी नहीं होगा।

Bank credit to MSME has declined from roughly Rs.5 lakh crore to Rs.4.5 lakh crore. Completed or semi-completed housing units numbering 4,55,351 remain unsold at the end of March 2020. Telecom sector has a debt burden of Rs.5 lakh crore and has got no relief. Aviation sector is operating at 40 per cent of capacity. Discoms are burdened with a debt of Rs.4.5 lakh crore. Demand for power declined by 11.8 per cent in June 2020. Of total installed thermal power capacity, the average PLF is only 48.28 per cent. Hospitality and tourism sector is estimated to lose by Rs.15 lakh crore in 2020-21. Railway freight earning declined by 26.4 per cent in April. अब तो रेलवे प्राइवेटाइजेशन में चली जा रही है।

(1910/CP/SNT)

सर, यह मोदी सरकार ग्रीन शूट कहती है, तो ग्रीन शूट आने वाला नहीं है। अगर यह कहें कि कार की बिक्री, मैडम की बात करते हैं, अगर यह कहें कि कार की बिक्री कम क्यों हो रही है, तो मैडम कहती हैं कि लोग अब टैक्सी में चलने लगे हैं। अगर कहें कि प्याज की कीमतें क्यों बढ़ गईं, तो कहेंगे कि हम तो प्याज ही नहीं खाते। अगर कहें कि जीएसटी इतना पेचीदा क्यों है, तो कह देंगे कि कानून ही ऐसा है। कानून किसने बनाया? अगर कहेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था क्यों गिर रही है, तो कहेंगे कि इसके लिए भगवान जिम्मेदार है। अगर कहेंगे कि नौकरियां क्यों जा रही हैं, तो कहेंगे कि नौकरियां जाना देश की अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। अगर कहेंगे कि अर्थव्यवस्था पर कोरोना का कोई असर होगा, तो कहेंगे कि कोई असर ही नहीं पड़ता। यह देश की वित्त मंत्री कह रही हैं। अगर कहें कि कोरोना पर विजय कैसे पाएं, तो ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) कुछ दिन में कहेंगे कि ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) और ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)। कोरोना का इलाज है, तो कहेंगे कि ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ये भारत सरकार के मंत्री हैं। कोई ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) कोरोना भगा रहे हैं तो कोई ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)। चीन को कैसे हराएं और अर्थतंत्र को कैसे बचायें? इसका एक ही सिंगल पाइंट सोल्यूशन है, मोदी जी मोर के साथ फोटो खिंचवायें। यह इस सरकार की अब हालत है। कोरोना के बारे में देश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि भारत में कोरोना महामारी है ही नहीं।

महोदय, इस सप्लीमेंट्री डिमांड का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही है। यह कहकर मैं अपने भाषण को विराम देता हूं।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : मैं पुन: सभी माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं कि वे अपनी बात को संक्षेप में कहें।

1912 hours

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Thank you, Speaker Sir. I will speak within the time limit.

1912 hours (Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

Sir, I rise to speak on certain troubling aspects of how the Government is handling the economic crisis, its misplaced priorities, the deadlock on GST compensation issue, and flippant attitude towards the citizens of India, especially the middle class.

Sir, before I begin my speech, I would like to share a quote from the great Thirukkural:

"Anbilaar Ellaam Thamakkkuriyar Anpudaiyaar
Enpum Uriyar Pirarkku."

It means, those who are destitute of love, appropriate all they have to themselves; but those who possess love, consider even their bones to belong to others.

Sir, we find ourselves in the midst of the worst financial crisis that the nation has witnessed in the last 40 years. I understand this is a global pandemic and we are not the only ones trapped in the economic crisis. But let us be clear about one thing. We have been the worst affected among the large economies. Much has been said but little can be done to help the Central Government out of its complacency at this point. The Government keeps calling this as an 'Act of God'. This very attitude is the problem. Statements, such as this, will not help revive the sentiments of economy. It will only reduce the global investors' confidence and look like a sign of the Central Government's fatigue, desperation to the common man, who is looking towards the Government for some sign of hope and relief.

At the same time, Sir, I also register my protest against how the term 'Act of God' has been used to make the distinction on the issue of GST compensation to the States. The Centre's decision to split the GST compensation into two separate categories: (i) revenue loss as a result of GST implementation, and (ii) revenue loss as a result of an 'Act of God', will betray both the spirit and letter of the GST (Compensation to States) Act. The GST (Compensation to States) Act guarantees all States an annual growth of 14 per cent in the GST revenues during the period July 2017 to July 2022. If a State GST revenue grows slower

than 14 per cent, such a loss of revenue must be taken care of by the Centre by providing GST compensation grants to the State. When the UPA Government planned the GST system, it was to ensure a seamless market, free of tax terrorism, and could help us realise the full potential of the Indian market. But we all know how the GST was introduced.

Sir, in 2017, we had a manmade pandemic, called the demonetization, which was single-handedly brought by our hon. Minister. And to compensate, to save faces, GST was hurriedly introduced in December to cover up the manmade disaster.

(1915/GM/NK)

It is a complicated maze of compliance and tax extortion that is leaving both the industry and the State with little ability to plan and implement growth strategies. When the BJP's version of GST was implemented in 2017, the principle of indirect taxation for many goods and services was changed from origin-based to destination-based. This meant the ability to tax goods and services and raise revenue shifted from the origin State where goods and services are being produced to the destination State where they are being consumed. This change came with the risk of revenue uncertainty for States like Tamil Nadu. But your ... (*Expunged as ordered by the Chair*) Government in Tamil Nadu simply agreed and went along with your commands. Luckily, the Compensation Act was made to compensate the States for five years to avoid revenue loss due to GST. You are now diluting even this promise with your 'Act of God' excuse.

As on date, Rs. 12,250.50 crore is due to Tamil Nadu as compensation for the shortfall in GST collection, of which Rs. 11,459.37 crore has accrued from April to July, 2020. This money belongs to the State Government and citizens of Tamil Nadu and they need it if they are to plan any form of compensation or stimulus to revive the State's gloomy economic landscape. At a time like this, that is during the pandemic, States need even more spending power. Not only are you not giving us the due amount, you are also unjustly trapping the State in financial crisis legalese. By delaying the funds due to us, you are weakening the State's autonomy and the ability to handle the fallout of the pandemic. All the States have spent to their maximum capacity to handle the pandemic. How can the Centre now expect the States to carry out additional borrowing instead of

giving what is due to us? The Centre's decision to go for the borrowing route to compensate States for the GST revenue shortfall and the options provided to States has been seen as nothing short of deception by so many Chief Ministers and State Finance Ministers and it is hard to not see it that way. We cannot see any green shoots at this point of time.

After all, as per the Constitutional provision, the Centre is accountable for providing GST compensation. If the Centre makes the States borrow loans for this purpose, then the financial burden would ultimately fall on the States. Receiving the cess for GST compensation from the Centre and repaying the loan through it will be a complex and uncertain process for States. States are being served a raw deal again. The intent of the Central Government is worrisome. It is reducing the States' federal autonomy but crippling them financially, forcing them to come back to the Centre with a begging bowl every time their rightful share of fund is due. The DMK has been pointing out that the economy's response to the Central Government's relief package and its policy response to the coronavirus pandemic has been lukewarm at the best.

It is important to note that things were pretty bad even before the pandemic. The Economic Times in an alarming article dated 16th December 2019 pointed out that Indian economy grew only by 4.5 per cent in the second quarter of the year, making it the sixth successive quarter when the country's GDP has shrunk. Then the pandemic happened, making it not just the longest spell in over two decades but also a sign of warning about the onset of the deepest recession we have had since 1996. It is no surprise to see why the economy has collapsed under the weight of the pandemic and lockdowns.

We have structural faults that need major overall reforms. This Government enjoys a brute majority and has the ability to pass bills with ease. Yet, it has not taken up economic reforms in the last six years, which goes to show that they care little as long as they can continue winning election after election with ultra-nationalist rhetoric and hand-out style of populism, liquidating one PSU after the other to finance the misguided policies. The inability of the Government to accept criticism from the Opposition has proven expensive. Members of this House have been pointing out this danger from as early as the first session of this Lok Sabha in 2019. Even during the Budget session, several attempts were made to

alert the Government about the impending financial crisis. But the Government chose to silence the Opposition and stay in denial mode. Now, the Government's data shows that the Indian economy has contracted to a record low of 23.9 per cent in the quarter ending June' 2020. These numbers can only get worse when the estimates of the damage in the informal sector come in, but after the alarming attitude of the Government where they have haughtily declared that they do not have data on the migrant exodus and loss of lives, I have little faith left. Turning a blind eye to the hard data will not make the problem go away.

(1920/RK/SK)

I would urge the Government, especially the Finance Minister to release a White Paper on the economic crisis and to adopt a consultative approach with the Opposition Parties, the State Governments, and the industry representatives to boost confidence in our economy. It is imperative for us to analyse where we stand if the economy must be revived.

All four major drivers of the GDP: Government expenditure, consumption, investment, and net exports, are in doldrums. Not even one of the indicators is showing any positive trend. You are only able to see green shoots. In an economy like ours, household consumption is the major driver, the engine that accounts for almost 60 per cent of India's GDP. This is majorly dependent on the ability of the nation's middleclass consumers to spend.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Your allocated time is only ten minutes.

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): I have 15 minutes, Sir. I am the only speaker from my Party.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): I have a few points to make.

Year after year, Budget after Budget, and now relief package instalment after relief package instalment, it is the middleclass that is always left out with nothing to gain.

Even now, when we are desperate for the economy to jump start and growth to resume, that too when three major components – exports, private investment and Government spending – remain unsure and shaky, consumption will be the only driver that can take us forward. You may say that the Foreign Direct Investments are flowing. India procured the maximum FDI during COVID-

19 pandemic. What to do? FDI comes only through the Gateway of India in Mumbai and only the Reliance gets it because Jio's Brand Ambassador is the … *(Not recorded)*. No other company is able to get any Foreign Direct Investment.

The Coronavirus pandemic and lockdown have hurt the middleclass the most. Families are digging into their savings and bracing for lay-offs, salary cuts and deferred salaries as the industries contract, exercising extreme discretion on all expenditures. All non-essential expenditure has come to a near-standstill with the disposable component of the income of the middle-class dwindling. How then will we see an uptick in domestic consumption that can revive the economy?

The middleclass has only got six years of lip service by this BJP Government, and very little has been done to help the middleclass. The people who bear a massive chunk of the tax burden, the middleclass citizens have always been ignored and unjustly treated by this Government.

Yet, once again when the economy is in doldrums, we find that the burden to revive has fallen on the common man. What have you done for the common man, the middleclass citizens in your relief package? How are you putting money in the hands of families? These expensive corporate loans write offs and restructuring options from the Ministry can do little to revive the economy if you do not offer serious relief to the common man and enable him to spend more and consume.

The Prime Minister likes to praise the middleclass in his speeches, showering praises that the middleclass lives with dignity, the middleclass is the strata of the society which contributes the most when it comes to running the country and never rely on someone else's mercy. The hon. Finance minister has also credited the country's middleclass for keeping the country going by paying taxes diligently, timely and honestly. So, how are you rewarding the middleclass? What relief has your Rs.20 lakh crore stimulus package given to the middleclass? You have to give us proof of how you could get Rs.20 lakh crore from the Budget.

How does loan moratorium or extra time to pay credit card bills help anyone in the long run? CMIE data shows that the poorly planned lockdown has led to the loss of nearly 20 million salaried jobs. These are not the CEOs and CFOs who lost

the jobs. These are the hard-working middleclass blue collared Indians who are falling back into the cracks of poverty. Even the Central banks rate that actions in the last year have been bad for the middle-class.

Even the Fixed Deposit, which is the main component of Indian households' planning, is yielding much lesser returns due to rate cut, impacting the middleclass ability to purchase better.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Yes, Sir. I would like to say that in trying to thumps up the economy, you have taken away the MPLADS expenditure, to the tune of nearly Rs.9,000 crore out of 750 MPs, for two-and-a-half years. It is like, when the Rome was burning, Nero was fiddling.

(1925/PS/MK)

This MPLADS money -- that is, Rs. 9000 crore -- is the money to uplift the lives of the people and to build *Anganwadis* and toilets. But the Government is building palatial houses for the Prime Minister and for the Parliament. Would the people not laugh at us? The hon. Ministers are not cutting down or following any austerity measures. You are travelling by special flights and are not even trying to save money. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Please conclude. Shri Sougata Ray will speak next.

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): I will finish in one minute. If this is how you are going to go, let me tell you that you will lose the middleclass. In the first six months of coming into power, this Government has started losing the allies. The Shiv Sena Party left you. Now, an hon. Minister of another Party has resigned. You will lose the trust of the people. It is time for the change. Thank you, Sir.

(ends)

HON. CHAIRPERSON: Thank you very much.

Those hon. Members who would like to place their written speeches, they are permitted to place their written speeches on the Table of the House.

Now, Shri Sougata Ray Ji.

1926 hours

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hon. Chairperson, Sir, I will speak on the Supplementary Demands for Grants and I will speak in support of four Cut Motions proposed by me.

The Government has sought the parliamentary nod to incur an additional expenditure of Rs. 1.67 trillion for 2020-21 to recapitalise banks, fight Covid-19, and fund various welfare schemes announced by the Government. This included Rs. 40,000 crore for additional allocation to the MGNREGS, Rs. 33,000 crore for direct benefit transfer to women holders of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana Accounts, Rs. 10,000 crore for food subsidy, Rs. 6,000 crore for setting up price stabilisation fund, Rs. 4,374 crore for PM Garib Kalyan Yojana, and Rs. 4,000 crore for emergency credit line for micro, small and medium enterprises.

Around Rs. 14,000 crore was asked for the health sector, which is in the forefront of fighting Covid and Rs. 2,475 crore to the Indian Council of Medical Research. Around Rs. 46,000 crore was sought for revenue deficit grants to States and disaster response fund in line with the Fifteenth Finance Commission's recommendations.

Now, where does that lead the economy? The baseline expectation is now that the fiscal deficit of the Government of India will widen to Rs. 14 trillion or 7.4 per cent of the GDP in the financial year 2021. This is what is happening to the economy. The deficit has already touched Rs. 8.2 trillion in the first four months of the current fiscal year, which is 3.1 per cent more than that estimated in the Budget. The revenue shortfall would be around Rs. 6 trillion in the financial year 2021.

Now, I do not envy the hon. Finance Minister for presiding over the Finance Ministry at this disastrous time. It is, definitely, a by-product of COVID which the hon. Minister has called as an 'Act of God'. But the economy was on a downward spiral even before the COVID struck. We reacted to COVID late. It was known in January that COVID was coming, but we were still welcoming Mr. Trump to India. When the Government suddenly announced a lockdown, already COVID spread was taking place.

Now, what is this leading to? India's GDP shrank by the steepest ever 23.9 per cent in the April-June period as the coronavirus lockdowns battered an

already slowing economy. About 24 per cent is the loss to the economy. The economy had grown by 5.2 per cent in the same quarter of last fiscal.

Now, you just compare this to China. China's economy grew by 3.2 per cent in April-June. Ours shrank by 24 per cent. China had a decline of 6.8 per cent in January-March, 2020.

(1930/RC/YSH)

Now how are you going to compete with China? Agriculture or poor kisans were the only outlier as all other sectors including manufacturing, construction, and services suffered a steep decline. The other thing that this Budget is doing is that it may infuse Rs.20,000 crore into public sector banks to shore up their equity. Now the Reserve Bank has given a report. It has asked the Government to urgently infuse capital and as a reaction to that Rs.20,000 crore is being given. But actually earlier Rs.80,000 crore and Rs.1.06 lakh crore were given in the previous two fiscals. We are getting only Rs.20,000 crore for the banks in the latest position.

What is the total damage to the economy due to COVID-19? The coronavirus outbreak has caused losses to the tune of Rs. 30.3 lakh crore to the national economy which is 50 per cent more than COVID-19 relief package worth of Rs. 20 lakh crore announced by the Finance Minister in her five-day press conference. So, the total loss is worth Rs.30.3 lakh crore and the Finance Minister has announced relief to the extent of Rs.20 lakh crore. So, this is the Government's response to COVID-19.

This is an economic mess which has been in the making for some time. The economy shrunk by almost a quarter due to the COVID-19 lock down. The seeds of economic disaster were sown much earlier. The first was the overnight demonetisation of 500 and 1000 rupee notes in the name of war on corruption and terror which actually did not happen. To follow it up, the demonetisation devasted small business and MSMEs and the largely informal economy. On top of that when there were green shoots of recovery, the botched implementation of GST designed by people who probably never ran a business in their lives, almost doubled the cost of compliance for small businesses. With four non-zero GST tax slabs, India keeps company with other chaotic political systems like Italy and Pakistan. Most nations have a maximum of one or two slabs. So, this

is what we have done to the economy over which the Finance Minister is presiding.

Now the Government and its supporters are behaving like ostriches. I do not know when they will get their collective heads out of the sand and recognize that this is a genuine big problem.

Having stated the problem of the economy and given the statistics about the state of the economy, I must also mention that the hardest hit are employed people. Unemployment levels have reduced as the economy unlocks but 18.9 million salaried jobs were lost in the lock down. Now where are you going to give them jobs? This Government has snatched jobs of the people.

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Sir, I am on a point of order.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): How can he have a point of order while I am making a speech? He is a professional *… (Not recorded)*. You ignore him. Sir, you are an experienced parliamentarian. Do not listen to the professional *… (Not recorded)*.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): He is on a point of order. Let us see.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, may I say about the economy that the four key engines of growth - domestic consumption, private investment, Government expenditure, and exports are faltering. Unemployment is at an all time high. Kaushik Basu was the former Chief Economist of the World Bank. He has said that investment has to go up for economic revival.

(1935/SNB/RPS)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N.K. PREMACHANDRAN): Hon. Member, Prof. Sougata Ray, let him make his point of order.

Dr. Dubey, under which rule are you raising your point of order?

प्रो. सौगत राय (दमदम): आप रूल पढ़िए।

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): This is under rule 216 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. I quote:

> “The debate on the Supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them save insofar as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion.”

सर, माननीय सदस्य इम्प्लायमेंट की बात कर रहे हैं, जीएसटी की बात कर रहे हैं, डिमॉनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये सभी पॉलिसी डिसीजन्स हैं और पिछले बजट की बात कर रहे हैं। यहां डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट्स में जो चीजें हैं, उनके अलावा वे किसी अन्य चीज पर डिसकशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए, इसी पर उनको कन्फाइन करने के लिए कहिए। …(व्यवधान) वह इतने सीनियर सदस्य हैं कि हम उनसे सीखते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि नियम 216 …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Nishikant Dubey ji, what he is saying is to supplement and illustrate his case in relation to the original grants. He is absolutely within the rule and, therefore, there is no point of order.

Prof. Sougata Ray, please continue.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, thank you for your ruling. You are a wise man, as I have always felt.

Now, I have mentioned about the failure of the economy, the very bad state in which the economy is. But one may ask that what is the formula?

I have no readymade formula. But it is said that there may be demand side interventions -- Demand side interventions by way of Direct Cash Transfers and Tax cuts to leave more money with consumers so that domestic consumption increases. From the beginning of the lockdown, economists like Dr. Abhijit Banerjee, the Nobel laureate, have been suggesting to pay at least Rs. 10,000 to the migrant labours whose conditions Shri Adhir Ranjan ji described very aptly. Not one single rupee was given.

HON. CHAIRPERSON: There is one more speaker to speak from your party.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, let him speak when his turn will come. The more, the merrier. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: All I am saying is there is one more speaker to speak from your party.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am winding up.

What is needed is, this demand side economists say, that the Government should allocate more funds for income transfers to schemes like MNREGA, speed up the process of transfer of revenues owed by the Centre to State Governments and increase Government spending on public infrastructure. Other proposals include the extension of the free food grain distribution system. So, there are formulae available but the Government is not realising it.

The hon. Finance Minister thought it fit, at this time of Corona pandemic, to sell six airports. What have airports got to do with fighting Corona pandemic

or the economic mess? They are selling the Public Sector Units, as was rightly mentioned by Shri Adhir Ranjan ji. They are selling the family silver. Now, they are not giving the GST dues to the States which amounts to Rs. 3 lakh crore. The hon. Finance Minister says that the Centre has no money, let the States borrow. Is this a responsible statement?

Sir, lastly, they are cutting out MPLADS. The amount involved is Rs. 4,000 crore per year. But as far as the Ministers are concerned, what sacrifice are they making? The Government says that they are reducing the sumptuary allowance of Cabinet Ministers from Rs. 2000 to Rs. 1400, that is Rs. 600 less, where as for the Members of Parliament, they are cutting Rs. 30,000. The hon. Ministers have the sumptuary allowance to treat and entertain guests and for that they have reduced the amount from Rs. 2000 to Rs. 1400. This Government does not believe in stringency and in any sort of austerity. The hon. Ministers will have their money, their salaries and constituency allowances would not be cut. But poor MPs would be told otherwise …(*Interruptions*) Yes, you have to work and entertain people. You are an entertainer Shri Babul Supriyo.

Sir, I would like conclude my speech by saying that the hon. Finance Minister should show a way out of the tunnel that we are in.

(1940/SRG/IND)

She has to tell us whether there is a light at the end of the tunnel.

With these few words, I thank you for allowing me time. Again, I press for my Cut Motions on the failure of the Government to tackle the problem of migrant labourers and COVID-19.

(ends)

1941 hours

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, thank you for this opportunity. First of all, I would to thank the hon. Minister for taking up multiple measures to tackle this COVID-19 induced economic crisis. I urge upon the hon. Minister to help the State Governments tide over this fiscal challenge posed by this pandemic. It is more so compounded for us because the effects of the bifurcation which we are actually facing, timely release of the dues from the Centre is of paramount importance to us.

Talking about GST compensation, from 1st April, no compensation has been given and about Rs. 4,594 crore is pending till 1st August. GST compensation for 2017-18 is also pending to the tune of Rs. 237 crore and Rs. 32 crore is pending for the year 2019-20. So, I request, through you, the hon. Finance Minister to take note of this and help us get this amount at an early date. The GST compensation has been linked to additional borrowing facility of the State. We object to it strongly and we request the Centre to work out a mechanism where the GST Council sits together and comes out with a mechanism and where the funds are raised from the open market. We have reluctantly agreed to option one. Both options one and two amount to borrowing money for the State.

Polavaram is an important project for us. It is a national project. Both the hon. Ministers are here. So, I would like to tell them, through you, that the payments are not being released on time and if you see the dates, the last payment released after 2018 was on 5.2.2020. After that, recently the hon. Finance Minister and the Water Resources Minister have told that the amount would be released soon. I thank them for that, but 6-7 months' delay is huge. The project was slated to be completed by 2021. So, we request the Government to work out a mechanism because any delay, even by a year, will be a loss of like more than Rs. 1,000 crore in terms of escalation. Even the people will get to lose. So, I request that the process of release may be streamlined by authorizing NABARD to open a direct line of credit as revolving fund with Polavaram Project authority, so that any national project or any other NABARD funded project is centrally aided. The amount is to be paid within a week of the submission of the bills. So, we request the Government to think about it. There is a lot of R&R and land acquisition amount that has to be cleared. If the project has to be

completed in 2021, the huge amount of Rs. 28,000 crore also needs to be released. So, I request the hon Ministers to take note of this.

Regarding the local body grants, I would like to say that under the 14th Finance Commission grant, Rs. 2,279 crore is pending. Most of the projects are almost due for completion and this amount which is going to be released will help complete these projects. For rural local bodies, the pending amount is Rs. 1698 crore and for urban local bodies, it is Rs. 581 crore. Even according to the 15th Finance Commission's interim report/recommendations, an amount of Rs. 1312 crore is pending for rural local bodies and Rs. 1015 crore is pending for urban local bodies. So, I request, through you, the hon. Minister to take a note of this.

Regarding the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PM-GKAY), the State has 1.49 crore ration cards covering 4,27,99,712 units. In this, we have a peculiar problem. The NFSA units in this are 2,68,25,000 and non-NFSA units are 1,59,74,000. So, there is no difference with respect to priority households of NFSA and priority households of non-NSFA State cards with respect to eligibility criteria. So, all these 4,27,99,000 people are having eligibility, but only a few people are being covered under this scheme.

(1945/RU/RAJ)

The Scheme will be existing till November, 2020. So, we request the Government to provide the benefits to all the eligible people in the State. Under the Garib Kalyan Rozgar Abhiyan, AP has not been included. We have seven backward districts; we have a huge number of migrant jobless labourers who have returned to the State. So, we request the Government to include the seven districts of Andhra Pradesh under this Scheme.

We also request the Government to release the grant meant for backward districts which is part of the AP Reorganisation Act and Rs. 700 crore is pending for almost more than one and a half years.

We also request the Government to release the dues of AP Civil Supplies Corporation which is to the tune of Rs. 1728 crore. It is an old due and it has been ratified. The figures which I am mentioning have been ratified both by the Centre and the State. There is no discrepancy in any form.

As regards Andhra Pradesh, special status has been promised on the floor of this House. We demand that special status be given to Andhra Pradesh.

It was promised by the NDA and the UPA. We request and we demand that special status be given to us.

I also want to bring one more important point to the notice of the Government. One of the main points on which the NDA Government came to power in 2014 and 2019 was that they will weed out corruption and that they will recover all the corrupt money that has gone into the system. I just want to know the steps taken by the Government to recover all the corrupt money.

I want to mention about a Press note released by the CBDT. It was released on 13th February, 2020 from New Delhi. It says that searches were conducted by the Income Tax Department leading to detection of unaccounted income of more than Rs. 2000 crore. In this Press note, there is also one more line which says that search operations were also carried out on an ex-Personal Secretary of a prominent person and incriminating evidence was seized. It is none other than our former Chief Minister's Secretary. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): No, you cannot quote a press report.

… (*Interruptions*)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): We want to know the action being taken by the Government and the status of this.…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: That will be looked into.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPESON: Please do not mention the name.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Can I say 'former Chief Minister'?

HON. CHAIRPERSON: May be.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, Sir. When the hon. Prime Minister visited our State, he commented in a public meeting that Amaravati, the capital, has been made a scam by our former Chief Minister. The hon. Prime Minister himself told this in a public meeting. This is a fact and he said that they have made an ATM of corruption. So, we demand a CBI inquiry into this matter.…(*Interruptions*) Even the State BJP unit has demanded a CBI inquiry into this issue. We request you for a CBI inquiry on this matter. …(*Interruptions*) I can hear the Telugu Desam Members supporting CBI inquiry.…(*Interruptions*)

I have one more point to raise. As regards AP Fibre Grid, public money is involved. I can place the proof on the Table of the House, if you allow me. In AP Fibre Grid, ten-lakh Set Top Boxes were bought and each Set Top Box was charged at the rate of Rs. 4400 but even a third-class kid or a fifth-class kid goes to a shop and buys a Set Top Box at the rate of Rs. 2000. At this rate, ten-lakh Set Top Boxes were bought and out of these, two lakhs of them are not working. They are not hi-tech boxes. …(*Interruptions*) We request the Central Government to look into this issue. We have already put up a request for a CBI inquiry. CBI inquiry should be conducted. It is very blatant. We can see that more than Rs. 2000 crore has been swindled from the funds of AP Fibre Grid.

There are two reasons as to why we are asking for a CBI inquiry. One is that we do not want to be branded vindictive. We expect a fair inquiry and we want a fair inquiry into this matter. …(*Interruptions*) So, we want a CBI inquiry into this issue.…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: He can very well seek an inquiry. There is no problem in it.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Secondly, I would like to quote what our honourable late Finance Minister, Shri Arun Jaitley said. I would like to bring it to the notice of the House. Please give me time to mention it. I think I have three more minutes to speak.

(1950/SKS/NKL)

Sir, when he was speaking on the Finance Bill in 2016, he said:

> "The judiciary had been encroaching on legislative and executive authority. Step-by-step, brick-by-brick, the edifice of India's legislature is being destroyed." …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N.K. PREMACHANDRAN): He is not mentioning any name. He is only making a general statement.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, he is only making a general statement. He is quoting the speech.

… (*Interruptions*)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, whatever hon. Arun Jaitley*ji* had spoken on the Floor of this House, I am quoting that. The same thing is

happening in Andhra Pradesh. The SIT has been stayed by the hon. High Court, and they have passed a Gag Order, reason being that a *… (Not recorded)* was named indeed, and the kith and kin of a *… (Not recorded)* was named in the FIR. …(*Interruptions*) Sir, it is not good. …(*Interruptions*) If the country has to prosper, the whole Collegium System has to be revoked and re-thought. …(*Interruptions*) People, who appeared as lawyers for Telugu Desam Party, have now become *… (Not recorded)*. We cannot expect a fair judgement in our State. …(*Interruptions*) We want the Government to have a fair discussion on the selection of these *… (Not recorded)*. These judgements are not in line, and there is a very thin line between judiciary and legislature. They should not encroach upon the powers of the legislature. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

…(*Interruptions*)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, the Government should take cognizance of this, and should protect the interests of the State. Thank you very much.

(ends)

माननीय सभापति : श्री अरविंद सावंत जी।

1951 बजे

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): मैं डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर अपने विचार प्रकट करते हुए और बाकी राजनीतिक चर्चा पर न जाते हुए, माननीय वित्त मंत्री जी I will confine only to the Demands for Grants. यह थोड़ा-बहुत इधर-उधर हो सकता हूं। आपने मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद योगा एंड नैचुरोपैथी के लिए 190 करोड़ रुपये दिए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। कल इस पर बात हुई थी। कल इस पर विधेयक लाया गया और आज आपने डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में इसे शामिल किया है, मैं इसके लिए आपका स्वागत करता हूं।

आपने सिविल एविएशन के लिए जो पैसा दिया है, मैं उस पर आपसे एक विनती करना चाहता हूं। अभी मंत्री जी नहीं हैं, हम लोग एयर इंडिया की जो हालत कर रहे हैं, उसके लिए सरकार से मेरी प्रार्थना है। हमने जेट को डूबते हुए देखा है, वह प्राइवेट था। हमने किंगफिशर को डूबते हुए देखा है, लेकिन वहां काम करने वाले भारतीय कर्मचारी अपने ही हैं। वे बेरोज़गार हो गए हैं और हम बैठकर उन्हें देख रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि अगर एयर इंडिया को कोई नहीं ले रहा है, तो उसे बंद कर देंगे, तो उन कर्मचारियों का क्या होगा? इसी दरमियान एयर इंडिया के मैंनेजमेंट ने पूरे भारतवर्ष में पिछले 10-20 वर्षों से काम करने वाले टेम्पेरेरी कर्मचारियों को रेगुलराइज़ करने का काम किया है, लेकिन मुम्बई में काम कर रहे कर्मचारियों को आज तक रेगुलराइज़ नहीं किया गया है। सिर्फ मुम्बई के कर्मचारी बचे हुए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आप सरकार को कह दें कि यह काम बचा हुआ है और आप वहां ध्यान देंगे, तो अच्छा होगा।

तीसरी बात यह है कि ‘प्रधान मंत्री मुद्रा योजना’ में अच्छा प्रावधान किया गया है, लेकिन जब मैं मुम्बई जैसे शहरों को देखता हूं, मैंने दिशा की दो बार मीटिंग ली है। मैंने बैंक वालों से पूछा कि कितने लोगों की एप्लीकेशंस आई हैं, तो वे बता भी नहीं पा रहे हैं। उन्हें जब लोगों की जानकारी ही नहीं है, तो किस बात की मुद्रा योजना है? ये इस तरह से बात करते हैं। मैं आपका ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप उनसे खासकर इसका डेटा मांगिए कि उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में कितना काम किया है और बड़े शहरों में कितना काम किया है? इससे अनेक लोगों को मदद मिलेगी।

मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए कोविड-19 में अच्छा प्रावधान किया गया है। मैं श्री अनुराग ठाकुर जी की बात से सहमत हूं। आपने कहा है कि देश कोरोना से लड़ रहा था, तो लोग राजनीति कर रहे थे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपकी पार्टी वहां विपक्ष में है और वह वही राजनीति वहां भी कर रही है। आप उनसे कहिए कि वहां की सरकार कोरोना से लड़ रही है और कोरोना का संकट सिर्फ मुम्बई या महाराष्ट्र के लिए नहीं है। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। आप भी जानते हैं कि ऐसी स्थिति में भी महाराष्ट्र ने, मुम्बई ने बहुत अच्छा काम किया है। डब्ल्यूएचओ ने भी इसकी सराहना की है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो राजनीति वहां चल रही है, वह राजनीति नहीं होनी चाहिए। इतनी गंदी राजनीति हुई है कि Madam, you will be surprised to know, and you may also be knowing that.

महोदय, जब पीएम केयर्स फंड की बात आई, तो पीएम केयर्स फंड के लिए मैंने भी चेक दिया है। यह ठीक है कि मैंने रिजाइन किया और मैं बाहर आ गया, लेकिन मेरे मन में कुछ भी नहीं था। मैंने

सोचा कि मैं राज्य को भी पैसे दूंगा और केन्द्र को भी पैसे दूंगा। मैंने दोनों के लिए चेक साइन किया था। मैं जब चेक देने गया, तो मुझे पता चला कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सारे सांसदों ने सिर्फ पीएम केयर्स फंड में पैसे दिए हैं। राज्यों को पैसा नहीं दिया है, उनके विधायकों ने भी सारी तनख्वाह पीएम केयर्स फंड में दे दी, राज्य को नहीं दी।

(1955/VB/KSP)

लेकिन राज्य को पैसे नहीं दिए। उनकी सारी तनख्वाह यहाँ दे दी। उनके विधायकों ने भी पीएम केयर्स फण्ड में अपनी-अपनी तनख्वाहें दे दीं। लेकिन राज्य को नहीं दिया, जबकि राज्य सबसे ज्यादा अफेक्टेड था, दुर्भाग्य इस बात का है। मैडम, मेरी एक और प्रार्थना है। मैं पीएम केयर्स फण्ड के डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। पीएम केयर्स फण्ड में, जो डोनर्स डोनेशन देंगे, उनको आपने 80 जी की सहूलियत दे दी। लेकिन राज्य की सरकार ने भी उसी तरह का फण्ड बनाया। आपने उसको सहूलियत नहीं दी। यह अच्छा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि you should be magnanimous towards the State; this is not a fair attitude towards the State. The State is also raising money for the same purpose. But it is being deprived of the benefit of concession under Section 80G of the Income Tax Act. That is not being given to the Maharashtra Chief Minister’s Covid-19 Fund. So, I request the hon. Finance Minister to look into it and grant relief under Section 80G to the Maharashtra Chief Minister’s Covid-19 Fund so that they will also be able to help the people.

पीएम केयर्स फण्ड पर सभी लोग बोलते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं इतना ही कहूँगा कि why should I fear? उसको भी आरटीआई में जाने दो, क्या है? मोदी जैसा एक प्रामाणिक व्यक्ति कहता है कि मैंने इसके लिए फण्ड बनाया है, तो डर किस बात का, आने दो लोगों को, जिनको आरटीआई में जानकारी चाहिए, तो जानकारी ले लो भैया। इतने पैसे आए, जिनका इस्तेमाल हम इसके लिए कर रहे हैं। उसमें क्या डरना है, मुझे लगता है डरना नहीं चाहिए।

एक और बात है। जीएसटी के 22 हजार करोड़ रुपए, महाराष्ट्र राज्य के 22 हजार करोड़ रुपए अभी तक नहीं मिले हैं। आप उनको प्राथमिकता से दे देंगी, तो बहुत-बहुत भला होगा, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। कोविड-19 के लिए वही तकलीफ हमें भी होती रहती है।

अब बात है ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ की। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लिए आपने पैसे रखे, पेट्रोलियम के लिए रखे। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब हम ये सारे काम करते रहते हैं, तो आगे चलकर you have made allocation to public sector banks through the Department of Financial Services and that is for meeting expenditure towards recapitalisation of public sector banks. I welcome it; there is no objection. लेकिन क्या, हम बैंकों के कर्मचारियों का समाधान व्यक्त नहीं कर रहे हैं। आपने कल एक अच्छा काम किया है, जो अच्छा काम है, उसको अच्छा बोलूँगा। पीएमसी बैंक्स के लिए आप जो कदम उठा रही हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको जल्द-से-जल्द न्याय मिले। उसका अमलगमेशन किसी बैंक से हो।

मैडम वित्त मंत्री जी, आप विश्वास नहीं करेंगी, मेरे पास उल्हासनगर से महिलाएं आईं। एक महिला रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? वह बोली, जब मैं रिटायर हुई थी, तो मैंने अपनी जिन्दगी की सारी आमदनी 50 लाख रुपए वहाँ रखे। मैंने पूछा क्यों? वह बोली कि इंट्रेस्ट ज्यादा मिलता है। वहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक्स से भी ज्यादा इंट्रेस्ट मिलता है, इसलिए मैंने वहाँ रखे। आज वे लोग रो रहे हैं। आप उनका समाधान करने की कोशिश करें। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, उसका जल्दी-से-जल्दी समाधान हो। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में अमलगमेशन करते समय आप जो कदम उठाने जा रही हैं, उसमें आपको व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा मुझे लगता है। आप उनके वेज एग्रीमेंट कर रही हैं, लेकिन उस वेज एग्रीमेंट से भी उनका समाधान होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है।

इसके बाद मैं दूसरा मुद्दा रखूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के लिए आपने पैसे रखे। आईएमडी उसके अंडर आती है। आपको पता नहीं होगा कि उसके साइंटिस्ट कहते हैं कि none of them is doing research work; they are just copying from Google and those Scientists in the IMD are like officers. उनके प्रमोशन होते हैं और नीचे वाला, जो एक्चुअल में वहाँ काम करता है, किन्तु उसका नहीं होता है।

माननीय सभापति (श्री एन.के. प्रेमचंद्रन): अरविन्द सावंत जी, इधर एड्रेस करें।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉइंटेड बोल रहा हूँ।

इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आईएमडी के काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन की बात है, मैंडम मैं एक कैटेगोरिकल विषय बता देता हूँ। मैं आपकी सरकार को, यह मत समझना कि मैं विपक्ष का हूँ, अगर कोई सूचना आई है, तो वह आपके लिए स्वागतयोग्य है। आज हाउसिंग सेक्टर में हम प्रधानमंत्री आवास योजना लाए। मुम्बई शहर में पुरानी इमारतें ढह रही हैं। …(व्यवधान) सर, मैं एक-डेढ़ मिनट में खत्म कर रहा हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. There is one more speaker from your party.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): हाँ, मालूम है। उनको भी दो मिनट ज्यादा दे दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं कनक्लूड कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मैं राजनीतिक बातें नहीं करूँगा।

अभी हमारी राज्य सरकार ने बीडीडी चॉल के डेवलपमेंट का प्लान लाया। मुम्बई में बीडीडी चॉल्स के कलस्टर्स हैं। एक बीडीडी चॉल का कलस्टर मुम्बई पोटर्स की लैंड पर है। आप विश्वास कीजिए। आज तक सरकार उसको अनुमति नहीं दे रही है, न आप करती हैं, न उनको करने देती हैं। जैसे एलआईसी की बिल्डिंग है, एनटीसी की बिल्डिंग है, ये पुराने हो गए हैं, ये ढह जाएंगे, लोग मर जाएंगे। ये बिल्डिंग्स सौ-सौ वर्ष पुरानी हो गई हैं। आपको इसके लिए नीति लानी पड़ेगी। आप सिर्फ कहेंगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उससे काम नहीं होगा।

(2000/PC/KKD)

सर, आपने समय कम कर दिया है, इसलिए मैं सीधे आखिरी विषय पर आता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त सारे क्षेत्रों का निजीकरण किया, राष्ट्रीयकरण किया, चाहे बैंक्स हों या इंश्योरेंस हो। आपकी जन-धन योजना किसके कारण सफल हुई? वह इन पब्लिक सैक्टर बैंक्स की वजह से सफल हुई या प्राइवेट सैक्टर बैंक्स की वजह से सफल हुई? …(व्यवधान) सर, मेरा एक ही वाक्य बचा है, मैं उसे पूरा करता हूं। यदि आप पब्लिक सैक्टर बैंक्स और पब्लिक सैक्टर को नहीं बचाएंगी तो रोज़गार भी जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोगों को रोज़गार मिले और गरीबों को न्याय मिले। आज हमारी जो प्रतिभा बन रही है, उसे आपको बेचना है? मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं कि आप उसे बेचने की सोचते हो, हम बचाने की सोच रहे हैं। …(व्यवधान) अगर हम दोनों इकट्ठे आएंगे तो बेचना भी होगा और बचाना भी होगा। …(व्यवधान) हम मिलकर काम करें, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।

(इति)

2001 बजे

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, वर्ष 2020-21 अनुदानों की अनुपूरक मांगों के विषय पर बोलने हेतु समय देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, वर्ष 2020-21 की पूरक अनुदान मांगों के लिए पहले बैच में 54 अनुदान मांगों का एक विनियोग है। 2,35,852.87 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से निवल नगद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च 1,66,983.91 करोड़ रुपये है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों और वसूलियों से समतल किया जाएगा। 68,868.33 करोड़ रुपये के अतिरिक्त नई सेवा या नई सेवा लिखित वाले मामलों में बचत पूर्ण विनियोग के लिए व्यय के प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपये के साथ 63 लाख रुपये का सांकेतिक प्रमाणन मांगा गया है।

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा लॉकडाउन के कारण कमजोर राजस्व संग्रह के चलते वित्त वर्ष के शुरूआती चार महीनों, अप्रैल-जुलाई में ही पूरे साल के बजट अनुमान को पार कर गया है। महालेखा नियंत्रक सीजीए द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जुलाई के दौरान राजकोषीय घाटा, इसके वार्षिक अनुमान की तुलना में 130.1 प्रतिशत यानी 8,213.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। एक साल पहले इन्हीं चार माह की अवधि में वार्षिक बजट अनुमान का 77.8 प्रतिशत रहा था। सरकार का राजकोषीय घाटा उसके कुल राजस्व खर्च के बीच का अंतर होता है। पिछले साल अक्तूबर में यह वार्षिक लक्ष्य से ऊपर निकल गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा इस वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में राजकोषीय घाटे के 7.96 लाख करोड़ रुपये यानी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। कोरोनावायरस महामारी के फैलने से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए इन आंकड़ों को संशोधित करना पड़ा है। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान हुआ है। मैं और मेरी पार्टी इस बिल का समर्थन करते हैं, इन मांगों को पूरा किया जाए। धन्यवाद।

(इति)

2004 hour

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, India is, today, confronted with a dangerous trinity of military, health, and economic threats. Diverting people's attention from these threats will not help. These are extraordinarily difficult times for our nation and also for the world. People are gripped with the fear of disease and death from COVID-19. This fear transcends geography, religion, and class.

There is unanimity that global economy will experience one of its worst years in history. While estimates vary, it is clear that for the first time in many decades, India's economy will contract significantly. The contracting economy can adversely impact our ability to feed and educate our children owing to a shortage of financial resources.

It is these imperatives to act with utmost urgency to nudge the economy back to good health, which I believe, this Government is doing diligently.

(2005/RP/SPS)

It is also expanding public expenditure to build infrastructure of various types.

Recently, Dr. Montek Singh Ahluwalia has said: "Reforms fall into three groups. About 40 per cent can be done by the Central Government alone, another 40 per cent require action by, both, the Centre and States and the rest 20 per cent can be done by the States alone." Therefore, there is a need to be agreeable across the Centre and States which is not easy but the present Union Government, under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi, can get things done.

2005 hours (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

Sir, despite strained revenues, the Government is not skimping on misspending and has proposed infusing Rs. 20,000 crore into public sector banks and allocating a further Rs. 40,000 crore for MGNREGA. The bank recapitalisation will not entail any fresh expenditure while the allocation for rural employment, as part of Atmanirbhar Bharat, will be a part Government's demand for fresh spending of Rs. 1.67 lakh crore in fiscal year 2020-21.

Around Rs. 68,868 crore will be met through savings in other schemes. According to estimates by ICRA, the Central fiscal deficit will touch 7.4 per cent of GDP in fiscal year 2021. The rating agency has, however, assumed 7.5 per

cent contraction in GDP at current prices in the current fiscal year. Sir, here, I would like to mention, with revenue collection hit amid disruptions due to lockdowns, the fiscal deficit is likely to touch 7 per cent of GDP. Here, there is 30.5 per cent fall in revenue from Income Tax. There is 34 per cent fall in revenue from GST and 13.1 per cent rise in expenditure due to additional spending incurred to save lives and livelihood. At the same time, I would also mention, around Rs. 33,771 crore have been allocated for cash transfer to women Jan Dhan accounts and in accounts of old people. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution has been provided an additional allocation of Rs. 16,000 crore for distribution of foodgrains and other expenditure. Around Rs. 14,000 crore have been allocated to the Ministry of Health and Family Welfare in its COVID fight. The National Credit Guarantee Trust Company has been allocated Rs. 4,000 crore for guaranteeing Rs. 3 lakh crore of loans to micro, small, and medium enterprises; and Rs. 46,600 crore have been allocated for revenue deficit grants to States as recommended by the Fifteenth Finance Commission.

Here, I would like to mention that while amidst calls for big push, the Government spending has gone up just by 11 per cent in April to July from last year, the expenditure pattern in rural development increased by 145 per cent. The allocation for agriculture cooperation and farmer welfare has been increased by 51 per cent. In transfer to States, it has been increased by 35 per cent. The allocation for Department of Revenue and GST compensation has been increased by 120 per cent. In case of the Ministry of Health and Family Welfare, it has been increased by 34.24 per cent, the Ministry of Labour and Employment by 150 per cent and health research by 200 per cent.

Here, last year, between April to July, the expenditure was Rs. 9.47 lakh crore. This year, despite the stimulus package, there is expenditure of about Rs. 10.54 lakh crore which is Rs. 1.07 lakh crore more or around 11 per cent. Why I am saying this is that there is a need to push more money into the economy and that is what this Government has been doing.

(2010/RCP/MM)

That should be the actual medicine to revive our economy. I would say, there is also a dire need to restore confidence in the financial system which acts as the vital lubricant for the economy. A large direct cash assistance to people,

improving capital adequacy of banks, and providing credit guarantee schemes for corporates require significant financial resources.

Government finances are already stretched and there is a major shortfall in revenues. New avenues for tax are not feasible in the short term. Higher borrowing by the Government is inevitable. India cannot afford to be too fiscally restrained in these distressing times. The Government should make full use of loan programmes of international institutions.

Recently, I saw some comments from Opposition parties why they have taken a loan from a bank which is stationed in Beijing. It is not a Chinese bank. It is an international bank where India also has its share. We have taken a loan and there is no harm in taking a loan from international institutions. Our long track record as an impeccable borrower with no default, timely repayments, and full transparency makes us an ideal borrower.

Tax revenues are going to fall short by about 2.5 per cent of GDP, but it makes no sense to respond by cutting expenditure to preserve the fiscal deficit. A slippage in the deficit should be accepted on this count. I believe, there should be larger consensus, cutting across party line, in this country.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Mahtab *ji,* please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I hardly have spoken for five minutes.

HON. CHAIRPERSON: You have already taken eight minutes; your allotted time is seven minutes.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Please allow me some more time.

HON. CHAIRPERSON: Okay, please.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Higher fiscal deficit necessitated by short-term compulsions in the current year must be followed by bolder steps to achieve fiscal consolidation once normalcy is restored. A credible plan for consolidation in the next five years is what is needed. This has to be part of the longer term agenda.

Some steps are being taken by the Government by increasing the role of the country's private sector in improving agricultural marketing, making it easier for industrial and housing projects to acquire land, introducing greater flexibility

in the labour market, and expanding public expenditure to build infrastructure of various types, to name a few.

Now, I come to the third point.

HON. CHAIRPERSON: This is your last point.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I have some more points but I will come to the third point. If you allow me, I will come to the other points relating to my State.

Now, I have a point to make on GST. The friction between the Centre and the States over GST compensation is the most important political economy challenge India faces today. It all goes back to the grand bargain to usher in GST. To create a common market that would subsume 17 taxes and 13 cesses, States voluntarily surrendered unilateral powers of taxation over half of their revenue base. To help them, a five-year compensation for revenue shortfall was legislated. It was believed that if the compensation fund did not have enough money, the Centre would step in. The legal position has two elements: States are entitled to compensation; and the GST Council shall decide the solution if there is not enough money in the compensation fund. The Centre cannot sidestep. The Centre has disproportionate powers when it comes to borrowing. But I believe, the way out requires the States to come forward to work with the Centre.

You have split the anticipated revenue shortfall between one arising out of implementation issues, amounting to around Rs 97,000 crore, and the residual amount presumed to be an act of God. You have offered two options to borrow on their own account. This is not what Mr. Arun Jaitley had assured.

(2015/SMN/SJN)

Yet, I would say as the global pandemic has played havoc with the economy, revenue streams of the Government have been severely impacted. You have provided two options. Option one seems to be better. If Centre is not coming forward to borrow, option two will hurt and will push up the interest rate.

In option one, the single window being arranged by the Centre and the entire debt being serviced from future cess receipts will ensure that the cost remains close to G-sec rate. Moreover, there will be no variation in the interest rate between the States. There will be a considerable flexibility in borrowing from the States in those stressed times as certain conditionalities have been relaxed.

Most significantly, 14 per cent assured growth has been maintained. Only a part of it has been deferred. Those who are harping on to take the pound of flesh from the Centre at this juncture should remember the VAT regime that was prevalent before the GST came into existence. I would ask those States to put themselves in that VAT regime and consider what would have been their position today in this time of contraction.

Sir, many things have been said about the migrant labour issue. I am not going more into it.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Just give me two or three minutes more. I will just shorten it.

HON. CHAIRPERSON: It is very difficult to give two or three minutes.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, we will be sitting here till 11 'o'Clock. You understand that. I will also be sitting to hear what the Minister is going to say because I have participated in this discussion.

HON. CHAIRPERSON: We have to accommodate everybody in this discussion. There are a number of hon. Members to speak.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I know about that. This is a Supplementary Demands for Grants, particularly, first Supplementary Demands for Grants, and this is the first discussion that we are having after six months.

HON. CHAIRPERSON: Your party has been allotted five minutes. But you have taken more time.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I know that and that is why, I am requesting you.

Even today, nobody knows for sure what is the number of migrant workers in our country. Therefore, it is necessary that we have to keep track of all these migrant workers.

The fourth thing is about urban poor. What Mr. Sawant was mentioning was relating to urban poor. There are migrant workers who are also urban poor but there are large number of urban poor who stay, reside or live in urban areas. What specific programme is being made for them? We are doing a lot of things. The Government is doing a lot of things for the rural poor. But there is a necessity to have something for urban poor.

Recently, Odisha faced severe flood. Nineteen districts of Odisha have been affected. A Committee had gone there from the Union Government and there is a demand from the Odisha Government to provide Rs. 1100 crore for that flood.

Lastly Sir, I would talk about the MPLAD. The first notification of MPLAD was given on 8th April where it was told that for two years, MPLAD will be suspended. Subsequently, on 12th May, another notification came where it was mentioned that this includes the unreleased instalment for any hon. MP as on 31st March, 2020 which means those MPs who have already utilized five crore of rupees, have been provided five crore of rupees but those who could not utilize five crore of rupees, have been denied. There has to be parity. That is why, I request the hon. Minister because in that Ministry, there is zero amount.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I am concluding.

In that Ministry, there is zero. Therefore, justice should prevail.

While concluding, I will just mention here that economic revival must focus on creating jobs. That is the highest challenge today. Now, it has assumed tsunami-like dimensions. The rise in utilisation of MNREGA scheme is witnessed by the workers.

HON. CHAIRPERSON: Mahtab Ji always concludes his speech within the time. Today, he has taken more time.

(2020/MMN/GG)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I am concluding. Therefore, I would request that restoring confidence in people through direct cash assistance and other welfare programmes can help them live their life and also spend money to revive the economy.

(ends)

2020 hours

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I rise here to present the views of Bahujan Samaj Party and *Behen* Kumari Mayawati Ji.

Hon. Chairperson, this Government has described COVID-19 as a blessing in disguise. All of a sudden, it can blame every policy failure of the last six years to this act of God but the people of this country should not forget that the failures of the once vibrant promising Indian economy are not an act of God. They are an act of Government; they are an act of bad governance.

मान्यवर, अर्थव्यवस्था लॉकडाउन से पहले किस स्थिति में थी, इस पर ज़रूर हम लोगों को थोड़ी सी समीक्षा करने की जरूरत है। बेरोज़गारी 45 साल की अपनी सबसे चर्मसीमा पर थी। किसानों की आय में 40 सालों में सबसे कम वृद्धि हो पाई थी। मार्च, 2020 में खपत में दस सालों में सबसे कम वृद्धि पाई गई थी और इसका प्रमुख कारण था कि तेज़ी से महंगाई बढ़ रही थी और उसी तेज़ी से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ पा रही थी। पिछले छह सालों में नोटबंदी, जीएसटी का खराब क्रियान्वयन और अस्थिर नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत बद से बदतर होती चली गई।

Hon. Chairperson, while the COVID-19 cases rapidly rose in every State and in every Union Territory of the country, the GDP collapsed with April-June recording a 23.9 per cent decline compared to the same period in the year before. While every economy has faced a decline due to COVID-19, the Indian economy saw this deepest decline of any group of 20 countries.

Now, I am going to come to the Supplementary Demands for Grants relating to the Ministry of Labour and Employment. मान्यवर, इसमें चार हजार 374 करोड़ रुपये प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए आवंटित किया गया है। सरकार की धमाकेदार हेडलाइंस में आता है कि 42 करोड़ लोगों को अब तक मदद की गई है, लेकिन इस दावे को गहराई से जांचने की जरूरत है। दो करोड़ 81 लाख वृद्ध, विधवा और दिव्यांग गरीबों को मात्र एक हजार रुपये दिए जाते हैं। क्या सरकार यह समझती है कि एक हज़ार रुपये में लॉकडाउन में ये लोग गुज़ारा कर पाएंग? 20.6 करोड़ लोगों को जन-धन खाते में प्रति माह 500 रुपये दिया जाता है। जो यह पांच सौ रुपये, मतलब एक दिन का 16 रुपये 66 पैसा होता है, क्या सरकार यह समझती है कि 16 रुपये 66 पैसे में इस जन-धन योजना के तहत हमारी महिलाएं अपना जीवन-यापन कर पाएंगी?

मान्यवर, दो करोड़ 66 लाख प्रवासी मज़दूरों को पांच किलो अनाज प्रति महीने, दो महीनों के लिए दिया गया। लेकिन मई के अपने आत्मनिर्भर पैकेज में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि इस पैकेज से आठ करोड़ लोगों को फायदा होगा। जिस हिसाब से अभी सिर्फ और सिर्फ एक तिहाई लोगों को फायदा हुआ है, बाकी दो तिहाई लोग अभी भी इस नीति का फायदा उठाने के लिए लालायित हैं। इसके साथ-साथ मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि इसी लेबर और एंप्लॉयमेंट बजट

में हमारे यहां के बुनकरों और खास तौर से पूर्वांचल और अंबेडकर नगर के बुनकरों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आज उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहां तक कि बिजली विभाग के लोग आए दिन उनके साथ ज़बरदस्ती करने का काम कर रहे हैं।

Now I come to the Supplementary Demands for Grants relating to the Ministry of Statistics. The Ministry of Statistics has been granted Rs.30.04 crore for the new scheme, 'National Programme for Improving Quality of Statistics.' I would like to ask the Government to clarify this. Will we now see the real data on unemployment, GDP, and farmers' suicide? Will we finally get a database on migrant workers? Over the last six years, the Central Government has worked to weaken the financial autonomy of the States and this crisis has culminated during the pandemic. The GST compensation due to the States now stands at Rs.2.35 lakh crore.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please conclude.

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am about to conclude. I have seven minutes' time.

HON. CHAIRPERSON: No.

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): I am not going to get into too much details because I have very little time.

(2025/VR/KN)

But as it stands today, roughly Rs.2.35 lakh crores are still falling short. The Finance Minister really needs to look into it.

I have two more points on Demands for Grants to raise and I will conclude. In the Supplementary Demands for Grants, the Ministry of Railways has been granted Rs.620 crores in terms of COVID-19 emergency response and health system. It is appalling to see that the Railway Ministry has recently accepted that 97 people have died while travelling through Shramik Special trains till 9.9.2020. In May, newspapers documented an article on how a four-year old died in a Shramik Special train. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please conclude.

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am about to conclude.

After all this starvation and suffering, migrant workers were charged ticket fares.

I want one more thing to add. In Ambedkar Nagar, two trains had been suspended because of COVID-19. I would speak on it later on because there is less time.

अंत में, मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना भी धन यह सदन सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में सरकार को देगा, मेरी उम्मीद है कि वह धन गरीबों के हाथ में जाएगा, ताकि उसका फायदा ले पाएं। सच्चाई यह है कि सारी की सारी सरकारी नौकरियाँ कान्ट्रैक्ट यानी कि संविदा पर दी जा रही हैं। हाल ही में यूपी सरकार ने प्रस्ताव किया है कि सरकारी नौकरियों पर पाँच साल संविदा पर कार्य करना अनिवार्य होगा, जो कि नौजवानों के साथ विश्वासघात है। नौजवानों को सम्मानजनक आय दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता कमजोर लग रही है। शायद सरकार अपना वादा भूल गई है, देश भर के करोड़ों नौजवान खास कर अम्बेडकर नगर और उत्तर प्रदेश के युवा अभी भी आशा और प्रतीक्षा में बैठे हैं कि हर-हर नौकरी, घर-घर पैसा आने का काम होगा। लेकिन मान्यवर, यह बिल्कुल नहीं हो पा रहा है।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am concluding. This is the last line.

मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि एक्ट ऑफ गॉड ने एक बहुत ही अच्छा मौका माननीय वित्त मंत्री जी को दिया है कि वह एक नए सिरे से अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना आरम्भ करें। मेरा आदरणीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि अर्थशास्त्रियों और सभी राज्य सरकारों को…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You always say that you are concluding but you do not.

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, this is my last line.

HON. CHAIRPERSON: Okay, conclude it in one minute only.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): मेरा वित्त मंत्री जी से यही निवेदन है कि सभी राज्य सरकारों और अर्थशास्त्रियों को निष्पक्ष रूप से साथ लेकर एक मजबूत अर्थव्यवस्था को गढ़ने का काम करें, जिससे शिक्षा, चिकित्सा और नौकरी हर भारतीय को समान रूप से मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(ends)

2027 hours

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): Thank you very much, Chairman, Sir, for allowing me to participate in this discussion on Demands for Grants. I know that there is paucity of time. I will confine to the particular points and I will conclude my speech within the time limit.

Sir, there are certain points to which I would like to draw the attention of the hon. Minister. Specially during the COVID-19 time, the Government of India had been giving assistance to the States in terms of equipment like ventilators, PPE Kits, masks, and everything till August. It is the common issue for all the States. But in the case of Maharashtra, the Government of India has stopped supply of such kits from the month of September. As you know, Maharashtra has been badly affected by COVID-19 pandemic. If the Government does not resume the supply of these safety kits, it will be very difficult for the State Government to control the situation and it will be an additional burden on the State Government. I would request the hon. Minister to kindly look into it.

The second point that I want to raise is with regarding to GST compensation. As per the CGST Act, the States are required to be compensated for loss of revenue due to implementation of GST for 5 years' period. But in the COVID-19 situation, from April to till date, the GST compensation of about Rs.25,000 crores to Maharashtra are still pending. So, it will be very difficult for the State Government to tackle the COVID-19 crisis without the help of the Central Government. I would also request the hon. Minister to take note of this.

Now, I come to the tax devolution part. The devolution of taxes has already been done. As per the recommendations of the Finance Commission, during the period between April and August, the State of Maharashtra has just received Rs.13,372 crores against an amount of Rs.20,045 crores. So, there is a shortfall of about Rs.6672 crore.

Under the *Atmanirbhar Bharat* scheme, the Government of India has announced to strengthen the MSME sector by providing a loan of about Rs.2 crore. As far as Maharashtra is concerned, about 20 lakh MSMEs have registered themselves for the incentive announced by the Government. But out of 20 lakhs, only 2.5 lakhs qualify to get this incentive.

(2030/SAN/CS)

So, these stringent guidelines, which are published by the Government of India, need to be relaxed so that maximum MSMEs can take advantage of these incentives being provided by the Government. Otherwise, it is going to affect the lowest part of our economy which will, again, be attributing and contributing to unemployment in the country.

Sir, I will come back to the nutrition of women and children. During this COVID-19 situation, Maharashtra Government demanded an assistance of Rs. 2,000 crore from the Government of India. So far they have sanctioned Rs. 1,330 crore. I would request the hon. Minister to look into that aspect also.

Sir, I am coming to the issues of my constituency now. Our main income is generated from the fisheries development. The only source of earning for the fishermen is the tuna and the dried tuna mass being produced out of it. So, for an effective marketing of this tuna mass being produced and for bringing technological advancement for tuna development, even the Standing Committee on Home Affairs have recommended releasing Rs. 12 crore to the Lakshadweep Administration so that there may be an effective marketing of these products. I do not say that the hon. Minister should provide it only because it has been recommended by the Committee, but if we get it, it will provide a great benefit to the fishermen who are already a vulnerable part of the society.

My second issue is regarding smart city project. Kavaratti Island has been given the Smart City Project. For that, Rs. 60 crore have to be contributed from the State head. So, Lakshadweep Administration has put the demand before the Central Government to grant special allowances for implementing the Smart City Project.

Sir, you know that our total allocation is ranging from Rs. 1,300 crore to Rs. 1,400 crore annually. From that, 20 per cent is already cut. Over and above, my MPLAD Fund, which was also being used for the development of my Island, is also taken away for two years. My request to the hon. Finance Minister is that in the Revised Estimate, which is going to come, if the Central Government considers it on humanitarian ground, it will be a great help. Otherwise, Lakshadweep will be in a very difficult position to go ahead because lot many development projects are pending. I would request the hon. Minister not to go for any further cuts when we ask for the revised estimates.

Sir, there was one proposal given under Khelo India for construction of an indoor stadium amounting to almost Rs. 18 crore. That has been pending for almost one year. No amount has been released for that.

I took even the meeting of DISHA. For MNGREGS, not a single pie has been released for Lakshadweep Administration.

The NHM, National Health Mission, is contributing to lot many things as an easy way to buy the equipment and appointment of specialist doctors. There are three posts of specialist doctors lying vacant. We are not in a position to appoint them because of paucity of funds. We had requested for Rs. 11.6 crore, of which Rs. 7.5 crore have been approved, but only Rs. 4 crore have been released. I urge upon the Government to release that.

Finally, I come to the wage component. The issue of enhancement of wages of local labour has been pending since 2011. The Labour Welfare Board has recommended for the enhancement of wage which is pending for want of additional five crores of rupees so that wage component can be given to them. This is the need of the hour also because wage loss and everything is happening.

I thank you for allowing me to speak.

(ends)

2034 hours

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on Supplementary Demands for Grants.

Firstly, the Finance Minister is seeking approval for an expenditure of Rs. 2.35 lakh crore, which includes Rs. 1.66 lakh crore for the ongoing COVID-19 pandemic. I would just request the Finance Minister to give the break up of Rs. 1.66 lakh crore as to how much is being given to each State, particularly Telangana, to combat COVID-19.

Secondly, the Finance Minister is also seeking Rs. 46,600 crore towards the revenue deficit grants to the States as recommended by the 15th Finance Commission. What is the share of Telangana and when will the revenue deficit grants be given to the States?

(2035/RBN/RV)

I would like to make a few points. The first point is about the revenue deficit grants. Revenue deficit grants are calculated as recommended by the Finance Commission. But our hon. Chief Minister, Shri KCR *Garu*, has been requesting the Centre to release additional funds in the form of special package over and above clearing the pending dues of States to fight this pandemic. So, what does the Ministry have to say on this?

Secondly, the Finance Commission was to meet the Economic Advisory Council with a view to revisiting some of the recommendations made by it. What happened to that meeting? That may kindly be informed.

The next point is about the GST dues to States. I will focus on the State of Telangana only. Like other States, Telangana also agreed for GST when GOI assured in this very august House, with legislative backing, that compensation would be paid to States for five years. But now the Finance Minister is taking shelter under ‘act of God’. It is not acceptable.

The late Shri Jaitley, while replying to the debate on the GST Compensation Bill in Parliament had said and I quote: “States have pooled in their national interest to the GST Council, the Centre has also pooled in to the GST Council. So, the GST Council is India’s first federal institution where national interests of the Centre and States have been pooled together in a federal institution. It is incumbent upon all of us to make sure that the federal institutions work. Therefore, in order to make this federal institution work, the

delicate balance between what the Centre and States have unanimously agreed upon is to be maintained." He further said, "It is a federal contract".

So, this federal contract has to be honoured. The States always get a dribble whenever new taxes are implemented. After the introduction of the GST, Telangana is losing revenue. The GOI is saying that it would not compensate the GST revenue loss which is not acceptable. The agreement should strictly be followed. Now, as on date, there is more than Rs. 9,000 crore of dues to our State, Telangana, towards GST and IGST. The GST dues are Rs. 5,500 crore and the balance are the IGST dues.

The States are in the forefront in fighting COVID-19 and reviving the stalled economic activities. For all these measures, adequate funds are needed. The State is in dire need of funds and has requested the Centre for its due share as the GST compensation.

The issues related to the GST have also been raised by our hon. Chief Minister, Shri KCR *Garu*, who has written a detailed letter to the hon. Prime Minister recently.

Section 8 of the GST Act, 2017 stipulates that the Centre shall levy a cess on the Central GST and the Integrated GST for five years in respect of specified goods and services for the purpose of providing compensation to States.

There is no provision in the law that the States would borrow in case of shortfall in GST compensation pay-out by the Centre. It is legally the responsibility of the Centre as the administrator of public accounts of India, of which the GST Compensation Fund is only a part.

To calculate the compensation, the projected revenue is to be calculated by applying 14 per cent annual growth over the 2015-16 base revenue from taxes subsumed under GST.

The Centre promised that cess will come down after introduction of GST. But the reality was totally different. Most importantly, these cesses are not sharable with the States. For example, the cess of Rs. 13 per litre on petrol is yielding Rs. 2 lakh crore revenue to the Centre. But on the other hand, the States are losing their chance to tax.

The Centre has violated the provisions of the GST Compensation Act by parking the surplus cess in its Consolidated Fund instead of parking them in the

non-lapsable Compensation Fund in the Public Account and using the surpluses for meeting its expenditure.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Hon. Member, please conclude.

(2040/SM/MY)

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Sir. I am concluding. The argument that borrowing by the States will be helpful for reducing the burden of the national economy is not correct. The borrowings by the Centre as well as by the States are from the same financial system and same pool of investors and their impact on the micro-economic situation is not very different. Borrowings by the States will also push up the yields on Government securities.

By borrowing and paying shortfall in compensation, the Centre is not going to lose anything. The Act provides for the levy of cess beyond five years. The Centre can revamp its borrowings and the cess will be levied for five years.

Sir, my last point is, in the difficult COVID-19 situation, हमारे स्टेट तेलंगाना में हम लोग रायतु बंधू स्कीम के तहत इंडिया में पहली दफा प्रति एकड़ एवं प्रति ईयर के लिए 10,000 रुपये देते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने 39,000 करोड़ रुपये किसानों के एकाउंट में डायरेक्ट दिया है। We are giving 24 hours electricity …(*Interruptions*) Within one minute, I will conclude. Recently, in pandemic situation, 64 lakh metric ton of paddy, हम लोगों ने फार्मर्स से डायरेक्ट परचेज़ करके उनके एकाउंट में पैसा डाला है। उसी तरह से हमने 9 लाख मीट्रिक टन मक्का भी परचेज किया है। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

(इति)

2041 बजे

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण अनुदानों की पूरक माँगों पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। साथ ही साथ आपसे निवेदन करता हँ कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से दूसरा वक्ता हूँ, इसलिए समय के मामले में आपके संरक्षण की कृपा प्राप्त हो।

माननीय सभापति महोदय, सप्लीमेन्ट्री डिमांड्स फॉर ग्रान्ट्स मूलत: दो वजहों से सदन में आता है। जब ऑथराइज़्ड अमाउंट सफिशएन्ट नहीं रह जाता, या फिर जब एडिशनल एक्सपेंडिचर की जरुरत पड़ती है, तब इन सप्लीमेन्ट्री डिमांड्स फॉर ग्रान्ट्स के माध्यम से आदरणीय वित्त मंत्री जी ने लगभग 2.35 लाख करोड़ रुपये की राशि का निर्धारण इस लोक सभा के अंतर्गत रखा है।

जहाँ तक मेरा ध्यान आता है कि भारत के संसदीय इतिहास में यह सबसे बड़ा रकम वाला डिमांड्स फॉर ग्रान्ट्स होगा। इसके तहत लगभग 1.67 लाख करोड़ रुपये का नैट कैश जो अतिरिक्त व्यय के रूप में इस देश के सामने आएगा। जबकि 68,868 करोड़ रुपये की राशि का इंतजाम विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में बचत को बढ़ावा देकर तथा अन्य मदों में प्राप्तियों के माध्यम से पूरा किया गया है। यह डिमांड फॉर ग्रान्ट इस महत्वपूर्ण दौर में सदन के सामने आया है, जब पूरे विश्व के साथ-साथ भारत भी कोरोना की वैश्विक चुनौती का सामना कर रहा है, इसलिए कोविड महामारी के माध्यम से ये पैसे समाज और वित्तीय ढाँचे को मजबूत बनाने के लिए खर्च होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आँकड़ों में बहुत इसलिए नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पार्टी के पूर्व वक्ता आदरणीय जयंत सिन्हा जी ने आँकड़े आपके समक्ष रखे हैं। मैं मुख्य रूप से यह कहना चाहूँगा कि जहाँ मनरेगा में हमने 40,000 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है, वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना और सामाजिक सहायता कार्यक्रम के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में नकदी ट्रान्सफर के लिए 33,771 करोड़ रुपये माँगे हैं। वहीं कोरोना से लड़ने के लिए और उसकी चुनौतियों से सामना करने के लिए हमने 14231.96 करोड़ रुपये की माँग की है, जिसमें कोरोना महामारी के शोध कार्य के लिए आईसीएमआर के माध्यम से 2,475 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया है।

(2045/CP/AK)

भारत के मध्यम वर्ग और भारत की जनता को ध्यान में रखते हुए, हमारा मूल्य स्थिर रहे, बाजार में कोई आपाधापी नहीं मचे, इसलिए मूल्य स्थिरीकरण के लिए हमने 6 हजार करोड़ रुपये रखे हैं। उसी के साथ-साथ जो खाद सब्सिडी की योजना माननीय प्रधान मंत्री जी ने नवंबर तक जारी रखने की बात कही है, उसके लिए भी हमने 10 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। वहीं नौजवानों के लिए, मुद्रा योजना के लिए लगभग 1,232 करोड़ रुपये और गरीब कल्याण योजना के लिए 4,800 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं, वहीं सहकारी बैंकों के लिए 20 हजार करोड़ रुपये, 'प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना' के लाभार्थियों के लिए लगभग 13 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस डिमांड फॉर ग्रांट्स के माध्यम से हम एक नए भारत की रचना करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमें यह देखना होगा कि इस डिमांड फॉर ग्रांट्स में जो इतनी बड़ी राशि आई है, उसके पीछे का मूल तत्व क्या है? हमारी विचारधारा क्या है? हमारी

सोच क्या है? यह सोच सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना तब और जरूरी हो जाता है, जब प्रतिपक्ष के नेता यह कहते हों कि कोरोना से लड़ने के लिए थाली बजायी, ताली बजायी, दिया जलाया, इसकी उपयोगिता क्या है और वह अर्थव्यवस्था को भगवान के भरोसे छोड़ते हैं। हम निश्चित रूप से भगवान के भरोसे अर्थव्यवस्था को नहीं चलाते, लेकिन हम भगवान के माध्यम से दिए गए संकेतों को पहचानते हैं, जिसको हम ईश वाणी कहते हैं, जिसको ईश्वरीय वाणी कहते हैं।

हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में हमारे मनीषियों के माध्यम से जो स्वर अभिव्यक्त हुए हैं, जिस अर्थशास्त्र को पहचानने की शक्ति भारत की आजादी के बाद की बनी सरकारों में नहीं थी, उस स्वर को हमने पहचाना है और अपनी नीतियों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने की योजना की शुरुआत की। इसलिए आपको मौलिक अंतर आएगा। हमने कभी यह चर्चा नहीं की कि जब महात्मा गांधी ने चरखे के माध्यम से देश को स्वतंत्रता दिलाने की बात कही थी, हम सबको पता है कि चरखे से स्वतंत्रता नहीं मिलती, हम यह भी जानते हैं कि नील की खेती का विरोध करने से स्वतंत्रता नहीं मिलती है, लेकिन वे भूल जाते हैं, क्योंकि वे यहां की सांस्कृतिक एकता और विरासत को नहीं जानते। हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सम्पद्राय के चश्मे से देखते हैं, नहीं तो उनको पता होगा कि इन संकेतों से इन कार्यक्रमों के माध्यम से देश का एक विराट जाग्रत होता है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने चिती शब्द से नवाजा है। उसी विराट चिती का प्रदर्शन था जिस दिन देश के अंदर जनता ने थाली बजाई और दीप जलाया। हम सब जानते हैं कि अंधेरे में गुजरते बच्चे को उसके बाप की उंगली सहारा देती है। कोई संकट आएगा, तो ठीक है, हो सकता है वह सामना नहीं करे, लेकिन उस बच्चे को भरोसा होता है कि उसका गार्जियन, उसका पिता, उसका अभिभावक उसकी रक्षा करने के लिए साथ चल रहा है। वहीं हमने इन माध्यमों के माध्यम से देश के सामने देश की चिती को जाग्रत करने का काम किया कि आओ, हम सब मिलकर इस कोरोना की वैश्विक महामारी से लड़ें और उसी का नतीजा है कि दुनिया के अन्य देशों के संसद सत्र, पार्लियामेंट ने एक-दो दिन का रस्मी कार्यक्रम करके उन्होंने निभा दिया। लेकिन आज पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, भारत की पार्लियामेंट 18 दिन की लगातार चर्चा के लिए बैठी है, ताकि हम आने वाले सुनहरे भारत के भविष्य का निर्माण रख सकें और जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा है, वह हम आने वाली पीढ़ियों को दे सकें। इस दृष्टि से इस डिमांड फॉर ग्रांट्स की महत्ता बढ़ जाती है।

मैं इसलिए भी यहां कहना चाहता हूं कि कल का जो दिन गया है, जहां वह हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का जन्म दिवस था, वहीं वह विश्वकर्मा दिवस भी था। विश्वकर्मा दिवस की चर्चा मैं इसलिए करता हूं कि जब माननीय दत्तोपन्त ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ ने उसको 'श्रम शक्ति दिवस' घोषित किया था, तो देश के बहुत सारे राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों के बीच खलबली मच गई कि यह विश्वकर्मा कौन आया? यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि हमने अर्थशास्त्र की प्राचीन विद्या को नहीं पहचाना।

(2050/NK/SPR)

अगर हमने कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा होता तो मालूम होता, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 114 बार अपने पूर्ववर्ती अर्थशास्त्री के निर्देशों और संदर्भों का उल्लेख किया गया है। हमारी अर्थशास्त्र की

भूमिका विदेश से नहीं आती है, हमारी इसी मिट्टी से जन्मती है। मैं यह बताना चाहूंगा, अगर आपको हिन्दू अर्थशास्त्र के बारे में जानना है, तो शुक्र नीति को जानिए, जिसमें स्वयं रोजगार और वेतन पद्धति की चर्चा है, विश्वकर्मा दिवस स्वयं रोजगार जिसको हम सैल्फ एम्पलायमेंट कहते हैं, की धारणा को मजबूती देता है, उसी की ओर से विभिन्न माध्यमों से देश के युवाओं को लोन देने और बाकी का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय जी का समय की ओर संकेत है। हमारे अर्थशास्त्र का अर्थ है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वसमावेशक मानवता की दीनदयाल जी की दृष्टि है। उस दृष्टि में भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता यह है कि वह संपूर्ण जीवन और संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करता है। उसका दृष्टिकोण एकात्मकवादी अर्थात् इंटीग्रेटेड होता है। मैं इसे इसलिए कोट कर रहा हूं कि हम संसद में टुकड़े-टुकड़े भारत का विचार करते हैं। हम संसद में विचार करते समय विभिन्न राज्यों के प्रति भेदभाव की चर्चा करते हैं। हम भूल जाते हैं कि आजादी के बाद की सरकारों ने अगर पूरे भारत का एक दृष्टि से विचार किया होता है तो आज ईस्ट ऑफ कानपुर और वेस्ट ऑफ कानपुर के बीच जो खेती की खाई खड़ी है, वह खाई खड़ी नहीं होती और पूरा भारत विकसित होता। इस दृष्टि से इस डिमांड ऑफ ग्रांट्स की आज आवश्यकता पड़ गई।

मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। प्रतिपक्ष के माध्यम से बार-बार कहा जाता है क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था में इसके माध्यम से भी हमने खेती-किसानी के लिए राशि दिया है। यह बार-बार कहा जाता है कि हम हरित क्रांति लाए थे। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि आप ही के समय में 1986 में डॉक्टर एस.के.राय भारत सरकार में ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी की किताब लिखी थी, उन्होंने एक चैप्टर लिखा है, `How Green was Revolution'? मैं उसे संक्षेप में पढ़ना चाहता हूं। मैं उनको कोट करना चाहता हूं `If the Green Revolution cannot be taken to the rest of India, the prospect for India's agriculture is not very bright. We have made a certain amount for the progress but this is still inadequate'. मैं इन बातों को कहते हुए एक बात और कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि हमें डिमांड ऑफ ग्रांट्स के माध्यम से काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष की जो चिंता है, आपको लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन काम, हमारी इच्छा, हमारी आवश्यकता है और अर्थ उसको पूरा करने का साधन है, धर्म तय करता है कि देश के लिए क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है। इसके आधार पर देश परमवैभव को प्राप्त करता है। जिसको हम मोक्ष कहते हैं, यह उस दिशा की ओर चलने का रास्ता है। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी ने इकोनॉमिक्स के साथ-साथ ऐथिक्स, एजुकेशन और इकोलॉजी का इंटीग्रेटेड एप्रोच अपनाया है। यह आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को आने वाले समय में पूरा करेगा, इतनी बात निवेदन करके इसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। वन्देमातरम्

(इति)

2054 hours

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Hon. Chairperson, I rise to speak on this Bill. At this moment, the only defence against China, the only pill for COVID-19, and the only solution for employment is the economy. Unfortunately, the Prime Minister has ignored this advice. This is precisely the reason why India has seen the deepest reduction in GDP, – minus 23.4 per cent. It is the only country in the world where the COVID-19 infection curve has not flattened. And the reason why the Prime Minister's statement on the Indo-China border is similar to the position of the Chinese government. This is a Government whose sole agenda is to protect the image of one man.

(2055/UB/SK)

It is unfortunate that while Parliament is discussing COVID-19, the state of economy, and the integrity of our territory, the Prime Minister chooses to be absent from Parliament. He is busy preparing his election speeches for Bihar or taking a picture with a peacock.

Whenever Rahul Gandhi ji has advised the BJP Government, he was found to be true. On 12th February, he spoke of COVID-19, he was right. In March, he spoke of economic tsunami, he was right. He pointed at the presence of the Chinese in the Galwan Valley, he was right. History will remember Prime Minister Modi having wasted his mandate while Congress and Rahul Gandhi ji continued to raise issues of national importance.

In India right now, we have had the strictest lockdown, the smallest fiscal stimulus, the greatest GDP crash, and the highest inflation rate. The last eleven days have seen a rise of 13 lakh cases of COVID-19. India has the most COVID-19 deaths reported in the world between 1st September and 15th September at 16,307. The Rs. 20 lakh crore stimulus package announced by the BJP Government is only a diversion to manage the news headlines.

The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana gives only Rs. 1000 per person, the Jan Dhan Yojana gives only Rs. 500 per month and the Migrant Labourer Grain Package gives 5kg of grains per month. Rs. 500 per month, Rs. 1000 per month and 5kg of grains per month do not even qualify as basic humanitarian relief to a nation that is struggling, let alone being described as a stimulus package.

The burden on the poor has increased with the rise in petrol and diesel prices having crossed Rs. 75. The migrant labourers were unable to pay their rent and still find themselves jobless. Therefore, the BJP Government should follow the advice of the Congress Party and Rahul Gandhi ji and give Rs. 7,500 to the poorest of the poor families.

I am afraid that today also, the hon. Finance Minister will only shift the accountability to God, global markets, and the Governments of the past. Hon. Finance Minister, it is not God who is to be blamed but your Government's focus on following Godse. Even now the Finance Ministry is only focused on catchy words like 'Atmanirbhar Bharat' which is only a rehashed version of 'Make In India'.

Meanwhile, the States are increasingly worried about the rising number of COVID-19 cases and the shortage of emergency medical infrastructure like ICU beds and ventilators. On 23rd April, it was pointed out that States like UP, Bihar, Assam and Madhya Pradesh faced grave shortages of isolation beds, ventilators, and ICU beds; yet after five months, the situation has not changed. The Ministry of Health in Assam says that COVID-19 cases are going out of control and, there is shortage of ICU beds. Who will answer the families who have to run from hospital to hospital searching for ICU beds and ventilators? The State, the Centre, the Health Ministry or the Finance Ministry? Have the *dias*, the *thalis* and the *talis* helped the 84,000 families who have lost their loved ones? Instead of helping the States at the time of need, the Finance Ministry is shifting additional burden of the revenue shortfall in GST to the States. The hon. Finance Minister simply cannot abdicate her legal and moral responsibility to the States.

Instead of asking the States to borrow, the Central Government should relax the norms under FRBM, borrow from the global market, and take international assistance from IMF, World Bank and ADB. The hon. Finance Minister must reconsider her options because what is at stake are the salaries of thousands of State Government employees, teachers, medical staff, the funds for rural roads and hospitals, and the money needed for scholarships of SC/ST students. You are unable to compensate the States, but instead you have the money to spend Rs. 20,000 crore on an extravagant Central Vista Project. You want to add to the financial burden of the States but you reduce the tax rate for your corporate friends and reduce their financial burden. What is the revenue

loss to the Centre after the reduction in corporate tax rate? What is the subsequent private sector investment after the reduction in corporate tax rate? Do you have the data with you?

This Bill completely misses the needs of the States, especially my home State of Assam. People of my State have rejected the overdependence on privatisation, the sale of the Lok Priya Gopinath Bordoloi Airport, our oil fields, and the proposal of sale of Hindustan Paper Mills in Cachar and Nagaon. The students want a research fund in universities; the students want a second Sainik School in Golaghat. Our State wants the Union Ministers who give attention to our problems. The Jal Shakti Minister did not even visit the State during floods. He was busy trying to pull down the Government in Rajasthan. The Road Transport Minister, Nitin Gadkari ji, inaugurated two bridges over Brahmaputra for which the DPR had not been prepared. The oil fields in Baghjan is still on fire.

I am concluding, hon. Chairperson. For all the reasons I have cited in my speech, I regret to reach my conclusion. Hon. Finance Minister, while I hold you in high personal esteem, I submit my demand to the Union Finance Minister of India. I request you to step aside for the sake of unemployed youth, for the sake of starving labourers, and for the sake of distressed farmers. Please step aside.

(2100/KMR/MK)

Not that I recommend another person from the Union Cabinet, the Cabinet simply lacks the necessary talent, but the responsibility of putting India back on the economic growth track cannot be yours alone. It needs to be a collective effort. I propose the creation of an Emergency Economic and Financial Recovery Council, similar to the GST Council, a council of State Finance Ministers with past Union Finance Ministers as members, Ministers such as Shri Yashwant Singh and Shri P. Chidambaram, to be steered by the person who led India out of the 2008-09 global financial crisis, the former Prime Minister Dr. Manmohan Singh.

I say to Prime Minister Modi that the gospel of one man, one saviour has completely failed. Time has come to rise above the image and think about the nation. We need a bold effort, through collective effort, through consensus and dialogue. That is the Indian way. That is how we protect our youths from frustration. That is how we protect our small business owners from depression. That is how we protect our farmers and labourers from suicide. And most importantly, that is how we protect the future of our children.

Thank you. Jai Hind!

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Hon. Members, there are ten more Members who want to take part in the discussion. If they take three minutes each, I may extend the House till 10 p.m. which includes hon. Minister's reply. Does the House agree?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

2101 hours

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to express my views on the Supplementary Demands and the Excess Grants placed before the House by the hon. Finance Minister.

Sir, the COVID-19 pandemic is a shock that not only shattered our economy but also affected consumer sentiment in an unprecedented manner. The negative 24 per cent GDP growth year on year of the first quarter of this fiscal indicates the recession that India has to pass through this year and in subsequent years, if the corrective interventions are not made. This indicates that Rs.8.5 trillion of national income, or about USD 115 billion at the current exchange rate, has gone up in smoke. There is no doubt that it is due to the unprecedented suspension of economic activity. But even after the lockdown, the situation is not so bright either. So, we have to focus on this.

Sir, there are indications coming from the RBI that there would be a second stimulus. I wish that this stimulus would be focused entirely on how to make money available to individual citizens of this country so that they will spend the money, create demand, and the wheel of the economy starts rolling.

Sir, we are all facing the same storm but we are all not in the same boat. Some businesses - such as travel, tourism, construction, MSMEs across verticals - have suffered much more while others - such as technology, telecom, pharma, healthcare and e-commerce - have prospered. For the middle class and the rich, the pandemic has been an inconvenience. But for the poor, including the migrant labour and the daily wage workers, it has become a matter of life and death. The financial support and the stimulus package needs to be directed to support the most vulnerable people and the most vulnerable businesses. I wish and hope that the second stimulus will come very soon.

Sir, I request the hon. Finance Minister to release the pending GST dues to the tune of Rs.3600 crore to Andhra Pradesh, and also the Finance Commission grants immediately. I also request the hon. Finance Minister to release the pending bills of Rs.3200 crore towards Polavaram project. I am making this request because the financial position of Andhra Pradesh is on the verge of collapse with nearly five per cent fiscal deficit, revenue deficit shooting up to 2.5 per cent in 2019-20 against the target of 0.16 per cent, borrowings already pegged for this financial year at Rs.60,250 crore, and there was a 20

per cent increase in the fiscal deficit. Sir, I am giving these statistics from the Budget papers of Andhra Pradesh which indicate the pathetic financial position. That is the reason why I am requesting you to help my State.

Sir, 29 commitments were made in the Andhra Pradesh Reorganisation Act. None of them has been fully implemented and no funds have been allotted to this including for SCS.

(2105/SNT/YSH)

Sir, instead of focusing on vindictive politics, YSRCP's priorities have become very clear. They are not talking about COVID-19 situation, they are not talking about the economy, they are trying to cover up their failures and diverting the attention and misleading the House.

When we look at classifying the expenditure into critical, essential and desirable, MPLAD Funds certainly fall under critical and they should not be touched and we should not be denied of that opportunity.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): MPLADS has already been discussed.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, my last point is this. The AP Government has been in power for 16 months. They have taken a vindictive approach right from the beginning. During the 16 months of investigation, they have been unable to do anything. They are now insisting that cases should be handed over to the CBI to ensure fair and unbiased investigation with credibility. Is it not an admission of their own failure and their own inability to provide a fair and unbiased investigation with credibility? More than 80 cases in the High Court and Supreme Court have gone against the YSRCP Government. Instead of being ashamed of this record, they have the audacity to cast aspersions on the courts and the judges of this country. They are proving again that they have no respect for rule of law nor the Judiciary. What about the CBI cases pending against the prisoners of AP for more than ten years?

With these observations, I support the Demands for Grants. Thank you, Sir.

(ends)

2106 hours

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

Sir, the simple theory of scientific financial management is using the available funds effectively, efficiently and transparently. It is true that global economy has its own shock due to COVID-19. India will also have its impact. But even before COVID-19, India's financial shape was poor because of the disastrous demonetization policy, rushed implementation of GST, and lack of sense in prioritization of spending of the available wealth.

At this juncture, we have to examine/introspect where have we stumbled in managing the COVID-19 situation; what have we missed; and what the Government did. When WHO and other countries were spreading the message of social distancing, what was happening on the Indian streets? Throughout Indian streets, the migrant labourers were moving like a flow of ferocious river. They were really deep-rooted with sorrows and difficulties. We have witnessed that. Why? It was because of the midnight declaration of lockdown. That was the root cause for all those kinds of things.

Sir, I would like to say one more thing. What exactly should be the wise leadership quality during the crisis? I believe, whether it is pandemic, or disastrous kind of thing, or health emergency, the approach should be of compassion, kindness and unity. You are missing that. What have we witnessed? What should we do? Developing the feeling of togetherness is the need of the hour. We all know that Government was really opting for this kind of dividing tendency. They were creating dividing methods on the grounds of caste, creed, and religion.

Sir, I would like to say with painful feeling what you have succeeded. You are all claiming, and tall claims were presented here, that under Prime Minister Narendra Modi, we are making wonders. But what really happened? What have you succeeded in? You have succeeded in scapegoating the poor section of the society, that is, SCs, STs, and minorities.

I have two documents in my hands. One is the report of the Delhi Minorities Commission Fact-Finding Committee. The other one is the Amnesty International Report. It tells the story of blood and tears of the minorities in this

country. We all know that witch hunting is going on in this land ruthlessly. Various laws namely, UAPA, NSA, and sedition charges are going on in this country.

Sir, I would like to tell you one thing. Kindly note three latest judgements. One judgement is by the Allahabad High Court about Kafeel Khan. The second one is by the Aurangabad Bench of Mumbai High Court.

HON. CHAIRPERSON: Basheer Ji, please conclude.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Yes, Sir, I am concluding. And the latest one is the Supreme Court judgement on Jihad.

(2110/GM/RPS)

All these things are going on. Instead of keeping the Indian people together and developing the feeling of togetherness, you are trying to divide the people. I want to say only one thing. Money is not the criteria in deciding things; mentality should also be there. Unfortunately, you do not have that mentality. You do not believe in that mentality. That is a bad thing. I would like to say one more thing about transparency. What about this PM CARES Fund? Why is it not transparent? What exactly are you hiding? Why are you not putting it within the purview of Right to Information Act? Do not hide things; be transparent; be straightforward; believe in truthfulness. Towards the end, I would like to tell you that your mentality towards India should change. I want to say only this much. With these few words, I conclude.

(ends)

2111 hours

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Hon. Chairperson Sir, I would like to register my dissent on Supplementary Demands for Grants for 2020-21 presented by the hon. Finance Minister. Why should I support the Demands for Grants for police? Though additional amount is not demanded, the police force is using it for targeting its political opponents like the *… (Not recorded)* and many intellectuals and leaders of Opposition parties including Congress for opposing the Government on CAA and NRC issues and has put many behind the bars, without even bail and charging with UAPA. Every person in this country has the democratic right to criticize the Government and its policies. You are trying to put all of them behind bars for criticizing the Government. I urge upon this Government to withdraw the move to register the case against these people and announce a judicial inquiry in connection with the Delhi riots.

Secondly, why should I support the Demands for Grants for Civil Aviation, Agriculture and others under items no. 1 and 8 in the given Schedule. The Government has already written off the land, sea and sky of this country to *… (Not recorded)* For that, the laws of land, be it related to agriculture, labour, banking, seaports or airports, are supported to suit the corporate agenda.

Thirdly, how is this Government handling the COVID-19 situation? This Government tries to wash its hands off the mismanagement of the economy by covering up its failure behind COVID-19, which is an 'act of God' according to our Finance Minister. There was news in a newspaper that the Finance Minister said this. This Government was clueless in handling the COVID-19 pandemic, unilaterally announcing nationwide lockdown without any planning or consultation and forcing millions of poor labourers of this country jobless. Now the Government says it has no data on how many migrant labourers lost their lives while desperately trying to reach their homes during the lockdown. This mishap is not an 'act of God' but an act of mismanagement by the Modi Government.

Coming to the Finance, the Government cannot shy away from the bitter truth staring at it. The GDP which contracted by 24 per cent in the first quarter of 2020-21, is the lowest in 24 years. We are facing the highest unemployment rates in recent decades and there is no let-up in farmers' suicides in this country.

Millions of this country are desperate to get a job. There is an undeclared prohibition about filling up of vacancies in all Central Government departments and PSUs in the country. In each and every step it has taken in the sphere of economy, the Government has failed to solve the pressing needs of the common people. So, I request the Government to raise the working days under MGNREGA to 200 days a year. Without giving statutory compensation under GST regime and denying the benefit of the tax exemption to State CMDRFs, the Government is literally crunching the States' finances and they are finding it difficult to make both ends meet in the wake of the COVID-19 pandemic. Even worse, this Government has not done anything substantial to the States from the PMNRF and PM CARES Fund.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please conclude now.

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, I come to the Demands for Grants for External Affairs under item no. 26. What is the state of affairs at our borders?

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Shrimati Anupriya Patel.

(2115/IND/RK)

2115 बजे

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश की गई 2.35 लाख करोड़ रुपये की अनुदानों की अनुपूरक मांग के समर्थन में अपने विचार रखना चाहती हूं, जिसमें 1.66 करोड़ रुपये की व्यवस्था के लिए संसद की अनुमति ली जा रही है। इसमें 68868 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था है, वह सरकारी खर्चों में कटौती के माध्यम से की जाएगी। इस समय सरकार की दो ही प्राथमिकताएं हैं – पहली कोविड-19 के प्रबंधन को देखना और दूसरी इसके साथ ही देश की आर्थिक गतिविधियों को पुन: सुदृढ़ करना। मैं बताना चाहती हूं कि सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान गरीब वर्ग की तमाम आवश्यकताओं के लिए चाहे रोजगार सृजन हो, चाहे भोजन हो या अन्य आवश्यकताएं हों, उनकी व्यापक चिंता करते हुए तमाम प्रयास किए हैं, जिसमें 80 करोड़ लोगों को साल के अंत तक मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था की गई है। महिला जनधन खाताधारकों के खाते में कैश ट्रांसफर की व्यवस्था की गई है और 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर एमएसएमई के सुदृढ़ीकरण को लेकर 15 हजार रुपये तक का वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए उनके पीएफ अंशदान को सरकार द्वारा दिए जाने की घोषणा की गई है। तमाम किस्म के ऋण की ईएमआई के भुगतान की स्थिति को टालना और यहां तक कि माननीय राष्ट्रपति जी से लेकर हमारे माननीय प्रधान मंत्री और हमारे मंत्रिगण तथा सांसदों के द्वारा अपने वेतन से 30 प्रतिशत का योगदान दिया है, जो इस कोरोना महामारी में हमारे देश के लोगों के लिए एक साथ खड़े होने के लिए और सभी को मिलकर एक साथ कोरोना महामारी का मुकाबला करने में सहायक होगा।

महोदय, अनुपूरक मांगों के अंतर्गत मनरेगा कार्यक्रम के लिए चालीस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो समय की मांग को देखते हुए एक बहुत ही परिपक्व व्यवस्था है, क्योंकि इस कोरोना आपदा में जिस तरीके से मजदूरों का विभिन्न राज्यों से अपने गृह राज्यों की ओर पलायन हुआ है और तमाम आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई हैं, उनके सामने रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है, ऐसे में मनरेगा सबसे बड़े सेफ्टी नेट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि जहां रोजगार के तमाम अवसर सीमित हैं, वहीं मनरेगा रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं। सरकार ने इससे पहले मनरेगा के तहत जो वेजेज दिए जाते थे, उन्हें 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये करने का काम किया है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इसमें कुछ और वृद्धि की जाए और इसके साथ ही मनरेगा मजदूरों के लिए हर गांव के अंतर्गत जो कार्य योजनाएं हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि मनरेगा मजदूरों का जो भुगतान है, वह समय पर हो। इसके साथ ही जो एनुअल वर्क गारंटी है, उसे सौ दिन से बढ़ाकर दो सौ दिनों तक ले जाया जाए। जितनी भी कोविड-19 सेफ्टी गाइडलाइन्स हैं, उनका अनुपालन मनरेगा की साइट्स में काम करने वाले वर्कर्स के लिए किया जाए। उनके लिए पानी, साबुन, सैनेटाइजर की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। अनुपूरक मांगों के तहत 14231.96 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था है, वह देश में स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए की गई है। इसके अंतर्गत 5915 करोड़ रुपये महामारी के प्रबंधन के उद्देश्य से और 2475 करोड़ रुपये आईसीएमआर को शोध

कार्य के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं इस संबंध में कहना चाहती हूं कि आज हमारे देश में कोरोना मरीजों की संख्या 52 लाख से अधिक हो चुकी है और प्रतिदिन एक लाख का आंकड़ा सामने आ रहा है। सरकार ने धीरे-धीरे टैस्टिंग की संख्या बढ़ाई है, नए टैस्टिंग लैब्स स्थापित किए हैं और आज की तारीख में हम रोज लगभग 10 लाख टैस्ट कर रहे हैं और 6 करोड़ के करीब टैस्ट कर चुके हैं। यहां तक कि पीएम फंड से वेंटिलेटर्स की भी बहुत बड़ी संख्या में व्यवस्था की गई है। यहां यह ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा जो सरकारी ढांचा है, वह बड़े शहरों में तो जैसे-तैसे काम कर रहा है, लेकिन जो हमारे छोटे शहर या कस्बे हैं या ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां स्वास्थ्य का ढांचा काफी अपर्याप्त है और विशेष रूप से जो आक्सीजन बैड्स हैं, उनकी कमी देखने को मिल रही है।

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please conclude. There are other Members to speak.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): सभापति महोदय, आप मुझे केवल एक-दो मिनट का समय और दीजिए।

महोदय, यदि किसी भी मरीज को अस्पताल में दाखिल करना है या किसी भी मरीज को कोविड केयर सैंटर में आइसोलेट करना है, इसमें बहुत बड़ा डिफाइनिंग पैरामीटर होता है कि उसके ब्लड में आक्सीजन का सैचुरेशन लेवल क्या है, जो सामान्यत: 95 से 99 परसेंट तक होता है और यदि लम्बे समय के लिए इससे नीचे लेवल चला जाता है, तो उस मरीज को क्रिटिकल केयर की आवश्यकता होती है और वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। लेकिन जो माइल्ड और मोडरेट केसेज होते हैं, उन्हें हम आक्सीजन सप्लाई बैड से मैनेज कर सकते हैं, इसलिए आक्सीजन बैड्स की कमी इस देश में महसूस की जा रही है, उसके लिए प्रबंध करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमारे बैड्स पाइप आक्सीजन सप्लाई के साथ या आक्सीजन कंसेंट्रेटर के साथ या आक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था के साथ हों।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): सभापति महोदय, आप मुझे बोलने दीजिए। I have not even covered two points, Sir. हमें ये व्यवस्थाएं छोटे शहरों में, कस्बों में और ग्रामीण इलाकों में तेजी से करने की आवश्यकता है।

(2120/RAJ/PS)

अध्यक्ष जी, जहां तक शोध कार्य की बात है, तो वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि यह वर्ष 2021 के प्रथम क्वार्टर तक आने की संभावना है। हम सभी उससे काफी उम्मीद लगाए हुए हैं। हमारे देश में वैक्सीन्स के डिफरेंट फेजेज के ट्रायल भी चल रहे हैं। अभी हम यह मान लेते हैं कि अगर पहले क्वार्टर में वैक्सीन आ भी जाती है तो लोगों तक वैक्सीन

पहुंचने में लगभग एक साल का समय लगेगा, तब तक इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना बहुत ही आवश्यक है।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please conclude.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक राज्यों को 46,602 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है।…(व्यवधान) जिसमें जीएसटी की क्षतिपूर्ति नहीं होने से वित्तीय तौर पर परेशान राज्यों को भी इससे राहत मिलेगी।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

Hon. Member, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): I have just two more points. Let me just finish it. अनुपूरक मांगों के तहत 33,771 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री जन-धन योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के खाते में कैश ट्रांसफर के लिए भी मांगे गए हैं। जन-धन योजना के तहत अब तक 40 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें से 64 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और लगभग 55 प्रतिशत महिलाओं के खाते खोले गए हैं। इस कोरोना आपदा के दौरान जिस तरह से इन जन-धन खातों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली पेंशन, खाद्यान्न सब्सिडी या गैस सब्सिडी, ये सभी कुछ जनता तक पहुंचाई गई हैं, उसमें जन-धन खाते वरदान के रूप में साबित हुए हैं। …(व्यवधान) लेकिन इसमें लास्ट माइल डिलिवरी लूप होल्स हैं।…(व्यवधान) अनऑपरेटिंग अकाउंट्स हैं, हमें उन्हें भी देखने की जरूरत है।…(व्यवधान)

अनुपूरक मांगों में सरकारी बैंकों के पूंजी आधार के लिए भी 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।…(व्यवधान) हमारी बैंकों को आज की डेट में, जो भी उनके कर्जदार हैं, वे पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, इसलिए बैंकों के एनएपीएज बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस कदम से बैंकों पर जो वित्तीय दबाव है, वह कम होगा और उन्हें राहत मिलेगी।

मैं इतना ही कह कर अपनी बात को खत्म करूंगी कि कुल मिला कर आज कोरोना के कारण हमारी अर्थव्यवस्था के जो हालात हैं, वह हमारे सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में है।

(इति)

(pp. 335-A)

2122 hours

SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the First Batch of the Supplementary Demands for Grants – 2020-21 and the Demands for Excess Grants relating to 2016-17.

I would like to thank the hon. Minister of Finance, Shrimati Nirmala Sitharaman Ji and the Minister of State, Shri Anurag Singh Thakur Ji. The First Batch of the Supplementary Demands for Grants – 2020-21 includes 54 Grants and one Appropriation for a gross additional expenditure of Rs. 2,35,852 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs. 1,66,983 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries and Departments or by enhanced receipts and recoveries aggregate to Rs. 68,868 crore.

सर, मैं कुछ लोकल डिमांड्स मराठी में करना चाहूंगा।

*Hon. Chairperson, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on the first batch of the supplementary demands for grants 2020-2021.

Sir, I would like to raise some of the demands in my mother tongue Marathi. We have been discussing the Demands for Grants, since afternoon and Opposition parties are repeatedly asking for the data. But, they refused to understand that we have transferred money to the bank accounts of around 17 crore farmers under PM Kisan Scheme. We are also giving monetary benefits to the widows through online mode. We are transferring money to the accounts of senior citizens, physically challenged persons and also giving scholarships to the students. Atalji once said that nobody can claim greatness without having greater vision and thinking.

Through 'one nation, one ration card', we are providing timely help to the migrant labourers for their livelihood. Hon. Sir, for MSME sector, our Government has increased its budget to the tune of Rs.3 lakh crore with Government guarantee. It has helped 85 lakh enterprises which create crores of jobs.

---

*Original in Marathi.

(pp. 335-B)

Our Government is helping not only the industry but also the entrepreneur for creation of employment. For PM Matsya Sampada Yojana, we have provided Rs.1 lakh crore and for vaccination of cattles we have provided Rs.14000 crore.

We are also infusing funds in Bee-keeping for creating employment for women. Our hon. Prime Minister Narendra Modiji is creating a 'New India' through the development of Ports, National Highways, and other infrastructure projects.

Respected Sir, when we amended SEZ policy they opposed it, and under Textile Park Policy, they only took care of Real Estate Developers. But we are doing it in public interest.

India is the first country where corporate tax has been reduced by 15%. They had also opposed International Finance Service Centre Bill and still they claim that no FDI is coming to India. We are also making policies for protection of farmers so that they can get their dues without hassles. So, the Opposition need to change their negative thinking and vision.

This contract farming is going to help farmers to earn more money and hence I congratulate and support it.

Sir, lastly I would like to raise three demands. I hail from Northern Maharashtra and in my constituency, there is a Lower Taptee Project which has not been completed for the last 25 years. If it is covered under PM Krishi Sinchai Yojana, around 7 talukas would get benefited. On Girna river, it is proposed to construct 7 small dams by using Baloon Wave Innovative Technology. This project should be sanctioned. For the overall development of Girna Ravine Technology, on Bodhre Dhule stretch of NH-211, largest tunnel is to be constructed near Autram Ghat, but this project is still pending. I would urge upon the Government that these important projects should be given priority and completed as early as possible. With these words, I support the Supplementary Demand for Grants. Thank you.

(ends)

(2125/VB/RC)

2126 बजे

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): The Supplementary Demands for Grants have nothing for the unemployed and the poor. It has nothing for Bihar which is suffering the most. Hon. Prime Minister is busy announcing various schemes for Bihar, इलेक्शन को देखते हुए, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि सवा लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ, जिसकी घोषणा उन्होंने पिछले इलेक्शन में की थी। पिछले चंद महीनों में जब पूरा हिन्दुस्तान तबाह था, परेशान था, हंग्री था, तब आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर बनो। इसका मतलब यह है कि अपनी सुरक्षा, अपना ख्याल खुद रखो। यह बड़ी अफसोस की बात है। अगर आज बिहार सबसे बदहाल है, तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, जो पिछले 15 साल से वहाँ पर हुकूमत कर रही है।

सर, मैं बिहार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कोविड-19 में 0.5 परसेंट डॉक्टर्स की मौतें हुई हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार में उनकी तादाद 4.5 परसेंट है। वह इसलिए है कि वहाँ अस्पताल सबसे कम हैं, मेडिकल कॉलेज सबसे कम हैं। बिहार में करीब 16 मेडिकल कॉलेजेज हैं and 780 seats are there in comparison to 532 colleges and 77000 seats in India.

सर, बड़े अफसोस की बात यह है कि फेज़ वन, टू और थ्री में सरकार ने 157 मेडिकल कॉलेजेज बनाने की घोषणा की है, जिनमें से सिर्फ सात ही बिहार में हैं, जबकि सौ होने चाहिए। मैंने आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की थी, किशनगंज में दो सौ एकड़ जमीन है, वहाँ पर आप एम्स का एक सेन्टर खोलिए। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही, एएमयू सेन्टर के लिए हमारी यूपीए चेयरपर्सन ने वर्ष 2013 में 137 करोड़ रुपए एलॉट किए थे। लेकिन अफसोस की बात है कि सात वर्षों में अभी तक उसके लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपके माध्यम से मेरी गुजारिश है कि आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर बाकी रकम भी दिलाएं।

अगर एक्सप्रेस हाइवेज़ को देखा जाए, तो हमारे यहाँ नेशनल हाइवेज 5,358 किलोमीटर्स हैं और पूरे हिन्दुस्तान में यह एक लाख बयालीस हजार एक सौ बासठ किलोमीटर्स हैं। लगभग 15 हजार किलोमीटर्स से ज्यादा हाइवेज़ हिन्दुस्तान में बन रहे हैं, लेकिन उनमें से बिहार के हिस्से में 21.5 किलोमीटर ही है। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या बिहार हिन्दुस्तान का हिस्सा है या बिहार हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है? हमें हर चीज में आप पीछे ठेल रहे हैं।

आपको यह बताते हुए और अफसोस होता है कि एग्रीकल्चर में 65 लाख मीट्रिक टन धान प्रोड्यूस होता है, लेकिन 13.5 लाख मीट्रिक टन केवल 1,815 रुपए के रेट पर खरीदा जा रहा है। वहाँ लगभग 35 लाख मीट्रिक टन मक्के की पैदाइश है, लेकिन एक क्विंटल मक्का भी सरकार ने नहीं खरीदा। वहाँ पर हमारा रेट 1850 रुपए है, लेकिन मजबूरन किसानों को सात-आठ सौ रुपए में ही बेचना पड़ रहा है।

(2130/PC/SNB)

सर, आधा मिनट और दीजिए। पिछले 30 सालों से जो सरकारें वहां पर हैं, वे एक साजिश के जरिए बिहार को कमज़ोर रखना चाहती हूं। बिहार की आबादी हिन्दुस्तान की लगभग दस परसेंट है। अगर बिहार पीछे रहेगा तो हिन्दुस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। धन्यवाद।

(इति)

2131 बजे

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे सप्लिमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया है। मैं इस वर्ष 2020-21 के अनुदान बजट के पक्ष में अपनी बात को रखना चाहूंगा। मेरे से पहले सभी सदस्यों ने इस अनुपूरक मांगों के लिए कहा है, लेकिन मैं इसमें इतना कहना चाहूंगा कि 2 लाख 36 हजार करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग, जो देश की वित्त मंत्री जी ने रखी हैं, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए, स्वास्थ्य विभाग में स्टार्ट-अप कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए इसमें लिया गया है।

पिछले सात महीनों से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। जब जनवरी में यह महामारी आई थी, तब से लेकर अब तक इस देश में 1,717 लैब्स केन्द्र सरकार ने बनाई हैं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना बड़ा काम देश में हुआ है। मैं देश के प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस स्थिति को काबू में रख के बहुत सराहनीय काम किया है।

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please conclude.

… (*Interruptions*)

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सर, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है। एक मिनट में ही मुझे खत्म करने के लिए कह रहे हैं? आप घंटी मत बजाइए, मैं जल्दी से खत्म कर दूंगा।

सभापति महोदय, देश के प्रधान मंत्री जी ने किसान, गरीब, श्रमिक, पिछड़े वर्ग के लिए गरीब कल्याण योजनाओं की शुरूआत की है। एक साल के अंदर केन्द्र सरकार द्वारा एक मजदूर का फ्री चैक-अप कराना बहुत बड़ी बात है। जो मजदूरी 182 रुपये थी, उसको भी 202 रुपये माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है। …(व्यवधान) मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

सर, मैं एक सुझाव देकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। …(व्यवधान) मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूं। राजस्थान प्रदेश में टिड्ढी दल आया था। केन्द्र सरकार ने यहां खेत-खलिहान और मजदूरों के लिए 68 करोड़ रुपये के करीब जारी किए हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार ने अभी तक वहां का सर्वे करवा कर केन्द्र सरकार को रिपोर्ट नहीं भेजी है। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि मैं पेट्रोल और डीज़ल को जीएसटी में लाने की वकालत करूंगा। धन्यवाद।

(इति)

2133 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Supplementary Demands for Grants.

This is the first batch of Supplementary Demands for Grants for the financial year 2020-21. The amount involved is around 2.36 lakh crore, out of which the cash outgo is Rs. 1,66,983.91 crore. The first clarification that I would like to seek is that it is being stated that there are 63 new entries for which stock and provision of Rs. 1 lakh crore has already been earmarked. I would like to seek this clarification about these 63 new entries, or new instruments of service.

Out of the total amount of Supplementary Demands for Grants, the major amounts are as follows. A sum of Rs. 46,602 crore is towards Revenue Deficit Grant. I would like to seek a clarification from the hon. Finance Minister that whether the Government did not foresee this expenditure. It is because the Revenue Deficit Grant is a grant which is allowable or is an entitlement for the States. I would like to know whether the Government did not foresee this expenditure of Rs. 46,602 crore as Revenue Deficit Grant. In short, the additional expenditure of Rs. 2.36 lakh crore will constitute 0.9 per cent of the total GDP in the current financial year.

Sir, coming to the macro economic factors, I would like to make a very important point and that is about the Gross Domestic Product (GDP) for the growth rate of the country. The state of economy of India is alarming. Twenty-four per cent contraction in the economic size is a big challenge for the country and we have to face it. Yes, we can understand that one of the reasons for the economic crisis is the COVID-19 pandemic situation.

(2135/SRG/SPS)

But the decline of the economic growth had started since long. I would like to cite an example about pre-COVID pandemic. For the financial year 2019-20, you may kindly see that during the first quarter, GDP was 5.2 per cent; during the second quarter, it was 4.4 per cent; during the third quarter it was 4.1 per cent; and during the fourth quarter it was 3.1 per cent. So, even before this pandemic in India, the economic growth was declining like anything. Gradual decline was there. So, the Indian economy was in deep trouble even before the

pandemic induced lockdown because the lockdown began on 21st March 2020. …(*Interruptions*)

I will come to another point about the fiscal deficit and then I will conclude. I am not going into the statistical figures. The fiscal deficit is going to touch seven per cent of GDP in financial year 2020-21 and the reason is also very clear. Now, two per cent of the GDP is being given to all the State Governments to borrow. If that also is allowed, then definitely the deficit could reach to around 12 per cent of GDP and that will be another alarming situation. …(*Interruptions*).

I am on my last point. Give me a minute. …(*Interruptions*). Regarding the Atmanirbhar Bharat Abhiyan scheme, I appreciate the scheme. When the hon. Finance Minister and the State Finance Minister were declaring the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, the entire people of the country were before the television to see what was happening and what was being announced. Rs. 2 lakh crore has been announced for the MSME. …(*Interruptions*). Sir, this is regarding the cashew industry …(*Interruptions*) one second …(*Interruptions*); Rs. 2 lakh crore is being allocated for MSME as credit facility, and out of that, Rs. 20,000 crore is for the NPAs. Cashew industries in Kerala are in distress and they are generating NPAs. So, I would like to appeal to the hon. Finance Minister that the cashew industries are taken into consideration for their revival. …(*Interruptions*).

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Now, Mr. Bhagwant Mann.

… (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am just concluding. The GST compensation to the State of Kerala was Rs. 7,000 crore upto July. That may kindly be given.

With these words, I conclude my speech.

(ends)

2137 बजे

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है और मेरी पार्टी को समय भी कम मिलता है। चूंकि बहुत बड़े-बड़े भाषण हो चुके हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। मैं गागर में सागर बंद करना चाहूंगा। मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा, उनमें सब कुछ है। मुझे उम्मीद है कि आपको बैल बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर कृपया ध्यान से सुन लिया जाए।

देश की जीडीपी माइनस है, सरकार हर मुद्दे साइलेंस है,
आज-कल करते नहीं हैं, वह काले धन की बात,
जनता की सुनते नहीं है, सिर्फ करते हैं अपने मन की बात,
जिसको सुन-सुनकर अब तो दुखी आकाशवाणी रेडियो के माइक हो गए,
लेकिन सरकार जी एक बात आपको माननी पड़ेगी कि,
इस बार आप सोशल मीडिया पर लाइक से ज्यादा डिसलाइक हो गए,
देश के बेरोजगारो पकौड़े तलो और भारतीय नस्ल के कुत्ते पालो,
सरकार जी अपनी हर योजना की नाकामी को कोविड के कंधे पर डालो,
न तालियों से, न थालियों से कोरोना गया,
न टॉर्च और मोमबत्ती की दिवालियों से कोरोना गया,
हां, इस बात से आप गोदी मीडिया के तो नायक हो गए,
लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि
आप लाइक से ज्यादा डिसलाइक हो गए,
लोग कह रहे हैं कि चाइना की तरफ से आने वाली
असली गोलियों को रोकने का प्रबंध करो,
सरकार कह रही है कि पहले नकली गोलियों वाली पबजी बंद करो,
हमारा चाइना के सामान के साथ तो धार्मिक नाता है,
क्योंकि रावण, मेघनाथ और कुम्भकरण का पुतला भी तो वहीं से बनकर आता है।

(इति)

2139 बजे

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात यहां रख रहा हूं। महाराष्ट्र राज्य सबसे ज्यादा कोविड -19 से प्रभावित है। महाराष्ट्र में 1 सितम्बर से केन्द्र सरकार द्वारा मेडिकल फैसिलिटी बंद कर दी गई है। जबकि महाराष्ट्र सरकार का लगभग 29 हजार करोड़ रुपये जीएसटी एवं अन्य टैक्स से केन्द्र सरकार से आना बाकी है। मैं महाराष्ट्र को सहयोग करने की मांग करता हूं।

मेरी दूसरी बात यह है कि जो एमपीलैड्स फंड बंद किया गया है, मैं एमपीलैड्स फंड चालू करने की मांग करता हूं। कोविड -19 से सभी राज्य प्रभावित हैं।

(2140/MM/RU)

आखिर में, मैं बोलना चाहता हूं कि एयरपोर्ट, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, रेलवे, पोर्ट, एलआईसी और ऑयल कम्पनीज़ का हिस्सा केन्द्र सरकार बेच रही है। सरकार के आने से पहले एक घोषणा की गयी थी- "न बेचूंगा, न बेचने दूंगा।" अब आप सब बेच रहे हैं। सरकार के द्वारा राज्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

(इति)

(pp. 342-A)

2140 Hrs.

*SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): Hon. Speaker sir, thank you for allowing me to speak on the discussion on Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021.The hon. Finance Minister has presented the Supplementary Demands for Grants to take the approval of Parliament which is to the tune of Rs. 2.36 lakh crore.

Sir, I would like to say that the Central Government has completely failed to sustain the economy of the country. The States are made to suffer the huge burden of debt due to wrong policies of the Government. COVID-19 pandemic, flood and droughts, all these have pushed the States into great financial crisis. Under these circumstances, yesterday, the Union Government has passed two bills which are not at all beneficial to the people or the farmers of the country.

Under Atmanirbhar Bharat Abhiyan, the Union Government assured that Rs. 5 lakh crore will be allocated for the welfare of farmers and also for the development of agriculture sector. However, it is not true as the Government has taken into consideration of the loans availed by farmers from the cooperative banks and societies much before this announcement of Atmanirbhar Bhartat Abhiyan Yojana. In this way, the Union Government is misleading the people of the country by giving wrong information.

Sir, as ours is an agriculture dominant country, the farmers need financial support for taking up farming every now and then. To meet this demand, they used to take crop loan from nationalised banks by pledging their gold jewels. In turn they were getting Interest subsidy under the Interest Subvention scheme for the said loan. However, the Union Government has deprived farmers of this facility as the nationalized banks are denying the crop loan after pledging of gold by farmers. I want the reply for this from the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister.

Another example of how the Union Government is doing injustice to the people of the country is that it has imposed cess of around Rs.10 to Rs.12 on petrol and diesel overnight. This is nothing but exploiting the people of the country who have been suffering from COVID-19 lockdown and other natural disasters.

Sir, we are all aware that in the previous year the GDP of the country has gone down by 3.1 %, it was much below than the projected estimate for the last year. This year again the GDP has gone down to -23%. So, there is no point in appreciating the hon'ble Prime Minister for this dismal achievement.

It is only showing that how the government has failed in managing the economy of the country.

---

*Original in Kannada.

(pp. 342-B)

The Union Government has announced that they would give special package for the farmers through co-operative bank but they are not giving anything. Instead the government is taking all the steps which would badly affect the cooperative federalism of the country by taking away the constitutionally guaranteed rights of the State Governments. During the imposition of lockdown in India, all the labourers and daily wagers from urban areas have returned to their native villages. Indeed, it has helped the agriculture sector to see progress as sufficient number of labourers were available for taking up agriculture and allied activities. As a result of increased farm activities, there is more demand for fertilizers, pesticides, quality seeds and other inputs in large scale. However, the Government is not paying attention to provide all these inputs. That is the reason why there is a huge shortage of fertilizers and other inputs in the country. Farmers are forced to pay more money to buy the inputs as there is rampant black marketing of chemical fertilizers in the country. So, this is causing severe burden to the farmers.

Another failure of the government is relating to the privatization of Railways, LIC, Aviation sector etc., this step is being taken by the Government at a time when the country is facing suffering from COVID-19 pandemic crisis. On the other hand, it is not taking steps to create job opportunities for the youth.

The hon. Prime Minster promised that he would create two crore jobs for the youth of the country but now there is no job creation. Instead, the jobs are being taken away from the Government by pushing the public sector undertaking into the hands of private investors. In the wake of COVID-19 lockdown the unemployment rate has gone up to an all time high. The Government has not paid unemployment allowance to youths. Under these circumstances, privatizing Public Sector Undertakings is not good for the country.

I urge upon the Union Government to release more funds to the State of Karnataka which is badly affected due to floods. The State sought for Rs.4000 crores financial assistance for taking up the flood relief activities. However, the Union Government has given only Rs. 300 crore to Karnataka.

Also, the union government has not paid the State of Karnataka its due in the Central share as recommended by the Finance Commission.

So, I request the Union Government and the hon. Finance Minister to look into this and release, at least, fifteen thousand crore rupees immediately for flood relief activities and also to clear all the dues including the Central share to the State of Karnataka.

I would also like to request the Government to increase the number of days to 200 in the MGNREG Scheme. So, it would be beneficial for the poor people, who could not get any employment during the lockdown imposed in the wake of Covid-19 pandemic. With these few words, I conclude my speech. Thank you, Sir.

(ends)

2143 बजे

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंटरी डिमांड्स फोर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, मैं दो-तीन बातें आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं। कल के ही मेरे सवाल के जवाब में माइनोरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने जवाब दिया है। उसमें जो ग्रांट्स उत्तर प्रदेश को जाती है, वह पिछले पांच साल में 50 प्रतिशत घट गयी है और यूपी गवर्नमेंट का पिछले साल का यूटिलाइजेशन सिर्फ 9.9 परसेंट है। क्या इस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनेगा?

मेरा दूसरा सवाल माननीय वित्त मंत्री जी है, राजेन्द्र अग्रवाल जी यहां बैठे हैं, हम दोनों दिशा की बैठक में साथ थे। एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कीम्स में एक भी पैसा किसी स्कीम में यूपी गवर्नमेंट को एलोकेट नहीं हुआ है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया इस बार 100 वर्ष पूरे कर रहा है। आजादी के आंदोलन से उपजा हुआ वह विश्वविद्यालय है। मेरी आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से डिमांड है कि वर्ष 2015 में इसी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था।

(2145/NKL/SJN)

इस देश में यह रिवायत रही है कि जब कोई विश्वविद्यालय 100 वर्ष पूरा करता है, तो उसको 100 करोड़ रुपये की स्पेशल ग्रांट्स दी जाती है। वर्ष 2015 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को दी गई थी। मेरी यह डिमांड है कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को भी, जिसने इस बार एमएचआरडी की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है, उसको 100 करोड़ रुपये की स्पेशल ग्रांट्स दी जाए।

महोदय, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां पर 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' की जो घोषणा हो रही है, मेरे जिले में पहली इन्स्टॉलमेंट 1,85,000 किसानों को मिली है। लेकिन वह घटते-घटते जो आखिरी और छठी इन्स्टॉलमेंट मिली है, वह केवल 47,000 किसानों को ही मिली है। यह सरकार कहीं न कहीं किसानों को…(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) बनाने का काम कर रही है।

सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से यही गुजारिश है कि जो कोरोना का संकट आया है, मेरे अमरोहा क्षेत्र में जो कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें हजारों-लाखों गरीब काम करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी मिलती थी, इस कोरोना काल में बिजली की सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनको उनका हक दिया जाए, तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। जब किसान और मजदूर आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी भारत आत्मनिर्भर बन सकता है।

(इति)

…(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में रिज़र्वेशन भी मिलना चाहिए।…(व्यवधान) आपको इसकी भी मांग रखनी

चाहिए।...(व्यवधान) आपको यह भी मांग रखनी चाहिए थी कि...(व्यवधान) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया विश्वविद्यालय में रिज़र्वेशन मिलना चाहिए।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Bidhuri*ji,* please sit down. The hon. Minister is going to reply.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Bidhuri*ji,* please sit down. The time is limited. Nothing is going on record except the statement of hon. Finance Minister.

…(Interruptions) …(Not recorded)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record. Only the Finance Minister's Statement is going on record.

…(Interruptions) …(Not recorded)

HON. CHAIRPERSON: Danish Ali*ji,* please sit down.

…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Ramesh*ji,* nothing is going on record except the hon. Finance Minister's speech.

…(Interruptions) …(Not recorded)

HON. CHAIRPERSON: Mann*ji,* please sit down. Nothing is going on record except the hon. Finance Minister's reply.

…(Interruptions) …(Not recorded)

HON. CHAIRPERSON: Bidhuri*ji,* please maintain silence.

…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Everything is over now. Danish Ali*ji,* you are a senior Member; please sit down.

…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down, and maintain silence. Bidhuri*ji,* please maintain silence. The hon. Finance Minister is replying.

…(Interruptions)

(FOR REST OF THE PROCEEDINGS,
PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)

*DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Speaker, Sir, the Finance Ministry had issued an order in the first week of June that no new scheme/sub-scheme, whether under delegate power of administrative Ministry including SFC proposals or through EFC, should be initiated this year (2020-21) except the proposal announced under Pradhan Mantri Garib Kalyan Package, Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan Package and any other special package announced.

This means, the initiation of new schemes already appraised/approved will remain suspended for one year till March 31, 2021 or till further orders, whichever is earlier. This is applicable for those schemes as well for which in-principle approval has already been given by the Department of Expenditure. Approval of the Parliament is sought to authorise the First Batch of Supplementary Demands for Grants for 2020-21 under the extraordinary circumstances due to COVID-19 crisis.

The total allocation of SDRMF (2020-21) in Tami Nadu is Rs.1,360 crore of which Rs.1,020 crore is the Central share and Rs.340 crore is State share. Tamil Nadu, being one of the most vulnerable States in the country, requires more funds from the Centre. But the Centre had not released amount under certain Centrally sponsored schemes for which the Government of Tamil Nadu had already spent. This will create a big hole in Tamil Nadu Budget in the coming year.

The Union Government has yet to release an amount of Rs.17,000 crore to Tamil Nadu as part of its share for Centrally sponsored schemes or towards reimbursing the money spent by the Government of Tamil Nadu. Tami Nadu is yet to get post/pre-matric scholarship funds of Rs.1500 crores meant for SC/ST students. Similarly, in School Education Department, Rs.1200 crore is yet to released.

Under the Swachh Bharat Mission (Gramin), an amount of Rs.600 crores, is still pending from the Central Government. A total amount of about Rs.1500 crores is yet to be released under the revised restructured Technology Upgradation Funds Scheme (TUFS) to entrepreneurs in Tamil Nadu.

----

*Laid on the Table

Sir, it is either due to the lackadaisical approach of the Government of Tamil Nadu and indifferent approach of the Union Government or by both. But we cannot just play like that with lives of the people, poor and downtrodden, SC/ST students, farmers and fisher folks, textile workers and MSME people. People of Tamil Nadu deserve better.

Sir, any delay in the release of funds sanctioned will not only affect the proper implementation of Centrally sponsored schemes but adversely affect the socio-economic and educational status of the beneficiaries. Therefore, I urge upon the Union Government to expedite the release of Rs.17,000 crores dues to Tamil Nadu and to avoid any such shortfalls in the approved Central share release in future.

Lots of efforts have to be taken under Chennai Rivers Restoration Trust (CRRT) to reduce the sewage let into the rivers and other water bodies of Chennai mega city. Creation and restoration of water bodies in Chennai and adjoining areas at the cost of Rs.500 crores and restoration of Chennai waterways at the cost of Rs.10,000 crores are the need of the hour.

The Cooum river restoration project had to be implemented at a total cost of Rs.3,833.62 crore in five years with Chennai River Restoration Trust as the nodal agency. But nothing has been done concretely so far to implement such an important programme. Apart from the Adyar River Eco-Restoration Project, Rs.150 crore was allocated out of the Environment Protection and Renewable Energy Fund to restore lake, water bodies in Chennai and other Cities, including Rs.42 crore for restoration of Chetpet Lake.

The Remediation/closure of Perungudi/kodungaiyur dump yards at the cost of Rs. 150 crores and Greenfield Regional Landfill and waste Processing Facility at the cost of Rs. 150 crores and an integrated waste collection and Transfer at the cost of Rs. 200 crores.

The 100 per cent sanitized and open defecation free city project at the cost of Rs.300 crores and Slum-free city program at the cost of Rs. 25000 crores include 100 per cent sewerage coverage program at the cost of Rs. 7000 crores.

The Department of Fisheries in Tamil Nadu has pioneered many fishery development activities in India. The Union Government has promised to form a separate Ministry to develop and conserve the fisheries' resources and to ameliorate the socio-economic status of the fishermen community.

The allocation made for important Central schemes like Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT), Smart Cities Mission, (iii) Pradhan Mantri Awas Yojana Urban (PMAY-U), (iv) Swachh Bharat Mission Urban (SBM-U), and Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM) is inadequate and insufficient to execute the ambitious targets set by the sloganeering Government.

Sir, under AMRUT Scheme, the Centre has not allocated adequate funds except few crores and the Government of Tamil Nadu has not done any noticeable work under this Scheme. This is the sorry state of affairs of the implementation of this Scheme.

The Smart Cities Mission lags way behind both in allocation of funds and execution of works. Under this Scheme, Government of India have selected 11 cities in Tamil Nadu to be developed as Smart Cities which includes Chennai, Coimbatore, Madurai, Thanjavur, Salem, Vellore, Tiruppur, Thoothukudi, Tirunelveli, Tiruchirappalli and Erode.

Sir, due to the lack of coordination between the different corporations and Tamil Nadu Urban Finance and Infrastructure Development Corporation Ltd. (TUFIDCO) as well as due to the political interference, the smart cities project in Tamil Nadu is non-starter. There is an urgent need for proper devolution of funds from the Centre and allocation and proper utilisation of funds by the Government of Tamil Nadu. Otherwise, reaching the desired targets in Smart Cities Mission is a distant dream.

Out of 378 projects sanctioned at a cost of Rs.10,379.14 crore, 63 projects at a cost of Rs.248.09 crore have been completed, 199 projects at a cost of Rs.5,502.40 crore are under execution and the remaining projects are under various stages of implementation. I would like to place on record in this august House that under the Smart City Mission, all the 11 cities of Tamil Nadu are totally neglected.

PMAY-U is an Affordable Housing Scheme being implemented from 2015 to 2022. The budgetary allocation towards the scheme for 2020-21 is Rs. 8,000 crore. But till December 2019, 103 lakh houses have been approved. Of this, as per the Government's data only 31% houses have been constructed. That means, the implementation of this Scheme is going at snail's pace and the Governments both at the Centre and State are doing publicity gimmicks only.

The percentage of beneficiaries is very less and negligible compared to the Mission targets.

Sir, more than 35 per cent of Chennai population live in slums. Chennai metropolitan population has grown from 2.64 million in 1971 to 6.5 Million as of now. The expansion of Chennai Metropolitan Development Area (CMDA) from 1,189 square kilometres to 8,878 square kilometres has increased slum population eight-fold. Slums present the most unhygienic, ugliest, nauseating scene. During rainy season, the whole area gets flooded, the pathways become swampy and the entire colony becomes a fertile breeding place for mosquitoes, exposing the slum dwellers living in the area to all sorts of diseases. During summer, the thatched huts are prone to fire accidents. Thus, the slum dwellers' life is the most miserable one.

The major factor contributing the development of slums is the lack of employment in rural areas and rapid urbanisation. People migrate from their hometown to Chennai and get employed in different unorganised sectors.

The Government did not have any policy for the welfare of slum dwellers until our visionary leader, Dr. Kalaignar, empowered the government to protect the rights of slum dwellers from eviction or relocation in 1971. The policy helped in created Tamil Nadu Slum Clearance Board (TNSCB) in 1971.

The Tamil Nadu Town and Country Planning Act, 1971 mandates a review of the Master Plan in every five years. This was not taken up by the CMDA and the Tamil Nadu Government. The CMDA has forgotten to address the changes due to climate change, urbanisation, and Chennai's expansion. Most of the slums do not have drainage facilities and open toilets are widely used, resulting in spread of diseases. The slum dwellers of Chennai are the worst affected due to very heavy rains, frequent floods and cyclonic storms during monsoons.

Development for the urban poor is beyond the provision of social housing. It involves the improvement of people's capacities within the urban sphere. This requires around 1.5 lakh houses with all the associated infrastructure facilities for providing quality education to medical care to create Smart Slums in Chennai Metropolitan Area.

I, therefore, urge the Government to take appropriate steps to provide funds for the construction of 1.5 lakh houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana - Housing for All (Urban) and also initiate the Smart Slums Programme

under the Smart Cities Initiative in Chennai metropolitan area which cover my South Chennai constituency.

The much publicised and projected, Swachh Bharat Mission (SBM) to eliminate open defecation is also falling in gutters. The Government's proclamation of achieving 100 per cent scientific management of municipal solid waste in all 4,041 statutory towns by October 2, 2019 has gone in thin air.

In 2020-21, Rs. 2,300 crore has been allocated towards the Scheme. The total estimated cost of implementation of SBM-U is Rs. 62,009 crore but the results achieved so far do not justify both allocation and proclamation. I do not know whether the Government could continue this scheme considering the extraordinary situation due to COVID-19 as the country’s GDP witnessed an abysmal fall.

Sir, Chennai, a thriving metropolis, is also known for its diverse ecosystem. The Pallikaranai marshland covering a geographical area of 80 square kilometres is one of the most significant wetland ecosystems which play an important role in the natural drainage systems in South India. Unfortunately, mindless damages have been done to its environment, making its very existence uncertain in future. It is most unfortunate that the Government at the State is the biggest culprit in the last decade. The lack of scientific approach coupled with inept and corrupt state Government made the things bad to worse and the disaster is awaiting.

The marshland has come under serious threat due to the developmental programmes adopted by the Government. Major problem faced by the marsh is the dumping of municipal wastes. The Corporation of Chennai is dumping about 2,200 tonnes of garbage in landfills right over the marsh. Besides, due to a sewage treatment plant which is located in this region, 32 million litres of untreated sewage are being let into the marsh on a daily basis. This has done an irreparable damage to the Pallikaranai marsh, which is most vulnerable to encroachment and degradation.

“If you mess with nature, it messes with you”. This suits best for Pallikaranai marshland. At present, the Chromium content in the land and groundwater is hazardously high and the air quality is too deteriorated and it exceeds the healthy limits by manyfold.

Due to rapid urbanisation and industrialisation, Pallikaranai marshland was reduced to one-tenth of its original extent. The presence of a major dump-yard and sewage treatment plant operated in the ecologically sensitive areas of Pallikaranai marsh poses a great threat to the biodiversity of the wetland. If the landfills are closed and sewage treatment plants relocated, the damage can be curtailed. The Madras High Court, in one of its recent verdicts, has ruled for the protection and preservation of 1,716 acres of marshland.

As a first real effort to protect the wetlands, Dr. Kalaignar's Government declared 317 hectares (780 acres) of the marsh as a reserve forest on 9th April, 2007 (Gazette notification G.O.Ms.No.52, dated 9 April 2007) under the Forest (Conservation) Act of 1980 and brought under the jurisdiction of Tambaram range, a separate range in Chengalpattu Forest Division with headquarters at Pallikaranai.

The Government of Tamil Nadu, in its State Budget of 2019-20, has allocated Rs.165.68 crore for restoration of the Pallikaranai marshland. But none of the projects announced so far to protect PallikaranaI marsh lands have been property done.

Therefore, I urge the Union Government to initiate immediately a comprehensive biodiversity protection and conservation project under the National Wetland Conservation Programme to save the marshland of Paliikaranal.

Given the pace of urbanisation, large capital investments are needed for infrastructure projects which include support from Central and State Governments in the form of capital grants.

Sir, Tholkappia Poonga or Adyar Eco-Park in the Adyar estuary area of Chennai is the brain child of our mercurial leader, Dr. Kalaignar and Thalapathy M.K. Stalin. The remarkable Poonga which acts as the oxygen factory of Chennai, is located in my South Chennai constituency. The project envisages the restoration of vegetation of Adyar estuary and creek, and the beautification of 358 acres of land once discarded by the local people as city's sewage and effluence dumping ground.

The Eco Park was inaugurated on 22 January, 2011 by Dr. Kalaignar and named after the renowned Tamil scholar, Tholkappiar. 500 acres of undisturbed tropical dry evergreen forest remain in Tamil Nadu and the Eco Park, serves as

a significant conservation effort to bring this vegetation back to the Coromandel coast. But the present State Government has almost jeopardised the priority accorded to this very important eco restoration project in the heart of Chennai city. Though two-and-a-half years passed after the Government of Tamil Nadu announced Rs.555.46 crore for executing the third phase of Adyar river restoration project, the project is still very much wanting. Therefore, I urge the Union Government to provide necessary financial and technological support through the Central agencies and sanction Rs.500 crores for the development and expansion of Tholkappiar Poonga and to expedite the Adyar River Restoration Project.

In 2020-21, Rs.20,000 crore has been allocated towards metro projects. This is a 6 per cent increase over the revised estimates of 2019-20. As of December 20, 2018, there are 27 on-going metro rails that have been set up as a 50:50 joint venture between the Central Government and respective State Governments. These have a total approximate completion cost of Rs 3,36,954 crore.

The metropolitan Chennai has been growing rapidly and traffic volumes have increased greatly. To promote and ease public transport of various forms including metro rail and to ensure that the share of public transportation in Chennai city is substantially increased, top most priority was accorded by our beloved leader, Dr. Kalaignar during his golden reign.

A detailed feasibility report for the expansion of the Chennai Metro Rail Project Phase II along 3 corridors - North West to South East; West to East; and an orbital corridor for a length of 118.9 kms. at an estimated cost of Rs.69,180 crore is very important for the people of Chennai, particularly my South Chennai constituency which extends up to Sholinganallur and beyond.

Also, the integration of the Chennai Mass Rapid Transit System (MRTS), with the Chennai Metro Rail is desirable and would enable effective synergies between various modes of public transport and increase share of public transport.

I urge upon the Government to support the Phase II of the Metro Rail Project of Chennai and to ensure that all necessary clearances are provided expeditiously to fulfil the dream and aspirations of the people of Chennai to provide the much-needed fillip to the public transport system in the Chennai

metropolitan city. I urge the Union Government to expedite the Phase-II of Chennai Metro Rail Project.

The Chennai metropolitan city is bursting with almost one crore people and also has a huge floating population converging from all corners of Tamil Nadu, India and world over. Unfortunately, the capacity of the city roads to handle the surging population of people and vehicles continues to be same and awfully inadequate, resulting in frequent traffic snarls and blockades. The people of Chennai city are often marred with traffic congestion, aging and worn-out road infrastructure and pedestrian-vehicular conflicts.

South Chennai constituency is formed by a major part of Chennai metro city and is affected very badly due to frequent traffic snarls, road blocks due to pedestrian-vehicular conflicts occur at Virugambakkam, Valasaravakkam, Vadapalani, T.Nagar, Adayar, Velacherry, Tharamani, Thiruvanmiyur, Perungudi and Sholinganallur road junctions. Chennai city has become the worst affected city due to frequent road accidents and fatal deaths. The Government of Tamil Nadu is blind and crippled.

The Chennai metropolitan city desperately requires several new impetuses in urban road infrastructure to mitigate traffic hurls and pedestrian-vehicle conflicts in almost all the road junctions.

Sensing the need for a skywalk or Foot Over Bridge demand for the same was proposed by several civic organizations and NGOs. Two years over, nothing has happened in bringing the proposal into reality. Skywalks with escalators and travelators are the need of the hour and should be established under the Smart Cities Mission. However, it is learnt that no such efforts were taken under Smart Cities Mission so far.

The Chennai Metropolitan Development Authority is all set to draw up a Third Master Plan for the Chennai Metropolitan Area (CMA) whose size would increase seven-fold. In these circumstances, I urge the Union Government to take necessary steps to expedite the sanction and construction of skywalks, Foot Over Bridges with escalator and travelator facilities at all the vantage road junctions in my South Chennai Constituency. As a member of Parliament from Chennai South parliamentary constituency, I urge the Hon. Minister once again to expedite the second phase of Chennai Metro Rail Project. I would also request the Union Government to set up a vigilance inquiry by Central agencies to find out how much funds allocated through the various Central schemes were siphoned by the corrupt agencies in Tamil Nadu, like what has happened in the PM Kisan Samman Yojana recently. Thank You.

(ends)

*DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Hon. Speaker, Sir, though the Supplementary Demand for Grants is almost a ritual every year, the handling of the current year by the Government, especially, during the global pandemic of COVID-19 -- which has affected India more than most other countries -- leaves us wondering if things could not have been better handled by this Government.

The decision to cut the salaries of Members of Parliament is more symbolic than of actual value as it will yield only less than Rs. 500 crore. However, the decision to cut the MPLADS for two years is shocking as this is the peoples fund provided for by the Constitution of India, and depriving the people of their rightful funds is deplorable. This amounts to almost Rs. 10,000 crore. The decision to proceed with construction of the new Parliament building amounts to spending MPLADS for the Parliament building construction and not to combat the health and economic fallout of COVID-19. I would urge the Government not only to rescind the decision to deprive the people of MPLADS, but to enhance the amount from Rs. 5 crore to Rs. 10 crore.

Sir, the hon. Prime Minister of India has been elected with a huge mandate for the second consecutive term. Hundreds of lakhs of citizens have great expectations from him. The hon. PM, I am sure, has great love and affection for his citizens. However, we expect more from him -- as one of the most powerful leaders of the free world -- than to call for clapping hands, clanging utensils, lighting lamps, switching-off lights, which incidentally threw a huge spanner in the power distribution of this country and which had to be carefully handled by the Energy Ministry. We have enough and more Godmen, Saints, Priests and Imams, etc. for this kind of religious hopes.

With his reputation and clout with international leaders due to his excellent foreign policy, I would urge upon the hon. Prime Minister to drum-up support from leaders of friendly nations and move the United Nations to pass a resolution for a ‘No First Aggression Policy’ by all its member countries for a period of 3-5 years. This will enable all countries to stop Capital Expenditure on Defense and use this to combat the health and economic fallout of COVID-19.

* Laid on the Table

Sir, may I humbly submit that we will be able to generate more than Rs. 100,000 crore, which can be of great use during this period of crisis. Though the unplanned announcement of lockdown has led to a lot of hardships for migrant labourers, industries, huge fall in GDP, unemployment reaching record heights, which is bound to increase crime rates and that is already evident, closure of several MSMEs that were left in the lurch, and deprivation of States of their rightfully due GST payments under the guise of ‘Act of God’.

Sir, the announcement of the so-called ‘Financial Package’ by the hon. Finance Minister was a huge disappointment for every citizen of this country. I would urge upon the Government to kindly reconsider the decision on MPLADS as there are several other ways to generate funds. Even the idea of monetizing during this crisis would not be a bad one as suggested by several economists. I am hoping that this Government will do all in its capacity and not disappoint the citizens who have such great expectations. Thank you.

(ends)

*SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on `Supplementary Demands for Grants'. We have many pressing issues in my constituency which I would like to highlight.

Regarding railways, I would like to say that the Gunupur-Therubali railway project is in the backburner. Despite being approved in the budget of 2017-18, it is still not yet started. The Railway Minister has mentioned that the project would start if the State Government provides land free of cost and bear 50 per cent of the cost. In this regard, I met the Chief Minister of Odisha and the State government has agreed to provide land free of cost and bear 50 per cent of the project cost. I would request the Ministry of Railways to urgently take this project up with the State government and revive the project.

We would need a new day time train from Jeypore/Koraput to Bhubaneswar *via* Rayagada. The work towards the new approved Railway Division at Rayagada is also going very slow. I would request the Ministry of Railways to expedite the work. Jeypore-Malkangiri and Jeypore-Nabarangpur railway projects are also moving very slowly. I would request the Ministry to expedite the work and revert with updates in this regard.

Regarding National Highways, the stretch from Barigumma-Jeypore-Koraput-Sunki in NH-26 is in very bad shape. Even after raising the issue multiple times, not much progress is seen. I would request the Government to repair the stretch and approve four laning of NH-26, especially the stretch in the undivided Koraput district. On the construction of Road Over Bridge in Sindhiripur Ghat, Lamataput under CRF, I have requested the Central Government multiple times. I would request the Ministry of Road Transport & Highways to approve the Road Over Bridge. The bypass road at Jeypore and Koraput on NH-26 and bypass road at Rayagada on NH-326 would need to be expeditiously approved. This has been a long-term demand of the people of Rayagada and Koraput districts.

----

*Laid on the Table

Mobile connectivity is still not available in most of the areas in Koraput/Rayagada districts. There are 51 Gram Panchayats in Koraput district and 69 Gram Panchayats in Rayagada district, which have no network coverage, especially during lockdown online classes for tribal students of these districts is a dismal proposition. Hence, I would request the Ministry of Communications to kindly set up mobile towers of BSNl network in all the Gram Panchayats in Rayagada and Koraput districts where there is no network coverage. Also, I would like to urge you kindly to ensure 4G connectivity of BSNL in these areas.

The National Testing Agency has selected seven places as Entrance Test Centres for JEE, NEET in Odisha. For students of undivided Koraput district, a predominantly tribal area, the Centres are over 400-500 km. away and it is difficult to travel to take the Entrance Tests. Hence, I would urge the Ministry of Education to introduce additional JEE, NEET Entrance Test Centres at Jeypore and Rayagada to enable the students from undivided Koraput district to appear in the Entrance Tests without travelling 400-500 km. Also, the Kendriya Vidyalaya at Jeypore is progressing at a snail's pace. I would request the Ministry of Education to expedite construction/approval of Kendriya Vidyalaya at Jeypore. A lot of money has been sanctioned previously to the Central University of Odisha(CUO), Koraput but the same has been returned back. I would request for a one-time grant of Rs.500 crore for infrastructure development of CUO, Odisha.

The UDAN airport project at Jeypore has been pending for a long time. I would request the Ministry of Civil Aviation to expedite the airport strip at Jeypore by removing impediments. Advanced treatment is not available in undivided Koraput district. Serious patients who are in need of referral treatment have to travel 400-500 km. I would request the Government to set up Air Ambulance at Jeypore airport strip.

Regarding tourism, a proposal has already been sent to the Central Government to allocate Rs.220 crore in regard to Rayagada and Koraput districts towards developing rural and tribal circuits under Swadesh Darshan Scheme. I would request the Ministry of Tourism to approve the funds urgently.

Finally, under Phase III of the Centrally-sponsored scheme for setting up of medical colleges, I would urge you to kindly approve a Government Medical College at Rayagada. The people have been demanding for a long time for the same. The same is very much required as the district is a tribal-dominated district where there is problem of unavailability of medical infrastructure.

With these words, I conclude.

(ends)

*SHRI OM PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD):Hon'ble Speaker Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants 2020-21. Sir, when Hon'ble Prime Minister Narendra Modiji assumed his office, he attended the Inauguration Programme of Solapur-Aurangabad Highway and visited Tuljabhawani Shrine at Tuljapur. He announced this Solapur-Tuljapur-Osmanabad Rail Project in 2014. But unfortunately this project did not get sufficient funds. Lacs of devotees visit Tuljapur every year from every corner of India, and they have to suffer due to the non-availability of Rail Service. Hence, I would like to request you to make budget provisions for this railway project and it should be completed as early as possible to fulfill Hon'ble Prime Minister's assurance.

I represent Osamanabad district of Maharashtra which is a drought ridden region. Due to the non-availability of drinking water and irrigation facilities, farmers suicide cases are very high in this area. Hence I would like to request you to kindly complete Krishna-Marathwada Irrigation Project by declaring it a project of National importance.

Osmanabad district is at number 3 in the list of most backward districts. This district desperately needs a medical college as during this Corona pandemic, thousands of people have to lose their lives due to the non-availability of modern medical facilities. Kindly provide funds for medical college.

In my constituency Osmanabad, around 8 to 10 lac people have to migrate to earn their livelihood as there are no employment opportunities available there. Hence, I would like to request Union Government to develop industry in this region so that the unemployed youth could get employment.

There are very few branches of Nationlised Banks in my constituency and the serving branches have higher work load. Hence, I would like to request you to kindly open more branches in my constituency to enable direct benefits of Central Government Schemes. It could help in distributing loans to the needy and unemployed youth. It would also be beneficial for the growth of industry and trade in this region.

----

*Laid on the Table/Original in Marathi

Hon'ble Sir, people from this area are continuously demanding to run an inter-city train between Latur and Pune. Rack point facility is available at Osmanabad Railway Station but the supplementary facilities like shelter shed, floating facility are not available. People are also demanding a passenger / express train stoppages at Kalamb Road, Talwada and Dhoki railway station. Kindly provide these facilities urgently.

Union Government has announced that the income of farmers will be doubled by 2022. But to achieve this target the recommendations of Dr. Swaminathan Commission Report should be implemented. Only by implementing it, we can fulfill this assurance.

Lastly, I would like to request Union Government to increase the amount of grant given to the physically challenged persons. Currently the grant is meagre and therefore it should be increased to Rs. 5000 per month.

I request the Government to take necessary steps in this regard. Thank you.

(ends).

*DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): I would like to thank the hon. Speaker, Sir, for allowing me to speak on supplementary demands for grants 2020-21.

India is facing the most disastrous pandemic so far in the past few decades. COVID-19 pandemic has brought several challenges before the Government. It has affected each and every sector of the industry vis-à-vis the people belonging to different strata of the society.

To overcome these challenges, the Government of India has taken several steps like distribution of free foodgrains to poor and BPL card holders and giving money to the women who have opened Jan Dhan Yojana accounts. The biggest step of the Government is the announcement of Atmanirbhar Bharat, it will solve the problems of unemployment, economic upliftment of budding businesses and provide entrepreneurs an opportunity to give jobs to more people, especially to youngsters.

I am taking this opportunity to also raise the issues of my constituency Nandurbar which is a tribal area and an aspirational district. As a tribal district, almost 70 per cent of the population is tribal. There are many problems like lack of educational facilities, irrigation potential not being fully utilised, malnutrition, anaemia and lack of connectivity of road and internet etc.

With regards to education, the literacy rate of tribal area is less than national and State average. It needs to be given more focus so as to bring the tribal people in the mainstream. Eklavya Model Residential Schools need to be opened in every taluka which has more than 50 per cent tribal population. Also, after school education, vocational training of the tribal youth will provide them jobs so I request the Government to start CIPET college in Nandurbar district. I would like to thank the hon. PM Modi ji for fulfilling the promise of opening New Medical College in Nandurbar and sanctioning Rs. 195 crore for my constituency.

----

*Laid on the Table

With regards to irrigation, Nandurbar district is located on the banks of river Tapi and Narmada. The water available in and around the district needs to be utilised fully. The irrigation facilities should be provided to these tribal areas since the tribal people do not have funds to make private lift irrigation scheme and, therefore, they can do good farming and fulfil the dream of PM Modi ji.

With regards to doubling farmers' income, improving irrigation facilities by doing lift irrigation schemes from Tapi and Narmada river basins, the per capita of income of the tribal farmers will increase. Most of these tribal farmers are small and marginal, so these farmers will be benefited by the irrigation schemes. So, I demand that the irrigation facilities be made available to these small and marginal farmers belonging to tribal community. There is a lot of irrigation potential in Nandurbar constituency, only the full utilisation is required.

Regarding health and nutrition, while fighting COVID-19 pandemic, our district had some other issues also which were big challenges for our tribal area. We have been fighting anaemia in girls and women in our area. Malnutrition has been a long-standing challenge which our tribal people are facing. We are working in this sector for last ten years and I am happy to share that the cases of malnutrition amongst the new born and neo-natal have reduced.

With regards to road connectivity, the road connectivity has improved in last five years as PMGSY and National Highways were sanctioned by PM Modi ji and the Government of India. Some highways were declared by Shri Nitin Gadkari ji, the Union Minister of Road, Transport and Highways, Government of India. These are the Ankaleshwar-Burhanpur National Highway, Dhule-Dondaicha-Shahada-Dhadgoon-Molgi-Pimpalkhuta-Dediapada-Baroda National Highway, Shevali-Nandurbar-Taloda-Ankaleshwar National Highway, Visarwadi-Khetia National Highway.

I would like to draw your attention that out of the above mentioned National Highways, only one NH work has started i.e. Visarwadi-Khetia National Highway and in that too, the work sanctioned is only half of the length of the National Highway.

Therefore, I request you to kindly sanction funds for my national highways so that the connectivity of my constituency will increase. Also, the *padas* (hamlets) of tribal area are still not connected which need to be connected. I request the Government to provide funds either under PMGSY or Tribal Department Funds to increase the connectivity of my district.

(ends)

(1020/KMR)

*SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Hon. Speaker, Sir, *Vanakkam!* Thank you for giving me opportunity to participate in the discussion on the Supplementary Demands for Grants 2020-21.

The very infamous economic stimulus package announced by our Prime Minister mentioned that 10 per cent of the GDP will go towards reviving the economy. But the devil in the detail is that only one per cent of fiscal stimulus was given and everything else was the money that the Government owed people, for example, the dues owed to the MSMEs.

Global crude oil prices have gone down drastically but the price of petroleum products has increased even in a scenario where purchasing power of people is low. Why has this benefit of lower prices at global level not translated to the citizens? Where has this money gone?

PSUs are bleeding, they have been forced to give money to PM-CARES Fund details of which the Government refuses to make public. PSUs are already in bad shape and yet they are being subjected to more financial distress.

GST dues to States are pending. As mentioned by hon. Finance Minister today, our current Prime Minister, who has also been a Chief Minister for 12 years, knows the importance of State revenues. Then, does he not know that in a crisis situation like this the primary responsibility of the Government is to pay its dues to the States so that they can tackle the problems. When asked for a solution, the Union Government directed the States instead of addressing their incompetency in financial management.

The condition of economy is at its worst. Unemployment rate is at an all-time high. GDP is in shambles. Amidst this, sanctioning a project to spend Rs.20,000 crore to construct a new Parliament building is senseless.

There is no development whatsoever in agricultural, railways, airways, education, health and many more sectors. No spending towards improving the condition of the suppressed sections of the society like women, SC/ST, the disabled, the transgenders and others. Farmers are protesting across the country. Crime rate amongst women has also spiked.

----

*Laid on the Table

Demand for work under MGNREGA has increased by 21 per cent in the month of June. However, the number of persondays provided in June was 32 per cent lower than what was given in May. MGNREGA has clearly emerged as a safety net for migrant workers during COVID-19 pandemic. If the Government really wants to improve unemployment status and condition of migrant workers of the country, they should use the opportunity under MNREGA and increase the daily wages provided.

Agriculture is the largest employing sector in India. That is also the section that gets affected the most in a crisis situation like the one we are in now. Especially, currently when the farmers are protesting against the three farm sector Bills, the Government should think hard about destressing their situation. The Government should consider waiving off interest on loans and instigating jewel loans. Consider offering zero per cent interest loans to farmers.

MSME sector is the backbone of economy in a country like this. With forced lockdown, they were affected the worst. Reforms like restructuring the loans are just a drop in an ocean. My constituency Karur is surviving on textiles, bus body building and mosquito net industries. The Government needs to impart more money towards revival of the sector.

Reduction in corporate tax has borne no results and is today costing us a huge loss. The one significant area of revenue for Government was reduced by the Modi Government. This Government is clearly favouring corporates by the way of their 'free market' policies and relaxation on taxation. The money is going to electoral bonds which in turn is being fed to BJP.

In addition to be so poor in giving financial assistance to the States, the Union Government has the audacity to cut MPLADS fund completely handicapping MPs to do any betterment in their constituencies.

The mysterious PM-CARES fund is claimed to have collected Rs.127 crore but yet there is no significant economic package for the revival of the economy.

The pertinent question is, where is the money going? Why do MGNREGA workers have to wait for months together to get their pay? Why is there no visible improvement in the condition of people of this country? The only visible change is in BJP!

(ends)

*SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Respected hon. Speaker, Sir, I rise to lay on the Table of the House the Supplementary Demands for Grants for the year 2020-21.

Sir, most of these expenditures are part of COVID-19 relief and also the difficulties faced by the people due to COVID-19 pandemic and hence these demands are formalization of the process of incurring these expenses. Our Government has provided subsidy on LPG to the poor people under Garib Kalyan Yojana during lockdown period and has incurred an expenditure of Rs. 13,000 crore to meet the demands. To meet the difficulties arising out of COVID-19 pandemic, Rs. 500 were given to the poor women in the rural areas.

As part of Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, Rs. 33,771.48 crore have been transferred to beneficiaries of both women Jan Dhan Account holders and Old Age Pension holders; Rs. 30,956.98 crore for providing Grants-in-Aid General for Direct Benefit Transfer to Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana; Rs. 30,956.98 crore for Women Accounts Holders; and Rs. 2,814.50 crore for Indira Gandhi National Old Age Pension.

Sir, in this Session we are discussing 54 Grants and 1 Appropriation. The Parliament approval is sought for gross additional expenditure of Rs. 2,35,852.87 crore and net cash outgo aggregate to Rs. 1,66,983.91 crore. The Central government, as of now, plans to spend an additional amount of Rs. 2.35 lakh crore to meet its commitment towards Atmanirbhar Bharat package and Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, as well as additional allocation towards post-devolution revenue deficit grants to States and other COVID-19 relief measures. Out of the gross additional expenditure of Rs. 2.35 lakh crore, Rs. 1.67 lakh crore is the net cash outgo and Rs. 68,868 crore is matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries.

The Supplementary Demands for Grants also included a sum of Rs. 46,602.43 crore required for providing additional allocations under the Post-Devolution Revenue Deficit Grant (Rs. 44,340 crore) and Grants-in-Aid General for States Disaster Response Fund (Rs. 2,262.43 crore) as per the accepted recommendations for the 15th Finance Commission. Also, a big chunk of additional expenditure is coming for the MGNREGS.

----

*Laid on the Table

The Centre has sought Rs. 40,000 crore for providing grants for the creation of capital assets under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and for the transfer of funds to National Employment Guarantee Fund. Also, for providing Grants-in-Aid General for Direct Benefit Transfer to Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana women bank account holders, the Government has sought approval for an additional expenditure of Rs. 30,956.98 crore.

Our hon. Prime Minister, Narendra Modi is keen to provide thrust to good quality technical and higher education in the backward areas of the country and for this Teacher's Education Quality Improvement Project is proposed for Rs. 20 crore. For recapitalization of Public Sector Banks, the Government proposed Rs. 20,000 crore and to uplift the Pradhan Mantri Mudra Yojana, our Government proposed Rs. 1,232 crore for providing 2 per cent interest subvention in Shishu Loans under the Pradhan Mantri Mudra Yojana.

Also, our Government is keen to make better position of Soil Health Management for which Centre has proposed Rs. 28 crore. In the sector of Oilseeds and Oil Palm Production under the National Food Security Mission, our Government has proposed Rs. 18 crore.

The initiatives taken by our Government to meet the demands arising due to COVID-19 pandemic and also other important expenditure in the Supplementary Demands for Grants for the year 2020-21 is very praiseworthy. I am, therefore, fully agreed and satisfied with the Supplementary Demands for Grants 2020-21 of the Government and I hereby support the bill.

(ends)

***श्री मलूक नागर (बिजनौर):** महोदय, सप्लिमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की मांगों पर बोलने का मौका नही मिलने की वजह से मैं लिख कर दे रहा हूं। आज महामारी के समय में पूरा देश तनाव से ग्रस्त है। कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है। ऐसे में देश के गरीब लोग, लेबर क्लास के लोग व किसान बहुत ही परेशान हैं। ऐसे में सरकार को भी रास्ता निकाल कर उनकी मदद करनी चाहिए।

वित्त मंत्रालय के विभाग I. T. A. T. Court में कुल 126 मैम्बर्स, (मा. जज साहब) चाहिए, लेकिन वहां 88 मैम्बर्स हैं। अगर उनकी संख्या पूरी कर दी जाए, तो सरकार को लाखों-करोड़ों रुपये आ सकते हैं। उन लाखों-करोड़ों रुपये से गरीब लोगों को अलग से पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। ठीक इसी तरह सरकार को किसानों की मदद (अनुदान) के लिए अलग से बजट (पैकेज डील), अनुदान की घोषणा करनी चाहिए। पूरे देश के किसानों को लॉकडाउन पीरियड के समय में हुए नुकसान, जैसे - खेतों में फसल सड़ गई, सब्जियां भी खेतों में सड़ गई, दूध की बिक्री न होने की वजह से, दूध भी घरों में ही खराब हो गयाा, की भरपाई की जानी चाहिए।

वित्त मंत्रालय के ही अधीन टी.डी.एस. टैक्स से संबंधित 'विवाद निवारक' से संबंधित कुछ अधिकारी के गलत तरीके, कुछ क्लॉजेज का अर्थ गलत (interpretation) करने की वजह से, व्यापारी बहुत परेशान हैं व इस वजह से सरकार के भी लाखों-करोड़ों रुपये खटाई में पड़े हैं। देश के करोड़ों बेरोजगारों को भी रोजगार दिया जाए। धन्यवाद।

(इति)

----

*Laid on the Table

2148 hours

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you very much, Sir. I am really indebted to yourself.…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. Nothing is going on record except the hon. Finance Minister’s speech.

…(Interruptions) …(Not recorded)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please seat down. Danish Ali*ji,* please take your seat.

…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please sit down. Please take your seat.

…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, now it is about 10 o’ clock; please cooperate with the Chair.

…(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Thank you very much, Sir. I thank all the 25 Members who have participated in the discussion. I am not reading the list as we are already close to 10 o’ clock but indeed, many Members have spoken on the actual Supplementary Demands for Grants. Although, of course, several of them had other concerns about the economy, but because it is already late, and I am sure, there are other finance related matters which will be coming in, so, I will get to talking about the other points which have been raised, during the debate. But considering that it has been a long sitting today, I will confine to some of the responses which are purely on the Supplementary Demands for Grants.

(2150/KSP/GG)

Sir, as has been rightly pointed out by several Members, particularly the first speaker from the Treasury Benches, this is probably the first time that this kind of a huge amount has ever been fixed in Supplementary Demands. The gross additional expenditure of Rs. 2,35,852 crore with a net cash outgo of Rs. 1,66,983 crore is probably one of the highest amounts that Budgets have seen in this country and this, obviously, has broad break-up of how much is the cash outgo, how much is the technical supplementary, and how much is the token supplementary. I am not getting into the details of what is the token supplementary, what is the technical supplementary etc.

2151 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

But I would like to highlight that particularly during these challenging times the additional resources, which are being placed in this First Batch of Supplementary Demands for Grants, are largely going towards people-centric activities so that monies can reach the people and they are also going to some of the most critical schemes of the Government.

I will just give a very important example here because people have been too generous to ask as to what is happening in MGNREGA? I want to highlight the fact now and, therefore, I would like to state that this cash outgo of Rs. 1,66,983 crore has a very big component of meeting the requirements, urgent needs, and priorities of post-devolution revenue deficit about which many Members spoke, SDRF which goes to States, Health, Food Subsidy, the Credit Guarantee Scheme and the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. So, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme has an additional demand of Rs. 40,000 crore. That is one of the main features of these Supplementary Demands. An amount of Rs. 40,000 crore is being additionally spent over and above what was earlier given at the time of presenting the Budget in February. In the Budget Speech I had mentioned that we would be spending Rs. 61,500 crore under MGNREGS. Now, with this addition of Rs. 40,000 crore, it touches Rs. 1,00,000 crore. So, through MGNREGA, highest amount is being spent and normally this is something which our opponents should also recognise. It is no good constantly reminding us, 'you are using MGNREGS now; you said it will not be there; *marega* MGNREGS' and all that.

But I want to highlight the fact that when there is an emergency situation like this, with effective DBT, टैक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डायरेक्टली जिन-जिन को काम दिलाना चाहिए, हम उनको काम दिलाते हैं, क्योंकि मनरेगा डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। उसमें जो मांगते हैं, उनके नाम कार्ड में से निकाल कर उनको देना पड़ता है और पैसा सीधा उनके अकाउंट में जा रहा है, इसीलिए मनरेगा लॉन्च करना एक बात है, मगर उसको इफेक्टिवली यूज़ करना अलग बात है। समय के अनुसार यूज़ करना और उसमें गलत कुछ न होना और जो पैसा मेहनत करने वाले, रोज़गार कमाने वाले के हाथ में जाना है, उनके हाथ में न जाते हुए, यूपीए के समय में, मैं जरूर पॉलिटिक्स में बात कर रही हूं, यूपीए के समय में गोस्ट अकाउंट्स में गया, जो नहीं थे, उनके नाम पर अकाउंट था, यह मैं नहीं कह रही हूँ, यह सीएजी की रिपोर्ट कह चुकी है। इसीलिए मनरेगा-मरेगा वगैरह हमारे ऊपर अभी आरोप लगाने वाले को मैं याद दिलाना चाह रही हूँ कि मनरेगा स्कीम उस

सरकार के समय सीएजी के पैराग्राफ के क्रिटिसिज़्म में आया और अभी क्या हो रहा है, मैं सिर्फ आंकड़ों के साथ बोलना चाह रही हूँ, यह मेरी अपनी इमैजिनेशन नहीं है।

(2155/KN/KKD)

वर्ष 2009-10 में सिर्फ दो नंबर, फिर एक्चुअल नम्बर्स पर जा रही हूँ। वर्ष 2009-10 में मनरेगा का बजट ऐस्टिमेट 39,100 करोड़ रुपये था। हमें यह याद रखना चाहिए कि उस समय भी 2008 में फाइनेंशियल क्राइसेस के बाद वर्ष 2009-10 और वर्ष 2010-11 बहुत ही स्ट्रेसफुल ईयर्स रहे। ग्रोथ के बारे में बोलने वाले को उस समय स्ट्रेस के बारे में भी बोलना चाहिए। 39,100 करोड़ रुपये बीई (बजट ऐस्टिमेट) था, वही एमाउंट रिवाइज्ड ऐस्टिमेट में भी था, मगर एक्चुअल उपयोग सिर्फ 33,539 करोड़ रुपये हुआ। एलोकेशन आरई, बीई में 39,000 करोड़ रुपये और एक्चुअल उपयोग 33,539 करोड़ रुपये हुआ। ऐसे आप 40,000 करोड़ रुपये बजट ऐस्टिमेट के समय एलोकेट कर रहे हैं, 35,000 करोड़ रुपये ही उपयोग होता है। वर्ष 2011-12 में दोबारा 40,000 करोड़ रुपये बजट ऐस्टिमेट के समय एलोकेट करते हैं, उसमें 29,215 करोड़ रुपये एक्चुअल उपयोग होता है। वर्ष 2012-13 में 33,000 करोड़ रुपये एलोकेट करते हैं, उसमें 30,000 करोड़ रुपये ही उपयोग होता है। ऐसा करके actual was so lower than the Budget Estimates. इनके समय पर मनरेगा का फरफॉर्मेंस रिकार्ड देखिए। ऐसे नम्बर्स में और सीएजी के द्वारा comments or criticism or ghost account के बारे में बोलने वाले के समय में मनरेगा का सोचिए और उससे बनाम अभी देख लीजिए। वर्ष 2014-15 में 34,000 बीई, मगर 33,000 एलोकेशन आरई में first year of this Government, 32,900 करोड़ रुपये ही उपयोग हुआ। उसके बाद से देख लीजिए। It was Rs. 34,699 crore in 2015-16, but the actual was Rs. 37,000 crore. वर्ष 2016-17 में देख लीजिए- 38,500 करोड़ रुपये बीई में, 48,215 करोड़ रुपये एक्चुअल में, वर्ष 2017-18 में देख लीजिए- 48,000 करोड़ रुपये बीई में बजट ऐस्टिमेट के समय, 55,166 करोड़ रुपये एक्चुअल में, वर्ष 2018-19 में देख लीजिए- 55,000 करोड़ रुपये बीई में, 61,815 एक्चुअल में, वर्ष 2019-20 में 60,000 बीई में, 71,027 करोड़ रुपये एक्चुअल में। So, BE and actual में इतना अंतर or, the actual was much, much more. And, this year, we have already, due to this Supplementary Demands for Grants, crossed Rs. 1 lakh crore.

सर, यह मनरेगा का विषय है। जब लाइवलीहुड की बात करते हैं तो रोजगार, जॉब क्रिएशन वगैरह और प्रधान मंत्री रोजगार योजना के ऊपर भी बहुत चर्चा हुई। मैं सीधे उसके आंकड़ों के साथ बोलना चाहती हूँ। I will come to that in a minute. मैं रोजगार के विषय में एक ही मिनट में बोल रही हूं। स्टेट को पैसा सही नहीं दे रहे हैं। स्टेट को जो पैसा जाना है, वह नहीं जा रहा है। मैं डेवोलूशन की बात कर रही हूँ; I am not talking about GST. मैं जीएसटी के विषय पर आती हूँ। About Centre’s Gross Tax Revenue, मैं दोबारा आंकड़ों के साथ बोलना चाहती हूँ। मैं वर्ष 2019-20 में अप्रैल टू जून की फिगर्स दे रही हूँ, पूरे साल का नहीं। वह 5,39,068 करोड़ रुपये था और इस साल वर्ष 2020-21 में अप्रैल टू जुलाई मतलब अभी जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई गए हैं, वह 3,80,000 करोड़ रुपये ही था, लॉकडाउन वगैरह के चलते।

(2200/RP/CS)

I am talking about Centre's gross tax revenue. इसमें से ही डिवोल्यूशन स्टेट्स को होता है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक मिनट रुकिए।

माननीय सदस्यगण, अगर सदन की अनुमति हो तो दोनों विधेयक पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य : जी हाँ, महोदय।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, समय तो बढ़ा दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : सर, ठीक है।

वर्ष 2019-2020 में अप्रैल-जुलाई 5 लाख 39 हजार करोड़ रुपये था, मगर उसी कालखंड में इस साल 2020-2021 में 3 लाख 80 हजार करोड़ रुपये ही था, that is the Centre's gross tax revenue. और जब पिछले साल का 5 लाख 39 हजार करोड़ रुपये था, the tax devolution was Rs. 1,99,000 crore. When our gross tax revenue collection has fallen by 29.51 per cent, Rs. 5,39,000 crore have has come down to Rs. 3,80,000 crore, which is a fall of Rs. 29.51 per cent; even then, the tax devolution to the States have happened without disruption and it is happening till now. I can tell you, we have devolved Rs. 1,76,009 crore, which is, actually, down by 11.96 per cent. हमारे रेवेन्यू में गिरावट माइनस 29, उसके तहत मैंने माइनस 29 कम नहीं किया, माइनस 11.96 ही किया है। In other words, last year, up to 49 per cent, in place of 41 per cent tax has been devolved without any disruption on the 20th of every month till today. I have not stopped any payment to any State. The devolution has happened and 49 per cent has been given to the States of the total gross that has been collected as opposed to what it was last year during the same period. Last year, it was only 41 per cent which was devolved between April and July. इस साल 49 परसेंट, मान लीजिए 50 परसेंट के नजदीक ही दे दिया, पूरा आधा समय पर दे दिया। Then, our revenues fell by 30 per cent but devolution fell only 12 per cent. That is the summary. तो राज्यों को नहीं दिया, सॉरी, यह ऑर्ग्युमेंट जमता नहीं है, यह गलत है।

The next point is about the total transfer to the States which is tax plus grants. हमने 19 फीसदी बढ़कर दिया है। I have given 19 per cent more this year. If we put together the tax and grants, it has been transferred to the States. So, there is a 19 per cent hike. यह सुनने लायक बात है। The total transfer to States exceeds Centre's gross tax revenue, it is at 107 per cent. मतलब मैंने 100 रुपया ग्रॉस टैक्स कलैक्ट किया है, मगर 107 रुपया राज्यों को दिया है। जितना कलैक्ट किया, उससे ज्यादा मैंने राज्यों को बंटवारा किया है। हम अपने पास जो पैसा अपने एक्सपेंडिचर के लिए रख रहे हैं, वह

पूरा का पूरा बॉरोड है। यही स्टोरी है। जितना सेंटर ने ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कलैक्ट किया, मान लीजिए वह 100 रुपया है, मैं राज्यों को 107 रुपया दे चुकी हूँ। इसमें 7 रुपया बॉरोड भी दे चुकी हूँ और अपने खर्च के लिए बॉरोड ही रख रही हूँ। यह सच्चाई है। राज्यों का कम नहीं किया है, जितना कलैक्ट हुआ, उतना ही दिया, उससे ज्यादा दिया है, हर सौ रुपये के लिए 7 रुपया ज्यादा दिया है। The Centre has, definitely, gone much beyond what it had in protecting the States' interests and their stakes. So, if you want to look at just grants, 61 per cent has already been given from what has been put in the Budget provisions, which means, I am frontloading expenditures on the grant. It is not happening gradually but it is spread over the years.

(2205/RV/RCP)

मैं फ्रंटलोड कर रही हूं। इसलिए स्टेट्स को कोई कमी नहीं होने दे रही हूं, चाहे हमारे पास कुछ भी हो। I would not mind repeating it. अगर हम 100 रुपये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं तो उस 100 रुपये में 7 रुपये जोड़ कर स्टेट्स को पूरे के पूरे दे चुकी हूं। मेरा खर्च ऋण लेकर चल रहा है। इसलिए स्टेट्स को कोई कमी नहीं होने दे रही हूं।

सर, हमारी इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं, इसके बारे में बहुत सारे मेम्बर्स ने सही कहा है। We have $ 537.5 billion forex reserves. Never ever before, we had this much of foreign exchange reserves. With $ 537.5 billion, crudely put, I can pay about 19 months of imports. That is the kind of money which we have. Our FDI inflows is $ 4.4. billion.

यह कहा जाता है कि हमारी इकोनॉमी इतनी गड़बड़ स्थिति में है, who is getting the money? Only some big people are getting it. It is not true. FDI is coming to this country. We are identifying good, listed companies, they are coming. It is coming to everybody and not just to the names you love to repeat.

सर, इकोनॉमी के इंटेरेस्टिंग डेटा को आम जनता भी समझ रही है। नॉर्मल समय में एक महीने में नए छ: लाख डी-मैट अकाउंट्स ओपेन होते हैं। इसका मतलब है कि retail people who want to invest in the stock market. अभी लॉकडाउन के दौरान छ: लाख नहीं, बल्कि 10 से 11 लाख नए डी-मैट अकाउंट्स ओपेन हुए हैं। ये रिटेल इंवेस्टर्स खुद म्युचुअल फण्ड्स के द्वारा न जाते हुए अपना खुद का अकाउंट ओपेन करके डायरेक्टली यह देख रहे हैं कि कौन-कौन सी लिस्टेड कंपनियां हैं, उनके डिस्क्लोजर्स सही हैं या नहीं, क्या वे साफ हैं या वेल-मैनेज्ड हैं? वे फिक्स्ड डिपॉज़िट में पैसे न रखते हुए, पोस्ट ऑफिस में सेविंग कम करते हुए आज डायरेक्टली रिस्क के साथ शेयर मार्केट में जाना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कम्प्लायंसेज अच्छी हैं। लोग भरोसे के साथ ऑपरेट करने को तैयार हैं। उसमें रिटर्न आ रही है, सही आ रही है। यह आम जनता कर रही है, not anybody else. पर, मिडिल क्लास की अपनी सोच है और इसके द्वारा हम समझ सकते हैं, यह मैं आपके सामने रखना चाह रही हूं। यह नहीं है कि वे एकदम संतुष्ट हैं, उनकी कुछ

डिमांड्स नहीं हैं। उनकी कुछ डिमांड्स शायद हो सकती हैं। उनमें से कुछ का जवाब देना आवश्यक है। But this is the fact which I have to place before you.

सर, माननीय रितेश जी ने कहा कि 500 रुपये प्रति महीने एक अकाउंट में भेजा जाता है, उससे क्या मिलता है? यह हर जन-धन अकाउंट्स को 500 रुपये प्रति महीना, तीन महीने के लिए दिए गए हैं। उन्हें फ्री राशन नवम्बर के अन्त तक मिलने वाला है। यह मिल रहा है। उन्हें हम कुकिंग गैस फ्री दे रहे हैं। आयुष्मान् भारत योजना के माध्यम से उनके हेल्थ केयर के लिए 5 लाख रुपये तक मिल रहे हैं।...(व्यवधान) ठीक है, यह बंगाल में नहीं मिलेगा क्योंकि स्टेट्स की च्वॉयसेज हैं। इसलिए एक अमाउंट को निकाल करके इससे क्या मिलेगा, ऐसा पूछने वाले को मैं जवाब देना चाहती हूं कि अगर जन-धन अकाउंट्स नहीं होते तो यह भी ट्रांसफर नहीं हो सकता था। एक रुपये में सोलह पैसे तक ही पहुंचता है, इसका रोना, I do not know how to say it, ऐसा हमने एक पूर्व प्रधान मंत्री जी से सुना था। आज हर एक रुपया पूरा हर बेनिफिशियरीज के अकाउंट में जाता है। केवल सोलह पैसे नहीं, बल्कि पूरे पैसे डी.बी.टी. के माध्यम से जाते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान विदेशों में एडवांस्ड इकोनॉमी में भी, how to reach cheques to these doorsteps, how can people be given money, इसमें वे बहुत ही प्रॉब्लम्स झेल रहे थे। मगर, भारत में जैसे ही प्रधान मंत्री जी ने 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना' को अनाउंस किया, बस 48 घंटे के भीतर पैसे उनके अकाउंट्स में गए। इस डी.बी.टी. की वजह से, बिना किसी कम्प्लेंट के, हो पाया है। मैं बार-बार यह भी बोलती हूं कि इसमें पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। बाद में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आए, मगर उनके बैंक मित्र के द्वारा गांव-गांव में गवर्नमेंट के पैसे पहुंचे हैं।

(2210/MY/SMN)

हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिस्टम में टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट को कितना प्रोत्साहन दिया है, यह उसी का ही फल है। यह उसका ही फल है कि आज गरीबों के हाथ में हमारी स्कीम के द्वारा समय से पैसा पहुँचना संभव हो रहा है।

सर, एन.के.प्रेमचन्द्रन जी ने पूछा कि 63 न्यू लाइन्स हैं, For which supplementary is being sought. इसके रेस्पॉन्स में मैं सिर्फ तीन-चार चीजों को हाइलाइट्स करना चाह रही हूँ। Some important things that I would like to highlight, मिडिल क्लास के बारे में बहुत सारे मेम्बर्स ने बात की है। अफॉर्डेबल और मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए हमने एक स्पेशल विंडो ओपेन की है। जिनको घर मिलना है, अफॉर्डेबल हाउसिंग मिलनी है, अगर उनके प्रोजेक्ट्स स्थगित हो गए हैं तो उनको पैसा देकर कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। That is a new line. उससे आपको कुछ भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अफॉर्डेबल हाउसिंग किनके हाथ में है, आज छोटे व मिडिल क्लास परिवार के हाथ में है। अगर उनका प्रोजेक्ट रुकावट में आ गया है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए सरकार को मदद करनी ही है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर लोग कोर्ट्स में घूम रहे थे। We have paid our rents. We are paying EMI to the bank for having taken home loans but होम नहीं मिला। अभी भी हम रेन्ट्ल हाउस में रह रहे हैं। उनके लिए हम स्पेशल विंडो ओपन कर रहे हैं। About Rs. 1366 crore. That is a new line.

Similarly, हमारे मंत्री गिरीराज जी इधर बैठे हैं। मत्स्य संपदा योजना, One of the major projects, फिशरमैन के लिए काम आएगी, गाँव-गाँव तक पहुँचेगी। उनके लिए एक स्पेशल विंडो ओपेन की है और इस साल के लिए तुरंत 500 करोड़ रुपये दे दिए गए हैं। But that is a major project in which we are going to reach probably upto Rs. 50,000 crore.

Similarly, health and family welfare के लिए एक नये विंडो के तहत 745 करोड़ रुपये सीजीएचएस और पेंशनर्स के लिए हैं। यह नया है और इसमें किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए। ऐसे ही स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स है। यह हर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा हम दे रहे हैं। यह भी नया विंडो है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का एक नया विंडो है, हम "उज्ज्वला योजना" के तहत जो फ्री एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं, उनके लिए 13,278 करोड़ रुपये हैं। इस लॉकडाउन के दौरान गरीब को घर में खाना पकाने के लिए हम उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। यह भी एक नयी लाइन है। इससे भी आपको कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

टेक्सटाइल्स के तहत प्रोक्योरमेन्ट्स ऑफ कॉटन कॉरपोरेशन के लिए 400 करोड़ रुपये हैं। मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। We have cleared all the VRS dues and therefore, that is also a new window. हम जितने भी नये प्रावधान दे रहे हैं, वे सब डायरेक्टिली इस कोविड के समय जनता तक पैसा पहुँचने के लिए है। इस प्रकार के हर एक उदाहरण में गरीब और मिडिल क्लास हैं।

सर, इसको और ज्यादा विस्तार से बताने के लिए मैं पेपर भी सबमिट कर रही हूँ।...(व्यवधान)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो): ममता दीदी ने बंगाल में डीबीटी नहीं होने दिया। उन्होंने इसका विरोध किया। इसे आप लोग याद रखिए।...(व्यवधान)

दादा, आयुष्मान भारत योजना थी, वहाँ लागू नहीं होने दी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी थी, वहाँ लागू नहीं होने दी, इसलिए 6000 रुपये नहीं मिले।...(व्यवधान)

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): सर, इस उज्ज्वला योजना के बारे में सिर्फ एक और स्टेटिस्टिक्स जोड़ना चाह रही हूँ। 8.3 करोड़ गरीब परिवारों को, One time cash transfer of thousand rupees और 8.3 करोड़ लोगों के लिए फ्री गैस सिलेंडर दिया गया। For three crore senior citizens, thousand rupees into their bank accounts as one time payment.

(2215/MMN/CP)

Then, I have already told you about the cash transfer of Rs.500 per month for three months. वह 20 करोड़ गरीब परिवारों को पहुंचा है, पर्टिकुलरली 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपये गए हैं। मनरेगा का डेटा मैंने दिया है। मंत्री तोमर जी भी इधर हैं।

The wage in MGNREGA was Rs.182 per day. It has been increased to Rs.202. Even that increases the budget but very rightly, this is done. So, hon. Speaker, Sir, I have responded to issues which have been largely raised.

जीएसटी कम्पंसैशन के ऊपर बहुत ही चर्चा हुई। मेरा यह कहना है कि एक्ट ऑफ गॉड को बार-बार सब याद कर रहे थे। I am very happy. लैटिन एक्सप्रेशन यूज करके एक्स्ट्रा आर्डिनरी सिचुएशन में कोर्ट में जाकर फोर्स मेजर बोलना सबको पसंद आता है। मगर एक घरेलू महिला जैसी वित्त मंत्री एक्ट ऑफ गॉड बोलती हैं, तो उसको व्यंग्य में, oh, she has told it is an act of God. सर, यह क्या तरीका है? *Force majeure* in the court from a client is very well but not an act of God because it is coming from a woman; it is coming from a Minister who looks very much like 'my neighbourhood aunty'. So, how can she ever say this? Sir, I like this condescension. If you can invoke *force majeure* in the courts and if internationally everybody is talking about the impact of a pandemic for which till today, we do not have a vaccine, to twist what I have said and to say, the Centre is reneging its responsibility, at best, आपकी अनुमति है तो एकदम irresponsible comment towards a responsible Government which is being led by Prime Minister Modi.

क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म के साथ सुझाव भी दे सकते हैं। मैं सुनने को तैयार हूं। मगर अगर व्यंग्य में, ओ! फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया कि एक्ट ऑफ गॉड, गलत है। Tell me one State Government which can tell me, no, this is all we can manage it; we will take care of it. फिर क्यों चर्चा हो रही है? माइनस 23 ग्रोथ सिर्फ भारत में ही नहीं, हर देश में इकोनॉमी कैसे उथल-पुथल है, हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है?...(व्यवधान) What is our population? What is our economy? ...(*Interruptions*) जीडीपी में ...(व्यवधान) अधीर भाई, सुन लीजिए।...(व्यवधान) Listen. You have spoken uninterrupted. It is time for you to kindly listen to me. Do not interrupt me, please.

सर, मैं कंट्री का नाम लेकर नहीं बोलना चाह रही हूं, सबको समझ में आएगा। उसने जीडीपी में 15 फीसदी तक स्टिमुलस उपयोग किया। तब सबने मुझे बोला, "Look at that country; they have spent 15 per cent of their GDP." What is your stimulus? उसी देश के वित्त मंत्री जी अब बोल रहे हैं कि हर आइटम के ऊपर मैं टैक्स बढ़ाना चाह रहा हूं। हम वह नहीं कर रहे हैं। We are not contemplating on taxation and increasing taxation to make up for what we have to pay. I proved here with data how much we have given to the States. 100 रुपये में 107 I am giving to the States, even if I am borrowing. स्टेट्स को जो पैसा देना है, उसको मैंने रोका नहीं है। इसीलिए to say as though we are reneging our responsibility गलत है। रेनेज नहीं है, एक्चुअली मैं पे करके दिखा रही हूं। इस महीने तक, अगर हर महीने की 20 तारीख तक टैक्सेशन का डिवोल्यूशन का पैसा नहीं गया, तो स्टेट उठकर बात करें। इसलिए प्लीज अफवाह न फैलायें, देश में आज कोविड की परिस्थिति है।

(2220/NK/VR)

इस देश में कोविड है, उसका अंत अभी तक हमें नहीं मिला है, वैक्सीन कब मिलेगी, हमें मालूम नहीं है। मैं नेशनल सिक्युरिटी के बारे में विस्तार से नहीं बोलना चाह रही हूं, लद्दाख को संभालना चाहिए कि नहीं? फिर भी स्टेट्स को मैंने कम नहीं किया। इस हाउस में हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूं कि हम इकोनॉमी के ऊपर प्रधानमंत्री जी खुद राज्यों के सीएम से बात करते हैं, इंडस्ट्री से कन्सलट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुद एक्सपर्ट्स को बुलाकर बात कर रहे हैं। हर ओपिनियन को सुन रहे हैं, ध्यान से चलने के लिए ही कर रहे हैं। इसीलिए इसमें जल्दबाजी से कमेंट न करें It is alright. क्योंकि महिला है, कमेंट करें या she does not possess the Harvard Degree. कमेंट करें, मुझे परवाह नहीं है, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं। इकोनॉमी के ऊपर इस हालात में सिनसियरिटी के साथ प्रधानमंत्री जी खुद इतना ध्यान देकर स्टेट को कम न करना, मैं डाटा के साथ बोल रही हूं। अगर आप में से किसी के पास डाटा है तो खड़े होकर मुझे कन्ट्राडिक्ट कीजिए।

आखिर में एक बात बोलना चाह रही हूं। वित्त मंत्री ने कम्पनसेशन सेस के संदर्भ में काउन्सिल में एक्ट ऑफ गॉड बोल दिया क्योंकि उनको कम्पनसेशन देने का मन नहीं है, यह गलत बात है। हम एक्ट ऑफ गॉड के सिचुऐशन में हैं। फिर भी केन्द्र सरकार जीएसटी काउन्सिल में खड़े होकर बात करके एक निर्णय करेंगे कि कैसे इस सिचुऐशन में कम्पनसेशन स्टेट को मिले।

मैं याद दिलाना चाहती हूं कि मेरे रिसपेक्टेड प्रेडिसेशर श्री अरूण जेटली जी जितना भी बोले, उसको बिल्कुल सम्मान के साथ मानूंगी। मगर यह नहीं है कि he said this way or that way, हरेक को अपना इंटरप्रिटेशन देना आवश्यक नहीं है। The GST Council in its wisdom has seen everything. The Council will take a call. इस गैप की भरपाई कैसी करनी है। कैसे बॉरो करना है। काउन्सिल के पास चर्चा हो चुकी है, हो रही है, होने वाली भी है। कैसे बॉरो करके देना है, काउन्सिल निर्णय करेगा। हमने जो ऑप्शन दिया है अगर वह मंजूर नहीं है तो फिर हम काउन्सिल में चर्चा करेंगे। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि सेंटर नहीं देने वाला है। सेंटर के देने की बात ही नहीं है। सेस के द्वारा जितना कम्पनसेशन कलैक्ट होता है, वह होता है कम्पनसेशन जिसे स्टेट को देना होता है, अगर सेस कलैक्शन में कुछ नहीं है तो नहीं है। कन्सोलिडेटेड फंड से पैसा देना, एजी का ओपिनियन आया है। कानून कन्सोलिडेटेड फंड से देने के लिए जीएसटी कानून में प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अभी खत्म भी नहीं किया, but everybody is reading my mind. मैंने सभी की बात पूरी सुनी। मैं जब बात करती हूं, प्रो. सौगत राय को जरूर सुनना चाहिए। You just cannot go on like that. इसलिए जीएसटी कम्पनसेशन के ऊपर बहुत ही एम्पॉवर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीएसटी काउन्सिल में सदस्य हैं, हर राज्य से हैं, उनके कहने में हमने जो ऑप्शन दिया, उसको लिखित रूप में देने के लिए बोले। 48 घंटे के अंदर हमने उनको लिखित रूप में भेजा है। सात फुल डेज का टाइम मांगा था, वह भी दिया, उससे ज्यादा भी दे रहे हैं। हम उनसे चर्चा और संपर्क में हैं। इसलिए किसी स्टेट के ओपिनियन को नकारने वाले रास्ते पर हम नहीं चल रहे हैं।

(2225/MK/SAN)

हम साथ बात करके साथ ही लेकर जाएंगे। इसका पूरा सॉल्यूशन काउंसिल में आएगा। यह मेरा स्ट्रांग ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। हम काउंसिल में तय करेंगे कि कैसे करना है। The Centre is not reneging, not at all thinking about it. People have put their words in my mouth saying: 'Is Centre reneging?'. Sir, I want to say here, through you, that the Centre is not reneging. जब मैं पूरे के पूरे ग्रॉस रेवेन्यू डिवॉल्व कर रही हूं, अगर सेस में कुछ होता तो वह आपको दे देते। अगर, सेस में नहीं है, फिर कानूनन जो होना चाहिए वह जीएसटी काउंसिल में होगा। वे जो भी तय करेंगे, वह हमें मंजूर होगा। So, Supplementary Demands for Grants के विषय में जहां तक जवाब देना था, probably I have responded. उसके अलावा जो भी विषय उठाया गया, उसका भी मैंने जवाब दिया है।

मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अपील करती हूं कि आप सप्लिमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट्स को पारित करें। आपने सुना कि मनरेगा सहित जनता के लिए जितने उपयोगी कार्यक्रम हैं, उनके लिए सब्स्टैंशियल एलोकेशन इसमें आ रही है। अभी तक विपक्ष के द्वारा हमें जो सुनाई दिया कि खर्च करो, खर्च करो तो खर्च के लिए पैसा है। आप इसको क्लियर कीजिए।

धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं 2020-2021 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें-पहला बैच सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाये गए मांग शीर्ष संख्या 1, 2, 4, 5, 7 से 9, 14 से 16, 18, 20, 23 से 27, 29, 32, 34, 39 से 44, 48, 51 से 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 70, 71, 73, 75, 76, 83 से 88, 92, 94, 95, 97, 98, 100 और 101 के संबंध में, 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: अब मैं 2016-2017 के लिए सिविल मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों की अतिरिक्त मांगें सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि सिविल मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्ष संख्या 13, 21 और 23 के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान हुए खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

(2230/YSH/RBN)

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक

2230 बजे

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 18, माननीय वित्त मंत्री जी।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2020-2021.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित कीजिए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर -19, माननीय वित्त मंत्री जी।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2020-2021, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 और 3

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

<u>खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

<u>अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक

2232 बजे

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 20, माननीय वित्त मंत्री जी।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2017, in excess of the amounts granted for those services and for that year.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित कीजिए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 21, माननीय वित्त मंत्री जी।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to provide for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2017, in excess of the amounts granted for those services and for that year, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 और 3

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

<u>खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

<u>अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

> "That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि विधेयक पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2020 को तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

2234 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 / 28 भाद्रपद, 1942 (शक) के पन्द्रह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>